12.32 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS.—*Contd.*

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION.—*Contd.*

MR. SPEAKER : The House will now take up further discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and cooperation. Shri Vyas may continue his speech.

श्री रमेश चन्द्र व्यास (भीलवाड़ा) : कल मैं बोल रहा था तो मैंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए कि भूमि का बंटवारा किस प्रकार इस देश में है। जो बड़-बड़े उद्योगपति हैं और बड़े-बड़े जो पैसे वाले है, वे फार्म खरीद रहे हैं और बड़े पैमाने पर खेती को बढ़ावा कर रखे हैं। यह ठीक है कि अन्न के स्वावलम्बन के मामले में हमें कुछ अरसे के लिए उससे राहत मिल जाये, लेकिन स्पीकर महोदय, इससे एक समस्या हमारे सामने बड़ी जबरदस्त खड़ी हो जायेगी और वह यह है कि जिनके पास छोटी-छोटी भूमि है और जो खेतहिर मजदूर हैं, वे शायद बेकार हो जायेंगे। आज जो कृषि मन्त्रालय और उसके अधिकारी रासायनिक खाद, हरी क्रान्ति करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, इस ओर जो श्रम कर रहे हैं और जिस तरह से वे एक अनाथ को, कमजोर अनाथ जनता को जिन को प्रोटीन नहीं मिलता है, उस तरह का अनाज देने की कोशिश कर रहे हैं उस बीज को कुछ गिने हुए लोगों के पास होर्डिंग हो जाए और जन साधारण के पास वह बीज यदि नहीं पहुँच सकेगा तो हमारी यह क्रान्ति है, यह जो हरी क्रान्ति है यह चन्द लोगों के पास रह जाएगी और इसका वह हाल कहीं न हो जाए, जो बंगाल में अंग्रेजों के जाने के कुछ समय पूर्व हुआ था, इस मुल्क में कितना अन्न था उसके बाद भी कई लोग भूखों मर गए, कहीं उसी स्थिति में हम न पहुँच जायें। हमारा खाद्य मंत्रालय कई बिदेशों की टैक्नीकल सहायता पर आधारित है। मैं कल जैसा कह रहा था कि कहीं हम विदेशी टैक्नीकल सहायता के बिलकुल आदी न हो जायें। ठीक है आज हम को, उपाध्यक्ष महोदय, जिस टैकनालाजी की जरूरत है उसको हम लें, सहयोग भी लें, लेकिन हमारे जो टैकनालाजिस्ट हैं, हमारे जो खेती के विशेषज्ञ प्रयत्न कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और जो तय कर रहे हैं और जो अनाज का बीज अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हम उपेक्षा न करें और कृषि मन्त्रालय कोई ऐसा माध्यम अपनाये कि उनकी शिकायतें दूर हो जायें।

12.34 hrs.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कितनी रियासतों से मिल कर बना है। वह सामन्तवादियों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों से आज भी घिरा हुआ है। इसलिए हम इलेक्शन में इन दोनों का मुकाबला करके बड़ी मुश्किल से पार हुए हैं। आज राजस्थान अकाल से, भयंकर अकाल से मुकाबला कर रहा है और उस मुकाबले के साथ-साथ उसने अकाल पर जितना खर्चा किया है, मैं समझता हूँ, वह खर्चा नहीं करता तो वह मवेशियों की जो राजस्थान में एक बहुत अच्छी नस्ल है और अच्छा दूध देने वाली नस्ल है, बचा न पाते। मनुष्यों को भी वे काम दे पाये हैं। राजस्थान के अलावा जो रजोरा बांध है उसको राजस्थान अपने खर्च से बनाने में असमर्थ है। इसलिए राजस्थान कैनाल को बनाने के लिए विशेष धन राज्य

[श्री रमेश चन्द्र व्यास]

सरकार को देना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बांध हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, उसका पानी राजस्थान में आयेगा। उसका 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के उस बांध से जो ग्राम डूबेंगे उन ग्राम निवासियों के लिए राजस्थान में भूमि भी निश्चित कर ली गई है। ऐसी हालत में अगर वह पानी नहीं पहुँचेगा और बांध जल्दी बन जायेगा तो उस बांध का क्या प्रयोजन होगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय जगजीवन राम जी, जो शायद यहां नहीं हैं, से कहना चाहता हूँ कि केन्द्र उस में अधिक से अधिक सहायता दे और बांध के बनने के पहले नहरों को पूरा करवाये ताकि राजस्थान हरा-भरा हो सके और राजस्थान कैनाल पूरी होगी तो मैं समझता हूँ कि सारे हिन्दुस्तान की अनाज की पूर्ति वहां से हो सकती है। राजस्थान का वह ऐसा भाग है, उपाध्यक्ष महोदय, जो वीरान पड़ा है, जहां आबादी नहीं है और जो अकाल से पीड़ित हैं।

मैं समाप्त करने से पहले राजस्थान में मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्हों ने इस अकाल का रात-दिन घूमकर मुकाबला किया और कर रहे हैं और इस के साथ साथ अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने अकाल राहत के लिये कुछ काम किये हैं, कुछ रुपया दिया है लेकिन वह काफ़ी नहीं है, वह और धन इसके लिये दे। यही कह कर मैं समाप्त करता हूं और जो टाईम आपने दिया है उस के लिये आप का आभारी हूं।

श्री ना. रा. पाटिल (भीर)**: उपाध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की संस्कृति सही अर्थों में कृषि संस्कृति है। कृषि क्षेत्र देश की अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। हमारी आबादी के अस्सी प्रतिशत लोग या तो खेती करते हैं या खेती पर निर्भर हैं। फिर भी अनाज की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये हमें दूसरे देशों का मुँह ताकना पड़ता है। यह अजीब बात है। स्वतंत्रता के बीस वर्ष बाद भी हम वैसे ही हैं। इस क्षेत्र में कुछ विशेष प्रगति नहीं कर पाये। हमारे साठ प्रतिशत किसानों के पास पांच एकड़ से भी कम (आधा एकड़ से पांच एकड़ तक) जमीन है। अत्यधिक गरीबी के कारण साधारण किसान अपने खेती के विकास हेतु पूंजी नहीं लगा पा रहा है। आज सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं किसानों की तरफ देने की आवश्यकता है।

हमारे देश में लगभग अस्सी प्रतिशत खेती पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं है। मुख्यतः यही एक प्रमुख कारण है कि हम खेती की उपज बढ़ाने में उतने सफल नही हुए जितने होना था। सरकार से अनुरोध है कि लाखों एकड़ की भूमि में तुरन्त सिंचाई की सुविधा करनी चाहिये। बावड़ियों और नलकूपों से सिंचाई की व्यवस्था प्रधान्य देना होगा जिस से कि तुरन्त फल मिल सके। हमारे योजना-कार्य क्रम को इस प्रकार का रूप देना चाहिये कि जिस से कुओं की सिंचाई और छोटी सिंचाई योजनाओं को प्रधान्य मिले। दुःख की बात हैं कि सरकार का इस ओर थोड़ा ध्यान इतने अर्से के बाद में गया है। सरकार इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और किसानों की वर्षा के ऊपर की निर्भरता कम करें। इस से किसान साल भर में एक से ज्यादा फसल उगा सकेगा जिस से उसकी आय बढ़ेगी। इस के परिणाम स्वरूप खेती पर निर्भर रहने वाले मज़दूरों को अधिक मज़दूरी मिलेगी जिससे उनकी भी समस्या कुछ हद तक सुलझेगी।

जैसा कि आप जानते हैं किसान मुख्यतः गरीबी में उलझा हुआ है। साठ प्रतिशत किसानों के पास पांच एकड़ से भी कम जमीन है। ऐसे किसान भला क्या अपने बिकास खेती के

*Hindi Translation of speech delivered in Marathi

लिए पूंजी लगा पायेंगे । सरकारी तकावी योजना तथा कोआपरेटिव बैंकों के बारे में यह देखा गया है कि वह मध्यम व उच्च श्रेणी के किसानों के ही काम आते हैं । सरकार छोटे किसानों की स्थिति सुधारने के लिये इन किसानों की तकावी तथा अन्य कृषि सम्बन्धी सुविधायें प्रधान्य रूप से दी जानी चाहिए । ज्यादा प्रयत्नशील होनी चाहिये । इन किसानों की आर्थिक स्थिति सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था द्वारा ही हो सकती है । ऐसे किसानों के पास पक्की बावड़ी का होना जरूरी है । सिंचाई की सुविधाएं उन्नत कृषि की पहली आवश्यकता है ।

छोटे किसानों की दूसरी मुख्य समस्या ऋण की है । प्रायः देखा गया है कि यहां भी छोटे किसानों की उपेक्षा होती है । यह शुभसूचक है कि व्यापारिक बैंकों ने कृषि क्षेत्र में धन लगाने की ओर ध्यान दिया है । मेरे ख्याल में ऋण का दुरुपयोग बचाने के लिये किसानों को जो ऋण दिया जाता है उसका कुछ अंश उन्नत बीज, खाद या पम्पिंग सैटस, कीटाणु नाशक दवायें, वगैरह इन चीजों में देना चाहिये— जिसके लिये कृषक ऋण चाहता है वह देना चाहिये । प्रायः गत कुछ वर्षों से भारत के किसी न किसी भाग में अवर्षण या अतिवृष्टि के कारण दुष्काल स्थिति पैदा हो जाती है । इस बात को ध्यान में रखते हुये कभी प्राकृतिक संकट या अन्य किसी कारण से यदि छोटे किसान बैंकों का ऋण चुकाने में असमर्थ हो जायं तो सरकार को चाहिये कि वह ऐसे किसानों का ऋण माफ कर के स्वयं बैंकों को रकम दे दें ताकि बैंको को नुकसान न उठाना पड़े । सरकार को इस बात की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऋण या उन्नत बीज किसानों को वक्त पर मिलना चाहिये नहीं तो वह निरर्थक जायेगा ।

आज किसानों की सहायता करने के लिए अनाज के भाव निश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है । वलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपने अहवाल में यह कहा था कि "किसानों को उनके परिश्रम का योग्य भी बदला देने की गारण्टी दी गई तो किसानों की खेती से अधिक उत्पादन निकालने की इच्छा और यह उत्पादन और बढ़ाने की जिद् पैदा होगी । अनाज के भाव एक बिशिष्ट मर्यादा से कम न होने की गारन्टी की भावना ही खेती की पैदावार बढ़ाने में उपयुक्त साबित होगी ।" किसान सारे साल सख्त मेहनत करके अनाज पैदा करता है उस अनाज का उसे योग्य भाव मिलना चाहिए । अगर यह नहीं मिला तो उस की साल भर की मेहनत बेकार जायेगी । सरकार कारखानों से निकले हुए माल का भाव निश्चित करने को तैयार हैं । लेकिन दुःख की बात है कि सरकार समाज के एक मुख्य अवयव "किसान" के माल के भाव निश्चित नहीं करती ।

किसान मण्डी में अपना माल ले जाने के बाद कटी हुई बेल की तरह एक ओर हो जाता है । फिर आढ़ती ओर खरीदार उस माल का इस प्रकार सौदा करते हैं जैसे किसी लावारिस माल को नीलाम कर रहे हैं । ऐसे वक्त किसान मजबूर होकर माल बेचता है क्योंकि उसे धन की आवश्यकता और माल वापिस ले जाने की कठिनाई रहती है ।

जिन क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार चीनी की मिलों के लिए की जाती है वहां गन्ने के भाव दिए जाते हैं याने कि सिर्फ विशिष्ट मर्यादा के बीच के खेतों के गन्ने के एक भाव और मर्यादा के बाहर वाले गन्ने का दूसरा भाव जो कि बहुत कम होता है । इस वजह से किसानों को बहुत नुकसान होता है । इसी प्रकार की समस्या अन्य अनाज की है । मिसाल के तौर पर सरकार को गुड़ के भाव भी निश्चित करना आवश्यक है । जितनी भी

कैश क्राप्स हैं उन सबके सरकार को भाव निश्चित करना चाहिए। (उदाहरणार्थ हल्दी, कपास, भुईमुग, तम्बाकू इत्यादि)। इनके भाव न बांधने के कारण मुनाफाखोर व्यापारी किसानों की बेवसी का फायदा उठाते हैं। गत वर्ष की अपेक्षा इस साल गुड़ के साव आधे हो गये थे इस वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इसी प्रकार प्याज के भाव की गिरावट के कारण किसानों को नुकसान हुआ। कपास महाराष्ट्र का एक मुख्य कैश क्राप है। सरकारी तौर पर भी कपास के भाव बांधने की जरूरत महसूस हुई है। सरकार से मांग है कि कपास के भाव जल्दी बांध दे और किसानों को मुनाफाखोर व्यापारियों से बचाये।

किसानों की समस्या पहले ही एक गम्भीर समस्या है। इस पर इस साल के वजट में जो कर वद्धि हुई है उसने तो कमाल कर दिया। खादों पर, पम्पिग सैट पर जो कर लागू किए गए हैं वह सर्वथा अनर्थकारक हैं। इस वजह से खेती के उत्पादन में बढ़ावा नही आ सकता उलटा यह हानिकारक सिद्ध होगा। वजट में किसानों पर जो सम्पत्ति कर लगाया है उसे रद्द कर दिया जाय। मैं जिस बीड जिले का प्रतिनिधि हूं वहां अनाज कपास तथा कुछ तालुके में गन्ने की अच्छी पैदावार होती है। लेकिन बीड के करीबन 65 मील क परिसर में यातायात का महत्वपूर्ण साधन रेल नहीं है। मैं यह मांग करता हूं कि जो नई रेल लाइन का निर्माण हो रहा है वह बीड मे लाया जाय। उसी प्रकार अम्बाजोगाई तथा आपटी तालुकों में गन्ने के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार चीनी कारखाने का निर्माण करें ऐसी सरकार से मेरी प्रार्थना है।

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सपकारिता मंत्रालय बहुत बड़ा है और उसके अन्तर्गत आने वाले विषय भी काफी महत्वपूर्ण व गम्भीर हैं लेकिन और विषयों को मैं इस समय नहीं लेना चाहता और मैं अपने को इस समय केवल शुगर इंडस्ट्री तक ही सीमित रखना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि चीनी की जो आज समस्या देश में है और आज की जो नीति हैं जिसको पार्शिल डिकंट्रोल कहते है यह एक नीति ऐसी है जिससे ऐसा लगता है कि जो उपभोक्ता हैं इस बीमारी से कभी उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आराम नहीं मिलने वाला है।

इसी प्रकार किसान जो चीनी के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं अर्थात गन्ना, तो उसका यह हाल है कि उसके उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इस हाऊस में माननीय खाद्य मंत्री ने यह घोषणा की कि वह इस बात का इंतजाम करेंगे कि कम से कम किसानों को 10 रु० फी क्विटल गन्ने का दाम मिलेगा लेकिन अनुभव यह बतलाता है कि आज वैस्ट यू० पी० में गन्ना साढ़े आठ रुपये पर क्विंटल मिल रहा है और यू० पी० के पूर्वी हिस्से और बिहार में वह करीब नौ और साढ़े नौ रुपये क्विंटल मिल रहा हैं। इधर इनकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो आऊट सैंटर्स हैं वहां जो गन्ना खरीदा जाता है तो उस गन्ने के भाड़े के निमित्त 32 पैसे क्विंटल यह देते हैं लेकिन फैक्टरीज वाले 50 पैसे लेते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। नीति घोषित कर देना इस सदन में काफी है या जो आप घोषणा करते हैं उसमें यह भी आप देखें कि उसकी पाबन्दी भी हो रही है या नहीं? मुझे ताज्जुब है कि सारे चीनी उद्योग का नियंत्रण यहां का खाद्य विभाग करता है लेकिन पिछले बर्ष जबकि चीनी में इतना मुनाफा हुआ केरल में 7 रुपये 37 पैसे प्रति क्विंटल गन्ने का दाम दिया।आज जब मद्रास में चीनी का भाव इतना ऊंचा है तब भी वहां 8 रु० क्विन्टल गन्ने का

दाम है। इसलिए या तो आप नियंत्रण करना छोड़ दें, और अगर नहीं, अगर आप नियन्त्रण रखना चाहते हैं तो आप को यह भी देखना चाहिए कि गन्ने का उचित मूल्य लोगों को मिले।

मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि आज से दो साल पहले 1966-67 में ऐसी स्थिति रही कि इस देश में 21 लाख टन चीनी पैदा हुई। इस का मुख्य कारण यह था कि गन्ने की सप्लाई फैक्ट्रियों में नहीं हुई क्योंकि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलता था। इसको जानने के बाद दूसरे वर्ष इस नीति में परिवर्तन हुआ और उसके अनुसार पार्शल डिकंट्रोल आया। आज से पिछली मर्तबा बोलते हुए मैंने विभिन्न प्रदेशों के आंकड़े दिए थे कि किस प्रदेश में उस नीति के अनुसार कितना गन्ने का दाम किसानों को मिला। लेकिन इस के बावजूद भी मैं देखता हूं कि सरकार कहती तो यह है कि हम धीरे-धीरे इस बात पर आ रहे हैं कि चीनी उद्योग को विनियन्त्रित कर दें, डिकंट्रोल कर दें, लेकिन जो वह काम कर रही है उससे वह दिनों दिन कन्ट्रोल के पक्ष में होती जा रही है। इस तरह कन्ट्रोल करने से कोई लाभ नहीं है। कंज्यूमर आज भी चीनी ले रहा है। बाजार से बाबूद इसके कि 70 फीसदी चीनी सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले रक्खी है और 30 फ़ीसदी को उसने छूट दी है। आज खुले बाजार में चीनी विकती है। पिछले बर्ष आप 60 फीसदी चीनी लेते थे और 40 फीसदी बाहर बाजार में आती थी अब आप कहते हैं कि आप इसको विनियन्त्रित करना चाहते हैं, डिकंट्रोल करना चाहते हैं, परन्तु इसके विपरीत आप ने 10 प्रतिशत अधिक नियन्त्रण में ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस रीति से जहाँ तक उपभोक्ता का प्रश्न है, उसको किस हद तक लाभ हुआ है ? आज भी कोई आदमी बाजार में 4 रु० से कम में चीनी नहीं पा सकता है, देहात की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इस लिए मैं कहता था कि पार्शल डिकंट्रोल की नीति निहायत गलत है और इस को रिवाइज करना चाहिए, इसके बारे में नई नीति निर्धारित करनी चाहिए।

आखिर जो कच्चा माल आता है, अर्थात गन्ना, वह कहां से आता है ? वह किसानों से आता है। आप या तो कम्प्लीट कन्ट्रोल कीजिए या फिर कम्प्लीट डिकन्ट्रोल कीजिए। लेकिन कम्प्लीट डिकंट्रोल में खतरा यह है कि बाद में जब दाम बढ़ेंगे तब आप फिर कन्ट्रोल करेंगे। इस लिए अच्छा यह है कि आप कंट्रोल रखिए, लेकिन कंट्रोल रखने के साथ साथ आप अनसर्टेंटी को दूर कीजिए। आज जब गन्ने की उपज ज्यादा होती है तब उस का दाम घट जाता है और जब गन्ने की उपज कम होती है तब उस का दाम बढ़ जाता है। इस देश में यह स्थिति है। यह किस प्रकार का नियन्त्रण है ? यदि आप मार्केट पर कन्ट्रोल रखना चाहते हैं तो आप के सामने यह आंकड़े भी होने चाहिए कि किस हद तक चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। आज मार्केट में जो रेट हैं आप उन को भी देखते हैं फिर भी कहते हैं कि स्थिति पर नियन्त्रण रखना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष जो आप की पालिसी है, बावजूद इसके कि आप ने घोषित किया कि आप 70 फीसदी चीनी नियन्त्रण में लेंगे, कितने उपभोक्ताओं को उस से राहत मिली ? यह भी सरकार कहती है कि किसानों को उचित मूल्य मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि किस हद तक उनको उचित मूल्य मिले ?

इस बात की मुझ को बड़ी खुशी है कि इस वक्त खाद्य विभाग नई मिले लगाने पर नियन्त्रण रख रहा है। कई सूबों की मांग है कि उनके यहां शुगर इन्डस्ट्री लगनी चाहिए। लेकिन शुगर इन्डस्ट्री ऐसा उद्योग है जिसका

[श्री कांशी नाथ पांण्डेय]

सम्बन्ध सारे देश से है। आप किसी एक सूबे के दृष्टि कोण से नहीं माप सकते हैं कि वहां कितनी शुगर फैक्ट्रियों की जरूरत है। आज यह अनुमान है कि फौर्थ फाइव इयर प्लेन में हमारे यहां 45 लाख टन चीनी की खपत होगी। आज आप के पास लगभग 45 लाख टन पैदा करने की क्षमता है, लेकिन क्या आप इस का इन्तजाम कर सके हैं कि 45 लाख टन कैपसिटी की जो फैक्ट्रियां हैं उन को पर्याप्त मात्रा में उचित दाम पर गन्ना मिले ? इस का क्या इन्जाम आप के पास है ? दूसरी बात यह भी है कि अगर यही फ्लक्चुएशन अथवा उतार चढ़ाव चलता रहा तो जो मौजूदा फैक्ट्रियां हैं उनको उचित मात्रा में गन्ना मिलेगा ? इस तरह की स्थिति को देखते हुए आज समय आ गया है कि आप अपनी पालिसी पर फिर से विचार करें।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि शायद अब समय आ गया है कि हम इस पर विचार करें कि गन्ने की खेती किस हद तक बढ़ सकती है। जब देश में गन्ने की खेती बढ़ेगी तब निश्चय ही उसका असर दूसरे खाद्यान्नों पर पड़ेगा। आज जरूरत इस बात की है कि सोचा जाए कि गन्ने की उपज या खेती को बढ़ाने के लिए क्या किया जाये। यह ठीक है कि बम्बई और मद्रास में एक एकड़ में गन्ने की उपज ज्यादा है। गन्ने की उपज के लिए आवश्यक चीज है पानी। उत्तर भारत के लिए कहा जाता है कि आखिर वहां पर गन्ने की उपज बढ़ेगी कैसे ? वहां पर सिंचाई के साधनों में आप ने क्या वृद्धि की है ? उत्तर भारत की जो मिलें हैं उन को आप कितनी सुविधा देते हैं ? केमिकल फार्टिाइजर से गन्ने की उपज नहीं वढ सकती है क्योंकि अगर गन्ने के लिए आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसके लिए पानी उपलब्ध नहीं है ; ऐसी स्थिति में गन्ने की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। यह एक बड़ी भारी समस्या है। केवल यह कह देने से कि उत्तर भारत में गन्ने की उपज नहीं वढ़ रही है। काम नहीं चलेगा। आज यह कह देना काफी नहीं है अगर आप उसकी खेती के लिए सारे साधन उपलब्ध करे उसके बाद कहें कि इन साधनों के बावजूद गन्ने की उपज नहीं बढ़ रही है, तब तो यह वात मेरी समझ में आ सकती है, नहीं तो नहीं।

जहां तक खाद्यान्नों का प्रश्न है, बहुत सी योजनायें उस के लिए बनाई गई और बहुत सी रिसर्च इस पर हुई हैं। इस में भी सन्देह नहीं है कि स्थिति में परिवर्तन हुआ है। वहां पहले एक एकड़ में 10 मन गेहूं होता था आज वह पर एक एकड़ में 40 मन गेहूं पैदा होता है। लेकिन अभी तक गन्ने के सम्बन्ध में मैंने नहीं देखा कि कोई रिसर्च हुई हो। गन्ने की पैदा वार रिसर्च के द्वारा बढ़ सकती है, क्या सरकार इस पर भी गौर करेगी ? मैं जानता हूं कि अगर सरकार इस विषय पर गौर करे और इस के लिए रिसर्च कराये तो निश्चित ही गन्ने की उपज फी एकड़ बढ़ सकती है। आज जहां पर शुगर फैक्ट्रियां हैं यह पर पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिलता है।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वड़ा परिवर्तन हुआ है, रिवोल्यूशन हुआ है नये बीजों में। एम पीज को भी गेहूं दिया गया है 3 रु० प्रति किलो की कीमत पर। बीज बहुत अच्छा है, लेकिन वेसिक चीज यह होती हैं कि जब बीज दिया जाय तो उसके साथ मोटे तौर से एक गाइड भी दी जाये कि इस तरह से बीज बोना चाहिये और इस तरह से पानी देना चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER : The hon. Member may try to conclude now.

SHRI K.N. PANDEY : Let me continue after lunch.

MR. DEPUTY SPEAKER : I have about 25 names here. I want to see that as many as possible are given an opportu-

nity. I have given you 12 minutes. Please conclude in a minute.

SHRI K.N. PANDEY : I have some more points to make. 200 sugar factories are there.

MR. DEPUTY SPEAKER : All right ; you may continue after lunch.

13 hours

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Foorteen of the Clock

———

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*
MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION—*Contd.*

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I have a very small submission to make.

SHKI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : It is a very serious and urgent matter.

MR. CHAIRMAN : All of you please resume your seat. Let me first look into the business. You do not even allow me to look into the papers ? You cannot obstruct me like this.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I wait to obstruct you.

MR. CHAIRMAN : Please wait. Let me see the business here.

SHRI S.M. BANERJEE : This morning when the hon. Speaker was in the Chair, he had mentioned that some members of Parliament including Prof. Ranga wanted a discussion on the situation in West Bengal. We are prepared for it. We have seen teleprinter news that there was no incident in Calcutta and it is absolutely peaceful. That is a different matter. The Deputy Chief Minister of West Bengal has issued a statement that any judicial probe or inquiry by the Centre is an undeclared war against the West Bengal Government. We request you...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You should not introduce a subject in an *ad hoc* manner like this. There must be some procedure. You need not mention all those things.

SHRI S.M. BANERJEE : The question is that either a discussion should be held or the Defence Minister should be requested through hon. Minister for Parlimentary Affairs to make a statement clarifying the position because we do not want the Centre-State relations to become so bitter.

Another point. The hon. Health Minister made a statement that the Essential Services Maintenance Act will be used against the striking doctors in Delhi. I request you and through you the hon. Minister of Home Affairs, the Health Minister for Parliamentary Affairs to convey to them that the doctors are already taking a decision with a view to end the strike. Such an anction on the part of the Government will only aggravate the situation. That is all that I want to convey.

MR. CHAIRMAN : I had been here following the proceedings of the House when the Speaker was in the Chair. He does not want any matter to be suddenly introduced into the House without previous intimation to the Speaker. Really he is the proper authority to deal with the points you have raised. I will convey it to him or the Deputy Speaker. Now we go on with the business on hand.

Mr. Kasinath Pandey : Will you please continue your speech.

श्री काशी नाथ पाण्डेय : थोड़ी देर पहले जब मैं बोल रहा था तो मैं कह रहा था कि

[श्री कांशीनाथ पाण्डेय]

शूगर इण्डस्ट्री के सामने आज कल गुड़ को लेकर भी एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। गुड़ बने इसके पक्ष में मैं भी हूं। लेकिन मैं समझता हूँ कि समय आ गया है जबकि इस बात पर किया जाए कि गुड़ किस हद तक बने और यह भी सामने रखा जाए कि गुड़ बनने के साथ साथ शूगर इण्डस्ट्री भी चलती रहे। आप देखे कि गुड़ का प्रयोग अब लोग खाने में ही नहीं दूसरी तरह से भी कर रहें हैं। गुड़ जाता है शराब बनाने में। चाहे बम्बई हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब ही, आंध्र हो···।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकामगढ़) : चार रुपये किलो लोग चीनी नही लेकर खा सकते हैं इसलिए वे गुड़ खाते हैं।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : पंजाब में उत्तर प्रदेश से गुड़ जा रहा है। शराब की जो हालत है वह तो आप को मालूम ही है। शराब किसी भी कीमत पर लोग खरीद कर पीने के लिए तैयार हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज किसान गुड़ बनाना चाहते हैं। जब गुड़ इस कारण से बनेगा तो उसके दाम भी ऊंचे रहेंगे। जब उसके दाम ऊंचे रहेंगे तो निश्चय ही आपको सोचना होगा कि गन्ना जो चीनी मिलों के पास जाता है उसका दाम क्या हो। गन्ने के दाम उचित सीमा पर रखे बगैर शूगर इंडस्ट्री को चलाना कठिन हो जाएगा।

शूगर इंडस्ट्री के सम्बन्ध में या गन्ने के डिवेलेपमेंट के सम्बन्ध में फूड मिनिस्ट्री ने एक डिवेलेपमेंट क्राऊंसिल बनाई हुई हैं। वह बहुत अच्छा काम कर रही है। सभी हितों का उसमें प्रतिनिधित्व है। वहां पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उसके जो प्रेजीडेंट हैं या चेयरमैन हैं यह फूड सैक्रेटरी हैं। वह तमाम बातें सुनते हैं। उस में मिनिस्टर नहीं होता है। इस वास्ते उन तमाम बातों को सुन कर वह आ कर मिनिस्टर को उनको सुनाते हैं। मिनिस्टर अगर उस कमेटी में रहते तो वह तमाम लोगों की बातों को सुनते और हो सकता है कि उन की उचित बातें सुन कर अपने दिमाग में कुछ सोचते कि क्या परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन उन के न रहने से केवल सेक्रेटरी और कुछ अफसरों के रहने से उस में वाद-विवाद होता है, जो बहस होती है, उसको वह महत्व नहीं दिया जाता जो कि मिनिस्टर के रहते हुए शायद दिया जाता।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जरूरत इस बात की है कि चीनी की कमी इस देश में है, इसलिए बगैर किसी रुकावट के, बाधा के, शुगर फैक्ट्रियां चलें और ज्यादा से ज्यादा वह चीनी का उत्पादन करें। इसके लिए जरूरत इस बात की भी हैं कि शुगर फैक्ट्रियों में लाम करने वाले मजदूर भी प्रसन्न रहें। आज होता यह है कि निश्चय ही ही इस पार्शियल डी-कंट्रोल से फैक्ट्रियों को मुनाफ़ा हुआ है और बोनस ऐक्ट के मुताबिक मजदूरों को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। गनर्नमेंट जो एक प्राइस पब्लिश करती है वह आल इण्डिया की बेसिस पर करती है और सही है कि जब मद्रास में 8 रुपये क्विन्टल गन्ने का दाम है तो चीनी वहां इतनी मंहगी नहीं हो सकती। यू० पी० और बिहार से कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा है। लेकिन यह यह जो एवरेज लगा कर प्राइस बताते हैं यह बड़ा ही मिसलीडिंग हो गया है और उस से जो कमेटियां बोनस तय करने के लिए बनाई गई हैं प्रदेशों में उन को उचित रास्ता नहीं मिलता मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से जोन को प्राइस मिलों के अश्यारेंश व रिकबरी के आधार पर तै की जाती हैं उसी तरह से जो फ्री शुगर बिक रही है उसकी भी एवरेज प्राइस फूड मिनिस्टरी को प्रकाशित करनी चाहिए। ताकि कमेटियों को यह मालूम हो सके कि इस भाव से चीनी फैक्टरी वालों

ने बेची है। क्योंकि मैंने देखा है कि जिस भाव से फैक्टरी वाले चीनी बेचते हैं उनके रेकर्ड में में वह भाव नहीं लिखा जाता। बेचते ऊंचे भाव में हैं और अपने यहां रेकर्ड में कम भाव दिखलाते हैं। वह आडिट भी हो जाता है और बनोस ऐक्ट के मुताबिक जो लिखा होता है वह हमें मानना पडता है क्यों कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उनके बैलेन्सशीट पर आप क्वेशन नहीं कर सकते। इसलिए हमारी मजबूरी होती है। अब अगर फैक्टिरयों को शांत रूप से चलाना है तो निश्चय ही ऐसे उपाय फूड मिनिस्ट्री को निकालने होंगे जिस से यह विवाद खत्म हो और कोई ऐसा सही रास्ता लोगों को मालूम हो सके, कम से कम ऐसा रास्ता जिस पर विश्वास किया जा सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं और वह पहले भी में कह चुका हूं कि पाशियल डी-कैंट्रोल की पालिसी बहुत ही गलत है, अव्यावहारिक है और एक अस्थिरता उस से देश में पैदा हो गई है। मैं इस विषय पर यह कहना चाहता हूं कि वह जो रिपोर्ट फूड मिनिस्ट्री की है उस में यह लिखा हुआ है :

The consumers besides getting their minimum requirements at reasonable prices were able to purchase any quantity of sugar in the open market for their extra requirements.

तो यह आप जानते हैं कि चीनी के उपभोक्ता इस देश में बहुत हैं। उसमें फैक्ट्रियों में काम करने वाले नौकर हैं सरकारी नौकर हैं और जो कोटा इस वक्त राशन से उनको मिलता है वह किसी के लिए काफी नहीं हे। अब सवाल यह है कि जो फ्री शुगर 4 रुपये किलो में बिक रही वह कितने लोग खरीद सकते हैं। यहां आपका यह लिख देना कि दे कैन गेट एनी क्वान्टिटी आफ शुगर कोई माने नहीं रखता। उनको इतना कैपेबल कर दें कि वह किसी प्राइस पर किसी क्वान्टिटी में ले सकें तब तो बात दूसरी है। लेकिन अगर उनकी केपेसिटी नही हैं तो इस से फायदा क्या है ? इसलि बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस पालिसी का जो कुछ भी औचित्य था और जो कुछ भी इस का फल होना था वह हो चुका है। अब इसको जितनी जल्दी बन्द कर दिया जाय उतना ही अच्छा है और मैं इस फेवर में हूं कि शुगर इंडस्ट्री का कम्प्लीट कन्ट्रोल होना चाहिए।

श्री महंत दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : श्रीमान्, कृषि का उत्पादन इस में शक नहीं कि कुछ अधिक हुआ है। लेकिन जितना होना चाहिये उतना नहीं हो सका। कृषि के उत्पादन के लिये जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उस पर हमें बिचार करना है। पहली चीज तो यह है कि हम को सस्ते मूल्य पर बैल, बीज, खाद और पानी मिले। हम देखते हैं कि बड़े वड़े उद्योगों के लिए बिजली सस्ती मिलती है और खेती बालों के लिए बिजली मंहगी मिलती है। यह विषमता जब तक हटेगी नहीं, किसान अधिक उत्पादन नहीं कर सकता। किसान जी तोड़ कर काम करता है वह प्रशंसनीय है। लेकिन साथ ही साथ उस को अगर यह साधन उपलब्ध हों जो मैंने अभी आप से कहे हैं तो हम समझते हैं कि दुगुना उत्पादन हो सकता है। इस साल उत्पादन होने का कुछ दूसरा भी कारण है कि भगवान की दया से वर्षा हुइ। लेकिन वह कुछ हिस्सों में ही हुई। उतर प्रदेश मैं मिर्जापुर इलाहावाद इत्यादि जगहों पर आज सूखे का बोलबाला है। वहाँ पर अधिक कुएं न होने के कारण उन को अधिक मदद न पहुंचने से आज वहां सूखा इतने जोरों से चल रहा है है कि वहाँ के लोगों को अपना जीवन यापन करना दुर्लभ है।

[श्री महंत दिग्विजय नाथ]

हुम को अच्छे बीज का प्रयोग करता चाहिए। साथ ही साथ उर्वरक का का भी प्रयोग अगर ठिकाने से करते रहें तो हम आशा करते हैं कि हम वह कमी जो बाहर से अनाज मंगा कर पूरी करनी पड़ती है, वह न मंगाना पड़े।

खेत की जुताई के लिए जब तक गहरी जुताई न हो तब तक उत्पादन की जितनी आशा करनी चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाता। इसलिए गहरी जुताई का जितना भी साधन उपलब्ध हो सके वह ब्लाक स्तर पर उपलब्ध करना चाहिए। जैसा अभी कहा गया है, वहां पर ट्रैक्टर्स सुलभ हो सकें तो हम समझते हैं कि हर जगह गहरी जुताई हो सकती है। लेकिन ट्रैक्टर्स के पार्ट्स मिलते में बड़ी दिक्कत है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर गोरखपुर में कोई ट्रैक्टर से फार्मिंग करता है तो उसको पुर्जों के लिए दिल्ली आना पढ़ता है और यदि पुर्जे दिल्ली में नहीं मिले तो मद्रास या बम्बई से उसो मंगाने पड़ने हैं। इसलिए आलटरनेटिव साधन जो है उसके उपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहाड़ों में ट्रैक्टर नही चल सकता। पहाड़ों में जो खेती होती हैं वह केबल बैलों से हो सकती है और बैल जो राष्ट्र की सम्पति हैं वह उस वक्त तक सुलभ नहीं हो सकते जब तक गौवध बन्द नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि गौवध बन्द करने के लिए सरकार सक्रीय पग उठाए। अभी हाल में ही सरकार ने एक कमिशन भी गोवधबन्दी पर नियुक्त किया था। लेकिन उस कमीशन के टर्म्स आफ रैफरेंस में कुछ झगड़ा होने के कारण जिसमें वोटिंग के बारे में कुछ आहति उठाई गई, वह कमीशन टूट गया। और नतीजा यह हुआ कि गवर्नमैंट जो पग जन-अन्दोलन के कारण उठाना चाहती थी वह उठा न सकी। ऐसे समय पर जब तक गवर्नमैंट इस तरफ ध्यान नहीं देगी यह समस्या हल नहीं होगी यह कहना कि कुछ लोग गाय का मांस खाते हैं, खायें, लेकिन उसकी जगह दूसरी वस्तुएं भी हैं जिन के जरिए से वह जीवन-यापन कर सकते हैं।

हमें आपसे केवल इतना ही निवेदन करना है कि गाय राष्ट्र की सम्पति है और इस सम्पति को नष्ट करने के मायने होंगे राष्ट्र को नष्ठ कर देना। हमारे देश में अधिकांश लोग छोटी छोटी खेती वाले हैं, जो ट्रैक्टर से अपनी खेती नहीं कर सकते हैं, उन के लिए बैलों के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस लिये हमारा कृषी मंत्री जी से आपके द्वारा नम्र निवेदन है कि वे इस पर पुनः विचार करें। इस को प्रेस्टिज का क्वेश्चन न वनाया जाय, क्योंकि कुछ लोग ऐसा निश्चय कर चुके हैं कि गऊ-बध बन्द नहीं करेंगे, इस लिये इस को प्रैस्टिज क्वेश्चन न वना कर देश की, अन्न की समस्या को सुलझाने में मदद करें।

किसानों को कोआपरेटिव बैंक के द्वारा ऋण लेने की जो व्यवस्था की गई है, वह ठीक नहीं चल रही है। उन में वड़ी दिक्कतें आ रही हैं, यहां तक हो जाता है कि बीज-गोदाम से बीज इतनी देर में मिलता है कि खेती सूख जाती है और बीज नहीं मिल पाता और जब मिलता है, तव उस से उपज नहीं हो पाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये आप ब्लाक में ठीक ढंग से व्यवस्था करें, जव तक यह व्यवस्था नहीं होगी खेती टीक ढंग से नहीं हो सकेगी।

किसानों के सामने इन कठिनाईयों के अतिरिक्त कुछ और भी छोटी छोटी कठिनाइयां हैं। जैसे खेतों मैं चूहे लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं, चिड़ियां काफ़ी अनाज खा जाती हैं, इन से बचाव के लिये हम लोग अभी तक कोई साधन प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। तीन-चार दिन हुए हम पूसा इंस्टीचूट में गये थे। वहां

पर हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि "साइनों-गैसिंग" का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन चुहे भी अब ज्यादा होशियार हो गये हैं, एक जगह साइनो-गैसिग तो वह दूसरी जगह निकल जाते हैं और इस तरह से साइनो-गैसिंग का भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। 8 चूहे एक आदमी का भोजन खा लेते हैं, इस तरह से प्रतिवर्ष कितना नुकसान होता है, उसका अनुमान आप यहां बैठकर नहीं लगा सकते। हम लोग जो खेती करते हैं, हम को मालूम है कि किस प्रकार से यह नुकसान होता है। इस के लिये जब तक हमारे वैज्ञानिक नये नये तरीके नहीं निकालेंगे, यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। इन के साथ ही मैं स्टोरेज के बारे में भी कहना चाहता हूं। स्टोरेज में जहां अन्न रखने की व्यावस्था की जाती है, वह ठीक ढंग से होनी चाहिये ताकि चूहे वहां पर न पहुंच सकें।

अन्न के नुकसान का एक बड़ा कारण यह भी है कि जब अन्न पैदा हो कर स्टेशन पर आता है तो बरसात के दिनों में उसे खुली गाड़ियों में भेजने से बहुत नुकसान होता है। ऐसी ही और भी बहुत सी बातें हैं जिन की वजह से अन्न के उत्पादन में बाधा पड़ रही है और जब तक आप इन बातों के लिये सामुहिक तरीके से नहीं सोचेंगे, हमारे यहां जो अन्न की कमी है, दूसरे देशों से मंगाने की जो आदत पड़ गई है, वह दूर नही हो सकेगी। मुझे आशा है कि कृषि मंत्री महोदय इस समस्या पर गम्भीरता से बिचार करेंगे।

हमारे वैज्ञानिक अनेक नये नये प्रकार के बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। हमने देखा भी है और हमें प्रसन्नता भी है। लेकिन उन बीजों का उत्पादन कैसे करना चाहिये, किस प्रकार से बीज बोया जाय, कैसे खाद डाली जाय, कितने पानी की आवश्यकता है, पानी की व्यवस्था वहां पर है या नहीं, इन सब बातों के बारे में कृषि मंत्रालय के एक्सपर्ट्स वहां जाकर किसानों को शिक्षा दें। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय तो हम समझते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ सकता है।

हमारे पशु धन का बहुत तेजी से ह्रास होता चला जा रहा है। पशुधन में हमारी गाय भैंसें हैं। दूसरे देशों से पाउडर मंगाकर, उस को दूध में मिला कर हम लोगों को पीने के लिये दे रहे हैं। हमने देखा है कि दूध में नीचे पाउडर जमा रहता है। आप की मिल्क स्कीम तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अपने यहां स्वयं डेरी स्थापित नहीं करेंगे। आप बम्बई में जा कर देखें—उन का डेयरी सिस्टम कितने सुन्दर ढंग से चल रहा है। आप गुजरात में जाइये कोआपरेटिव वेसिज पर बहुत सुन्दर ढंग से डेयरी चला रहे हैं – अगर ऐसी ही व्यबस्था आप यहां पर भी करें केन्द्रीय सरकार इस के लिये अनुदान दे, तब हम समझते हैं कि हमारी दूध की समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है अभी कल बताया गया था कि एक आदमी के लिये हिन्दुस्तान में केवल 130 ग्राम दूध मिलता है, जब कि पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति 200 ग्रांम दूध मिलता हैं। इस का कारण यही है कि हमने पशुधन की रक्षा के लिये आज तक कुछ नहीं किया। यही कारण है आज साफ़ दूध मिलना तो मुश्किल है ही, पानी भी साफ नहीं मिलता है। जिस देश में ऐसी व्यवस्था हो, आप कैसे अपनी हैल्थ-योजनाओं को चला सकेंगे जब तक आप इस ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे देश की स्थिति और ज्यादा खराब होती चली जायगी।

सिंचाई के बारे में भी कुछ कहना है। हमारे यहां एक गण्डक नहर की योजना चल रही है जो बिहार और यू० पी० के कुछ हिस्सों पर

(श्री महन्त दिग्विजय नाथ

लागू होगी, लेकिन अभी तक बह काम चालू नहीं हो सका है। इस समय वहां की स्थिति ऐसी है कि बगैर पानी के न गन्ना पैदा हो सकता है और न धान पैदा हो सकता है। गन्ने के लिये यदि गोरखपुर और बिहार दोनों को मिला कर जावा आफ इण्डिया कहा जाय तो अत्योजित नहीं होगी। गन्ना वहां की मुख्य पैदावार है लेकिन गवर्नमेंन्ट इस स्कीम में फेल रही है। इस का कारण यह है कि हमारे यहां प्लानिंग नहीं है। हम को यह नही मालूम है कि कितना गन्ना पैदा करना और कितना अन्न पैदा करना है, कितने शुगर की जरुरत है, क्यों कि इन सब के मूल्यों में समता नहीं है। अगर मूल्यों में समता रहे तो सरकार किसानों को बता सकती है कि तुम इतना गन्ना पैदा करो और इतना अन्न पैदा करो। दोनों की कीमतें बराबर रहें तो सरकार इन की पैदावार को कन्ट्रोल कर सकती है। कभी कभी इतना गन्ना पैदा कर लेते हैं कि मिलवाले उस को क्रश नहीं कर पाते और कभी इतना कम पैदा होता है कि बाहर से शकर मंगानी पड़ती है। जहां गन्ना बोया जाता है, उन के लिये मेरा सुझाव है कि गन्ने की खेती के बीच में एक अन्य क्राप भी बोई जा सकती है, चाहे सरसों बोई जाय या चना बोया जाय - इस तरह से एक सब्सिडी क्राप मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि यह शिक्षा हमारे काश्तकारों को दी जाय, इस से गन्ने के साथ साथ अन्न भी पैदा हो सकता है।

आप गन्ना मिलों में जायं, दो-दो रोज तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन केन डवेलपमैन्ट आफिस से पुर्जियां नहीं मिलती है। ईश्वर तो मिल सकता है, यदि उस का चिंतन किया जाय, परन्तु केन डवेलपमैन्ट आफिस से पुर्जियां नहीं मिल सकती हैं। यह स्थिति उस आंचल में है जहां से मैं आ रह हूं। मैं देखता हूं कि किन मुश्किलात से किसान गन्ना पैदा करता है, कितनी दिक्कतों के साथ उस को मिल में ले जाना पड़ता है, उस पर भी उस को पुर्जी नहीं मिलती है। जब तक इस की ठीक व्यवस्था नहीं होगी, हम कोई काम नहीं कर सकेंगे और न गन्ने का उत्पादन ज्यादा बढ़ा सकेंगे।

कृषि विभाग के लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लांट प्रोटेशन का नाम तो जरुर सुनाई देता है, लेकिन ईमानदारी से कहा जाय तो काम कुछ नहीं होता। उन को चिटठी लिखते लिखते हार जाते हैं, टिडियां आतीं हैं, खेतों को खा जाती हैं, तब वह वहां पहुंचते हैं। इस लिये प्लांट प्रोटेकशन की तरफ बिशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे एक आवश्यक बात और कहनी है और वह यह कि सरकार ने एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगाने की योजना तैयार की है। किसान की कमर तो अभी तक सीधी हो नहीं पाई है। सूखे की वजह से किसान भूखों मर रहा था। किसी वजह से अगर साल दो साल उसको अच्छी फसल मिल गई तो आपने उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात सोच ली। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बादशाह शिकार के लिए जा रहा था, रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी तो वह एक जगह पर रुक गया और एक किसान से कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो। उस किसान ने एक अनार तोड़ा और उसका रस निकाला जोकि एक गिलास भर कर हुआ और वह राजा को पीने के लिए दिया। बादशाह ने सोचा कि इस पर टैक्स लगाना चाहिए, सरकार की आमदनी बढ़ेगी। जब बादशाह शिकार से लोटा तो फिर उसने उसी किसान से उसकी मांग की। किसान ने दो, तीन, चार अनारों का रस निकाला लेकिन फिर भी गिलास नहीं भरा। बादशाह ने पूछा क्या बात है, पहले तो एक अनार से ही गिलास भर गया था, अब क्या कारण है ? किसान ने कहा ऐसा

मालूम होता है कि राजा की नीयत खराब हो गई है इसलिए गिलास नहीं भर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि उसी प्रकार से आप की भी नीयत खराब हो रही है, आप भी एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने की बात भी कर रहे हैं। किसान की स्थिति तो वैसे ही खराब है, उसके अनाज के भाव पलक्चुएट करते रहते हैं। अपना अनाज बाजारों तक ले जाने में उसे दिक्कत होती है क्योंकि देहातों में सड़कें नहीं हैं और दूसरे साधन भी नहीं हैं। लोग वहीं पर जा कर उसके अनाज को सस्ते दामों पर ले लेते हैं। वह बेचारा तो वैसे ही मारा जाता है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। उर्वक और सिंचाई पर उसको वैसे ही टैक्स देना पड़ता है। इस लिऐ मैं समझता हूं उन पर टैक्स को लगाना उचित नहीं होगा।

एक बात मुझे यह कहनी है कि आपकी जो लघु सिंचाई की योजना है उससे किसानों को ज्यादा लाभ पहुंच सकता है। बनिस्बत नहरों के क्योंकि पता नहीं नहरें कब तक बन पायेंगी इसलिए लघु सिंचाई योजना को अगर अच्छी तरह से चलाया जाये तो किसानों को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा।

इसके अलावा पी० एल० 480 के अन्तर्गत जो आप अनाज मंगाते हैं उसका जो पैसा होता है, वह पैसा इसाई लोग धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन अधिकत्तर उसी के कारण हो रहा है। इस तरफ सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज इस देश में मेजारिटी को माइनारिटी में चेंज करने के लिए कितने ही साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तरफ तो आप फेमिली प्लानिंग चला रहे हैं और दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन का कार्य जारी है। ये सारी चीजें उस मेजारिटी कम्युनिटी को समाप्त करने के लिये हो रही है आज इस देश में अपने को हिन्दू कहलाना अभिशाप समझा जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश नैपाल में अगर कोई व्यक्ति राजा से पूछे बिना या सरकार से पूछे बिना धर्म परिवर्तन करता है तो वह सजा का भोगी है।

अन्त में एक बात मुझे पटेल आयोग के सम्बन्ध में कहनी है। गाजीपुर के श्री गहरीम के जोर देने पर पं० जवाहरलाल नेहरू ने पटेल आयोग को गठन किया था। इसमें बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती जिलों को रखा गया था किन्तु गोरखपुर इसमें नहीं रखा गया था। लेकिन उस आयोग की सिफारिशें आज तक कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी हैं। सरकार योजनायें तो बहुत बनाती है लेकिन बाद में उन को कोल्ड स्टोरेज में डाल देती है। जब तक आप उनको कार्य रूप में परिणत नहीं करते तब तक जनता को इन योजनाओं से लाभ कैसे मिलेगा ? कारण यह है कि जब तक वहां की जनता आपके सिर पर सवार नहीं होती है और मजबूर नहीं करती तब तक आप कोई ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप उस योजना को वहां पर कार्यान्वित करेंगे तो उस अंचल से अधिक से अधिक आनज पैदा किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं सरकार इन बातों पर विचार करेगी।

SHRI BEDARATA BARUA (Kaliabor) : In the midst of understandable optimism about the green revolution, a note of caution has to be sounded because while the past performance had been impressive, according to this morning papers, this year's performance is expected to be about two millions tons short. Instead of maintaining a growth rate of four or five per cent in agriculture even after this green revolution had caught up there may be lean years in the next five or six years where we may have a shortfall of even ten million tons. If that happens all our calculations will certainly have to be modified and the question of increasing production in agriculture must be viewed

[Shri Bedarata Barua]

not only from the angle of production but from the angle of productivity. The basic weakness of our agriculture is that only twenty per cent of our cultivable land is irrigated ; the vest, about eighty per cent, depends upon the vagaries of the monson and any change in the monsoon may have affect on our agricultural production. In the meanwhile inspite of our family planning programmes, our population increases and in 1985 — not many years hence — we would need about 187 million tons of foodgrains which it would be impossible to achieve even at the present rate of growth. If we take the previous rate of growth of 2.4 per cent, the shortfall will be about 60 or 70 million tons in 1985. I think we must be careful and must also find out where exactly we are lagging behind and what axactly needs to be done. Today there is not so much progress in regard to family planning but that is not the subject which is under discussion now. In regard to increase in food production, the basic difficulty of the Central Government is that there is no uniform line of comand in agriculture and many things have to be done through the Chief Ministers' Conference and this leads to certain avoidable difficulties. Perhaps the National Commission on Agriculture may remove this lacune and may also help to bring about better understanding between different Government and also lay down a master plan for the development of agriculture. It is necessary that we should plan our agriculture on a scientific basic. I congratulate the Food Ministry for thinking in terms of a National Irrigation Commission also because it is in the fields of irrigation that the battle for more food production will ultimately be decided. It is quite obvious that when we talk of irrigation, we have always emphasized the major irrigation schemes only. The benefits of such schemes do not always reach the small peasantry. The major irrigation schemes can serve only one third of our cultivable land till the forseeable future. The rest will have to be served by medium and minor irrigation schemes. If we do not go into these aspects we are bound to create stresses and strains in our agricultural population ; the difference between the big peasants and small peasents will become such that there will be a real revolution and we shall have the same state of affairs in India as in Pakistan. It is said that in Pakistan they increased food production ; they actually doubled their food production during Ayub's regime but because they did not look to the difficulties of the small farmers, they are now in the midst of a revolutionary process which they could not contain by anything except the military rule. Unless we are able to take irrigation water technical know-how and other things to the small farmers, unless we have a method by which we can serve big as well as small farmers, the developed and the under developed areas unless we plan for the whole of India, we shall be in great difficulties. Today every technique appears to be oriented not towards the development of every agriculturist but somehow the benefits of agriculture go to certain sections of the agriculturists. This is a very dangerous signal for all of us. Not only in regards to minor irrigiation and all that, where the small farmer can also have his own irrigation and his own well which will take greater care of his land, but even in regard to implements like the heavy tractors and all that, we have before us the example of Japan which is not only experimenting but is already having what are called floating wells. There are again the garden tractors in the USA. We have produced some tractors that are usable only in big fields by the big farmers. We must remember that 90 per cent of the farmers of India are those who own not more than a few acres of land — one or two acres of land each. These people would require implements that can be fitted into their farms. Why is it not possible to do it ? There are some experiments which have been done and some efforts have been made in the matter of tractors. But we must make intensive efforts in that direction so that these implements not only do not certainly replace the labour and create new tensions, but serve the small farmers whose problems somehow we are unable, in spite of our good intentions, to solve.

There is again this lack of the chain of co-ordination or control in agriculture. The State Gevernments more ar less are more subject to pressures from the bigger peasantry and so the State Governments find it very difficult in trying to meet the needs of the small peasant.

When I come to refer to the question of research organisation, where not enough has been done but something has been done, I may mention the ICAR and the Central Research Institute on Agriculture and allied subjects which are there. The research must

be such that it can carry the benefit of research and the extension organisation to the field, and it can take the problems of the field to the research organisation. This is how our relationship has to be developed. I have no doubt that unless we carry out practical research and applied research and fundamental research, apart from taking the problem of the field to the research station or vice versa, we are not going to face the problem fully. As it has happened in many States, and in my own State, the extension organisation has given some technique, and that technique is demonstrated in the field, and the cultivators know that it has not been properly tried, and so the technique fails. The agriculturists gets more frustrated, because he knows that this technique has never been properly looked into and tried ; that it has not been properly researched. These are the problems. The extension organisation is very weak in the States. We have to see that this organisation is streamlined. Then there is the question of the supply of inputs and the provision of services. So far as this is concerned, we have done a lot.

The question of agricultural taxation has been posed before us. I feel that in Indian agriculture, if we are not able to avoid the strains that have come into the backward economy, and we are still having an economy where only the bigger agriculturists are prospering, then it is a real danger. This is not the time today for any taxation like this, because we are not sure that this green revolution, as you call it, has really stuck roots, whether it has stabilised or not. We do not know. We are unable to say that the increase in production has stabilised. It may be due to monsoonal factors ; 55 per cent of it may be due to the monsoons ; 10 to 15 millions a year. In this situation, it will be very improper now to do anything which may affect the big peasants. I know the pig peasant does not represent the peasants always. But he is the only dynamic section in the agricultural sector today. Whether you like it or not, he is the dynamic and progressive sector in agriculture today. And we cannot afford to do anything which may affect him or discourage him in anyway. If we do it, it is bound to affect our production and the country may lose the extra 20 million tonnes in terms of foodgrains. This problem has to be faced very cautiously. When you say about pump-sets and when you want to levy a tax on them, I shudder to think who is going to purchase them. The poor peasants are going to purchase these pump-sets and tractors and all that. He will be taxed and those who have already purchased these things will not be taxed.

MR. CHAIRMAN : He should conclude now.

SHRI BEDABRATA BARUA : I am concluding. The management technique has to be streamlined. At present only 3 per cent of the cooperative credit is given to those people who have assets worth less than Rs. 1,000. It should not continue like this.

So far as rain-fed areas including Assam are concerned, there has been no research made into their problems like what type of seeds will be effective there, what sort of pesticides will be necessary, whether tractors can be used, etc. Rain-fed areas have been completely left out of the picture. In areas like Assam, there are no big peasants. We have to develop our agriculture on a scientific basis and we must have research organisations to tackle these problems and also to find out how foodgrains can be produced in dry areas, we may have rains in summer, but no rains in winter and the soil may be as hard as iron. It may be difficult to cultivate except by tractors. Unless we face these problems in Assam, where agriculture is in a very backward condition, we may have to face other political problems there as in Telengana and other areas, because we have not gone into the basic problems of equalising the agricultural opportunities throughout India.

SHRI K.M. KOUSHIK (Chanda) : Sir, it shall be my endeavour in the brief time allotted to me to recapitualte what has been actually done and what the Government now intends doing and what are the hurdles that come across their intentions.

In the first plan, minor irrigation projects greatly increased. Use of fertilisers was put into effect and there was a lot of land

[Shri K.M. Koushik]

reclamation also and development and extension of land under cultivation. The result was, the plan was extremely successful. Production increased by 25 per cent and foodgrain prices came down by 20 per cent.

In the second plan, there was a shift in Government's policy. Agriculture was not cared for. Heavy industry was given more importance. There was also the land reforms policy brought into effect and there were ceilings on lands. The result was short-fall in production and foodgrain prices went up by 50 per cent. All measures to check the price rise completely failed and the plan was not successful. It could be called a failure.

In the third plan also, there was a complete shift towards heavy industry. To say the least, agriculture was completely neglected. Except in 1964-65, the production was very low resulting in heavy imports controls, zones, monopoly procurement, Food Corporation, State-trading, etc. came into being.

After all these pitfalls, in the fourth plan, the Government have realised that due attention has to be given to agriculture. I am glad about it. Now, they want to adopt new scientific techniques like use of improved seeds, heavy dose of fertilisers, weedicides, insecticides, etc. It is very good and I have no quarrel with it. But they must not forget that the biggest bottleneck in India is water, so far as agriculture is concerned and all these scientific techniques will be absolutely of no avail unless we actually give the former timely and adequate supply of water. This is absolutely necessary to utilise fully the scientific techniques they want to introduce to bring about an agricultural revolution.

Though I am not a cultivator, I have got intimate knowledge about it. In my district, in one tehsil, they took to Taichung—the Japanese method of rice cultivation. It was a gamble with rain. There was no rain and there was no source of irrigation with the result the crop completely withered. Now if you go and tell them to take to this method of cultivation, they would not even touch it with a pair of tongs. Therefor, the biggest bottleneck is water and you have to deal with that problem first.

Certain big projects have come into being. India is a vast country and a few big schemes here and there will not supply water to the nook and corner of India. Also, big projects require a long gestation period and involve a heavy expenditure, which is not possible for us to do in our present financial position. The alternative is to take to minor irrigation projects, as was done in the first plan. That is the only thing that can give the agriculturists timely and adequate supply of water. Minor irrigation projects may be in the nature of tanks which every village commands or bundings or small nallas which flow all through the year. There are small perennial sources of irrigation and we can have small bounds on them. They do not require a long gestation period nor heavy expenditure.

Now, who is to take the trouble to find out these sources of irrigation. Our ministers are busy ; they are sometimes too busy with extra-curricular activities like laying foundation stones, presidential addresses ; etc. I want the Government to take up a crash programme of improving every tank in every village. It is not possible to put up big irrigation projects or spend huge sums on bundings, etc. Therefore, there should be a crash programme of repairing every tank which was a source of irrigation in the old days.

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : Some minister will come to inaugurate that also.

SHRI K.M. KOUSHIK : That is not a bad thing at all. I would congartulate him, I only want the Government to look at it in the proper perspective. May be because of the vastness of the State, it may not have been possible to find out the potentialities of each district. That is also possible. But unless you give the farmer proper facilities and an adequate and timely supply of water, it is no use going in for sctentific techniques. They will only prove disastrous.

14.55 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Secondly, we must now decide what is the land reform policy. Already the peasants in our country are holding very uneconomic holdings. If you want to have ceilings on land it will further subdivide the already un-economic holdings into further sub-divisions and lead to fragmentation. I do not say that land reform measures should not be there. I am for progressive measures. But I want that one policy must be there. If the holdings are uneconomical the peasants will not be able to modernise the land and use improved methods of cultivation. If only they have economical holdings they can make use of them. Therefore, we must decide what should be our policy, whether we should have uneconomical holdings or economic holdings and whether there should be a ceiling on land or not. These are policies which should be decided so that there may not be any drag on agriculture.

Agriculture has become a gamble with rains in our country. This has to be kept in mind. Uneconomic holdings prevent the use of modern techniques. The holder has neither the means nor the enterprise to modernise his farms. Thirdly, the method of storing has to be re-vitalised. Some of my hon. friends have suggested and I also want to add that in the *Economic Times* of September, 1966 it has been said that in growing and harvesting 20 per cent of the grains are lost and 10 per cent are lost due to rodents and pests. The Bulletin on Grains Technology also says that 10 per cent is lost due to rodents and pests. The Government Audit Report (Civil) 1966-67 shows that there was procurement of grains worth Rs. 589 crores, sales amounted to Rs. 491 crores and losses due to rodents etc. amounted to Rs. 78.36 crores. Therefore, new methods of storage will have to be devised not only for storage of foodgrains of the Department but also of the agriculturists. We have been losing a lot of foodgrains because of lack of proper storage facilities.

The food problem is a creation of the Government and the Government always thinks that control is a *chumantar* for all scarcities and State Trading is supposed to be the cure for all ills of distribution. If the intention of the Government has been to supply cheap grain I regret to say that it has miserably failed due to various factors. For example, there are the food zones. The agro-economy is actually damaged and the national integrity also is damaged because the surplus and deficit States do not share the happiness and misery with each other. The surplus States want to exploit the deficit States with the result that there is damage to national integrity. Is the producer happy in the food zones? The producer is actually made to supply foodgrains at a rate which the State Government fixes and he is not having a free market. The consumer is not happy because he is not getting it at a cheap rate. Wide disparity in prices was observed in the price of gram. It was Rs. 85 in Rajasthan, Rs. 119 in M. P., Rs. 212 in Maharashtra and so on. This was the state of affairs so far as gram was concerned in 1967. This wide disparity gave rise to smuggling and a lot of corruption.

SHRI JAGJIWAN RAM: Today gram is free.

SHRI K. M. KOUSHIK; I am only saying that this disparity has led to these things and therefore the zonal barriers should go. Loss due to deterioration is also there. If you will see the figures given in government reports you will find that relaxation of these zones has yielded very good results. Barley in Punjab, which is a surplus State, was Rs. 64/65 and in Bombay it was Rs. 70/78. Maize was Rs. 64/66 and Rs. 70/75 respectively. This shows that after relaxation of zonal restrictions the price has stabilised and it has also been the same in surplus and deficit States.

15 hours

The hon. Minister reminded me the position with regard to gram. In this very House I have suggested that relaxation of the zonal restrictions on grams and pulses would give an idea to the government whether relaxation of the zonal rest-

[Shri K.M. Koushik]

rictions with regard to foedgrains should be there or not ; if the prices go up, cartainly, it would be harmful and that will give an indication. Accordingly, in the months of March-April, 1968 relaxation of the restriction on the movement of grams and pulses was ordered. What is the result ? Earlier, we were paying Rs. 3.50 per kilo of gram dal. Now, after the relaxation, for the last seven or eight months we are getting it at the rate of Re 1 per kilogram. So, the price has stabilised and there is no difference or fluctuation at all. The zonal restrictions have led to corruption and smuggling. But the removoval of this restriction has not in any way injuredconsumer. Actually, it has helped the stabilisation of the prices and prices have come down in the deficit areas. I will read out your own experience given in consumer prices. The removal of restriction by Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and recently Madhya Pradesh on the movement or coarse grains like jowar and bajra outside the State had a salutary effect of steadying the prices of coarse grains. So, zonal restictions have not improved matters in any way and they have not proved to be of advantage to the producers ; they have become equally disadvantageous to the consumers. They have not been helpful either to the producers or consumers according to your report. The relaxation of the restrictions is the remedy and you have accepted it. Therefore, I submit that the zonal restrictions must go with regard to foodgrains also.

Coming to other things, with regard to rice there might be honest difference of opinion, but with regard to wheat the position today is somewhat different. The restrictions on wheat should be freed and there should be no restrictions at all. With regard to making a buffer stock at this stage, you have already some stocks. In addition to that, you are expecting a consignment of 2·8 million tonnes in this month. So, you can have a buffer stock of the foodgrains you are importing and there should be free movement, so far as foodgrains produced in this country is concerned.

Lastly, the Food Corporation was intended to be a competitive venture for providing very cheap food to the consumers. But everybody now feels that it has become a monopolistic concern. The President of the Consumer Co-operative himself says that the Food Corporation is the biggest middleman in the country, charging a commission of more than 13 per cent on the procurement of rice from producers and selling them to the consumers. I will give you the procurement rates for jowar and rice in my district. Jowar was procured last year at Rs. 53 and the selling rate of the Government to the consumers was Rs. 67. So, the Corporation was getting Rs. 14 for one quintal of jowar without doing any work. If this is the way the Food Corporation functions, I do not know how the objective of Government of supplying cheap grain to the consumer can be fulfilled ; it is a matter which I am not able to understand.

Take another example. They pay Rs. 89 or 90 for one quintal of rice to the producer, procure it and keep it in the Government godown. The selling price to the consumer is Rs. 105, a margin of Rs. 15. If this is the contribution made by the Food Corporation, it is impossible to think that it can tackle this problem and supply cheap grain to the consumers.

Next to food is clothing. We are already short of cotton and, therefore, I would request that something should be done in order to step up the production of cotton in this country ; otherwise, we will be in a predicament and will again be made to import cotton from foreign countries.

Lastly increase in cattle wealth has not been taken into consideration at all. Apart from the fact that it supplies milk and fat which is rich in animal protein--that is one of the arguments that have been advanced--it will increase manure. I also say that chemical manures are going to make our lands absolutely useless if they are continuously used for some time. I have a lot of authorities ; I do not want to quote them and take the time of the House. An increase in cattle wealth will increase manure and that manure is necessary. Unless this manure is used along with chemical manure, our lands are going to be absolutely useless after some time. Therefore, I hope, the Government will take into consideration this position and try to increase cattle wealth.

Then, I wanted to deal with soil conservation also which is a factor, but I have no time. Kindly see to it. Soil conservation is a very important matter and, I hope, the Minister will see that something is done in this regard also.

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, while appreciating the developments made in the agricultural sector, all the rural population was expecting that more benefits will be given to the farmers in this Budget because on several occasions the Prime Minister of India and the Deputy Prime Minister and Finance Minister also had given an impression to the farmers that they would be given proper treatment by allocating funds, not for their personal use but for the development of agriculture so as to feed the undevelopment areas where foodgrains are not being grown. In several areas instead of growing foodgrains so as to be self-sufficient, they are constantly growing only commercial crops in the name of earning foreign exchange or something like that. The States which are growing foodgrains are not being benefited by the Government of India saying that they are not contributing to their projects because they have no money. Along with other States where they have developed industries —like port areas and States like Maharashtra ; we are not grudging the development of Maharashtra—areas where food production is developed should also be given finances from the Government of India. But after giving all assurances to foodgrains growers, all of a sudden in the present Budget our Finance Minister has dropped a bombshell,

SHRI JAGJIWAN RAM : It did not explode.

SHRI K. SURYANARAYNA : Not yet. It is a time bomb.

Almost 90 per cent of the Members, whether of this party or of that party, are elected by the rural areas and unless we look after the interest of farmers, not only for money but for the development of the country, there is no use of our being in Parliament. That is why we approached the Cabinet and we are thankful to them that they were kind enough. It seems, the entire Cabinet has agreed to reconsider the proposals.

Recently I received nearly 300 or 400 letters from our constituencies asking me to represent to the Government of India against the taxes—not only the tax on fertilisers but also on kerosene oil and petrol—which are affecting not only the farmers but agricultural labour and anyone. So, I request the Government of India to give deep consideration to relaxing all the tax burdens.

As for fertilisers, when other countries, like Japan, are using 200 to 300 kilogrammes per acre, our country has not reached even 4 kilogrammes per acre on an average. How can we develop agriculture unless we give some relief, some incentive to the farmer ? Instead of giving incentive, we are giving him discentive ; instead of giving encouragement, we are giving him discouragement. What is the use of saying, rural development, rural industry, will get encouragement and will be developed in the Fourth Plan. With all these slogons only we are going on like that. I submit to the Government, through you, Sir, that there must be some relief given to the farmer, not only by giving any loans or anything.

Take, for instance, tubewells. There are so many tubewells which are being put in various States. There are some failures also. I know of a veteren Congress gentleman in my district who was gone for a tubewell for which he has spent nearly Rs. 30,000 to Rs. 40,000. He has not suceeded. So, he has lost his entire property. In my district, we have ourselves formed a tubewells co-operative society with the help of the Collector and the Social Welfare Board with a capital of Rs. 25,000 to Rs. 30,000 to give some help, some fillip, to the farmer who has failed, where there is no success in the tubewell, as a sort of compensation. The Government should also give help to the farmer instead of giving it to consumer societies. City-fellows are being benefited like this. The farmers should also be benefited. The Government should give help to the farmers and to the rural population. We do not want to grudge the towns people. They should also be benefited. They should

[Shri K. Suryanarayana]

also be fed with our production and everything. They must live comfortably also. But recently, Sir, the Finance Secretary, Mr. I. G. Patel, has said that the agricultural industry has been developed like anything and they are very prosperous and are getting Rs. 1000 per acre. All these things have been said. Mr. Masani has given a report on the Suratgarh Farm. They are not even getting 0·07 percent income on the investment made. They say, it is an experimental farm. The farmers are also doing experiments all these years, for the last three or four years, by getting all the credits and facilities through community development, through fertiliser credit and everything.

Now, the prices of fertiliser have been increased abnormally. They have cut down the subsidy already and they have increased the prices also. They want to have 10 per cent which means that production charges will be increased by factory-walas and Importers. The taxes are also increasing, not only the prices. It is a set-back to the agricultural industry. If they do not give any consideration not only to reduce prices but to scrap the new proposal, I would beg of the Agriculture Minister to do something. He is only earning money and giving it to the cash-keepers, the public exchequer. He should not give it, unless he gets return for agricultural industry, from the Finance Minister. Simply giving 10 hours or 12 hours to speak on the demands for grants of the Food and Agriculture Ministry will not help. You are not getting money for the development of agricultural industry comparing with other industries. It is a big industry in the country. The Finance Ministry should give proper consideration to all the matters for the development of agriculture.

The agricultural industry in the rurals areas is being developed only recently. But there is still the food shortage in the country. There is the sugar industry. The country is exporting sugar. We are getting foreign exchange also. The industry is being developed in four or five States. We have no objection. They have developed long long ago. But where there is potentiality on account of recent changes, from Maharashtra area to Andhra, Mysore and Madras they are not being considered to licences immediately. I understand, according to the statement which was given in Parliament in Maharashtra State, besides other States, they have applied for 16 licences which are pending since 1963. They are getting, it seems, 40 tonnes of sugarcane per acre and the sugar content is 12 per cent. I would request you to consider immediately and to dispose of all the applications which are pending for cooperative sugar factories. That is the only industry which can develop in rural areas to help the farmers. So, I would beg of the Government to develop sugar industry and the foodgrains trade also. I have no objection to give it to private merchants. There must be some competition also. In the food trade the Government have lost Rs. 200 to Rs. 300 crores during the last ten years. But the Food Corporation are showing some profits. As far as my knowledge goes, they are imposing so many cuts on the millers and suppliers in the trade. I know these things. I am associated with the co-operative society. They will impose so many cuts. Some inspector will be there. Unless our clerk goes and sees them, they will not give that facility. They are imposing so many cuts. This means reducing the normal prices. But they are not giving this benefit to the consumers to whom condemned paddy and damaged rice are supplied. They are not giving the benefit to the consumers. This has to be inquired into by the Minister.

When the Food Corporation was formed we were very glad. But in the implementation there are so many deficiencies. For instance, they have constructed several godowns. In my district also they have planned a godown three miles away from the Railway Station. The transport difference in this will come to several lakhs of rupees. Our technical people may not know the local conditions that are prevailing. Where is the necessity to locate it three miles away from the Railway Station, Tadepalligudam, when there is a site available near the railway line. They have invested Rs. 30 to Rs. 40 lakhs. They have also asked for the modern rice mill to be put up three miles away, along with the godown, because they will supply paddy from the godown and no transport will be involved. All the farmers are supplying to the co-operative mills directly. We have paid only Rs. 5/- per yard for the construction of a co-operative rice mill near the Railway Station.

Therefore, the transport charges are lesser and we are benefited to the extent of Rs. 50 to Rs. 60 thousand per year.

There are so many obstacles for development in this country. In my view, the Planning Commission is one of the greatest obstacles. There is no necessity for this at this level. They have appointed so much of staff. I know. My friends are there. From morning to evening they have nothing to do except go on revising and revising the plans. In order to recover all these things they are charging the farmers to the extent of Rs. 20 or Rs. 30 crores on fertilisers alone. They are losing in some other sector, but are trying to make good the loss from this sector, and unnecessarily we are made unpopular.

AN HON. MEMBER : Wealth tax also.

SHRI K. SURYANARAYANA : So many of our friends think that we are all landlords and we are afraid of wealth tax. But we are not afraid of wealth tax. Not only in India but in the whole world, the honest tax-payer, the person who does not evade the tax, is the cultivator. In all other sectors persons are evading tax. All the cinemawalas are evading tax. We all know who are the tax-evaders. But still they are awarded Padma Shri, Padma Vibhushan and all that ? Why should they give those awards ? What is the necessity ? They spend Rs. 10,000 or Rs. 15,000 for functions in connection with these awards.

Any tax which will be beneficial to the farmer and which will act as an incentive for his production should be given. Mr. Jagjiwan Ram and Mr. Morarji Desai, with a good intention, may have thought of the wealth tax. But, after the introduction of land legislation, where is the wealth ? Birlas and Maharajas have purchased in our area 300 acres. Let Government tax those people. They should tax the black-marketeers who, in the name of purchasing land, have put their black money and are converting it into white money. They have taxed innocent people. Hon. Shri Jagjiwan Ram kindly reminded me regarding wealth tax. Our Finance Minister several times assured the people in Bombay year after year that agro-industries will be developed. Wealth tax also—we are not afraid of that. That should be given deep consideration, as also the fertiliser tax and the tax on pumping sets. They say only a wealthy man will have pumping sets and tubewells. But that is not a fact. Only in the upland area where they have no irrigation facilities, the tubewells are being proposed for the development of agriculture at an abnormal cost. We have started a co-operative tubewells society in my District. We are also arranging finance to the farmers through co-operative land mortgage banks. In our State there is one example. There is no money with the Electricity Board. We have borrowed from the Land Mortgage Bank nearly Rs. 28 lakhs and advanced it to them We are paying $7\frac{1}{2}\%$ interent to the Bank and the Electricity Board is paying it to the farmer at $5\frac{1}{2}\%$. The two per cent margin we are paying from our pockets to the co-operative Land Mortgage banks.

SHRI JAGJIWAN RAM : You are still continuing.

SHRI K. SURYANARAYANA : Yes, Sir. The tobacco growers also represented to the Government of India that their unsold stocks should be purchased by the STC and they should find out market for that in various countries. Unless they look after all these things not only farmers personally but your efforts also in food production will be affected.

DR. KARNI SINGH (Bikaner) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I realise that the time at my disposal is very short. So I will confine myself to the problems of the famine-affected areas in Rajasthan. As you know we are facing one of the worst famines the State has ever had in the last 100 years. There are just 3-4 months left now to tide over, and I feel that with the help of the hon. Minister and this House we will be in a position to tide over these 3 months. There is no doubt that the famine in Rajasthan this year will cripple the State for the next 15 years. There will be a great deal of help we will be requiring from the Centre to put the State back on its own feet.

As far as cattle wealth and agriculture is concerned, there are many parts in the country and in the world where there is low

[Dr. Karni Singh]

rainfall. I would like to make a suggestion to the hon. Minister that we should have research done on this aspect and the farmers should be shown to change the time of sowing because in Rajasthan we have seen the last rain has begun to fail year after year. Because of this the crops start withering away. Perhaps the Agricultural Research Institute may be in a position to give the farmer some idea.

The other question is about the use of a strain of grain for seeds which would grow in less irrigated areas and where there is very little rainfall. I think science and technology has reached a stage where it should be possible for us to produce strains of seeds which will grow in the arid areas of our country.

Coming to the major problems of Rajasthan's famine-stricken area, I would like to draw the attention of the hon. Minister and this House to one or two major problems that we have faced during the present famine and that is when work on a particular famine work or camp is completed before the new work is opened there is an intervening period of some days or even weeks and the poor famine-stricken people have no means of sustaining themselves during this period and for two or three weeks they have to depend entirely on their own savings which to say the least, is next to nil.

I would request the hon. Minister that in case immediatety work cannot be opened out in the next three months until rain comes, this labour must be given food free of cost or they should be paid for this lay off period because it is not their fault if the work cannot be opened out. Since this is the worst famine in 100 years it must be treated special care and sympathy.

The other question is about पिआई, drinking water being drawn by the villagers for use of the village. The same question arose in this House on a previous occasion and the hon. Minister was kind enough to observe that Rs. 25 to Rs. 50 would be given to each villager for drawing water. Now, I may draw the attention of the House to this fact once again. In this severe famine some of the animals used for drawing water have died. Often 2 or 3 men have to work together to draw the water for the village and cattle. Earlier on, Rs. 12·50 was paid for this work to the drawer and it was later raised to Rs. 25. This amount is not adequate. The payment rate should not be based on the basis of population alone but it should be based on the depth of water in the wells also. In Rajasthan water in many areas goes as low as 300 feet.

The other question is about shelter and medical aid. We are passing through an excruciating heat wave in the famine areas in Rajasthan. Never in the history of Rajasthan have we experienced this 107° F to 112° F in March. This is the temperature which is normally recorded in May, but this year the temperature has shot up to 112 degrees already even in the month of March. Because of this people are apprehensive of large-scale spread of epidemics. Adequate shelter will have to be provided at the famine camps, more so for women and children to protect them from this extreme heat.

The question of availability of fodder is another important point. Presently, fodder is reasonably easily available in towns but arrangements must be made for fodder to be made available in villages also preferably at patwar level instead of only town levels. Alternatively Government should notify to villages the dates on which fodder will be available in the villager so that they may go there and collect them from time to time.

One of the basic problems in our country is about the storage of foodgrains. I was told the other day that there is shortage of berthing place for loaded food wagons and one of the wagon trains with foodgrains had to be sent to Madras, because there was no berthing place to park these wagons in Punjab. If this is true, I request the hon. Minister to see that there should be a greater coordination between the

Ministries of Food and Agriculture and Railways.

I believe that the Food Corporation of India cannot dispose of their stocks of maize and jowar. I think these are lying in their own stocks today. If that be the case, they should be allotted to the famine-stricken areas where people are still getting lower quotas of food than their requirements, commensurate with their needs in the famine camps where considerable work is taken out of them, in these extremely hot conditions.

That is all that I wish to say and I thank you for the time that you have given.

श्री अचल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग खाद्य और कृषि समस्या के ऊपर जो डिमांड है उस पर विचार कर रहे हैं। हमारा देश कृषि-प्रधान देश है। आज भारत की जो नैशनल इनकम है वह करीब 3,000 करोड़ रुपये की है। उस में से 1,500 करोड़ रु० हम को ऐग्रीकल्चर से मिलता है। यह विषय बहुत अहम है। आजादी से पहले हम करोड़ों रुपयों का गल्ला देश से बाहर भेजते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद हमारा देश अन्न के मामले में दूसरों का मौहताज हो गया।

अन्न की बहुत कमी हो गई है। मुझे याद है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उस वक्त गेहूँ चार सेर का बिका था। तब हमारे देश में बड़ी हलचल गई है और लूटमार मच गई थी। दूसरी लड़ाई के बाद हमारे देश में जितना गल्ले का जखीरा था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। उसने कृषि की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया। पहले हमारे देश की मंडियों में लाखों और करोड़ों मन गल्ला पड़ा रहता था। गांवों में जो खत्तियां होती थीं, कोठे जो होते थे वहां पर भी कितना ही गल्ला पड़ा रहता था। इस तरह से करोड़ों मन गल्ले का स्टाक हमारे देश में रहा करता था और देशवासी बड़े आराम से रहते थे। उस वक्त गेहूँ का भाव दो रुपये और तीन रुपये मन था। लेकिन आज आप देखें कि गेहूँ का भाव चालीस से लेकर साठ रुपये मन तक का है। हमें इस बात पर गोर करना है कि हमारे देश में यह स्थिति क्यों पैदा हुई है।

हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला चलाया। तीन योजनायें हम पूरी कर चुके हैं। लेकिन कृषि पर हमको जितना ध्यान देना चाहिये था उतना ध्यान हमने नहीं दिया। हमने औद्योगीकरण पर काफी ध्यान दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में उद्योगों ने काफी उन्नित की। लेकिन कृषि में हमारे देश ने कोई उन्नित नहीं की। हमारी कृषि की पैदावार कम होती गई। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी आवश्यक्ता के लिए जितने अन्न की हमें आवश्यक्ता थी वह भी हमारे पास नहीं था और हमको अमरीका से करोड़ों रुपये का अन्न मंगाना पड़ा। यह अन्न हमने पी०एल० 480 के तहत लिया। इसकी वजह से हम आज हजारों करोड़ों रुपये के अमरीका के कर्जदार हो गए हैं। यह हमारे देश के लिए जोकि कृषि प्रधान देश है बड़े ही शर्म की बात है। हमको दूसरों के आगे झोली फैलानी पड़े, यह हमारे लिए खेद की बात होनी चाहिये। हम दूसरों से खाने के लिये अन्न मांगें, इससे बढ़ कर हमारे लिए शर्म की और क्या बात हो सकती है।

बड़ी खुशी की बात है कि पिछले दो वर्ष से जब से हमारे मौजूदा मन्त्री महोदय ने इस विभाग को सम्भाला है, हम ने कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति की है। हमारी कृषि की पैदावार बढ़ी है। दो साल पहले सूखा पड़ा था और तब हालत बहुत खराब हो गई थी।

[श्री अचल सिंह]

1967-68 में इस तरफ ध्यान दिया गया और वर्षा भी अच्छी हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में सौ मिलियन टन के करीब गल्ला पैदा हुआ। अब कुछ आशा का संचार हुआ था। और मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था हो, बीज की हो, खाद की हो और लोगों को कर्जा मिले ताकि वे अच्छी फसल पैदा कर सकें। इन सब प्रयत्नों के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस वर्ष महावट नहीं हुई, फलस्वरूप इस साल जो पैदावार होने का अनुमान है उतनी नहीं होगी। इसका कारण बारिश का न होना है। स्टेटिसटिक्स वाले बताते हैं कि इस साल भी जो उत्पादन है वह पिछले साल के उत्पादन के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो निश्चय ही हमारी हालत बहुत अच्छी हो जाती।

मैं देखता हूं इस वक्त गल्ले की कोई कमी नहीं है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि जो रेस्ट्रिक्शंज इसकी मूवमेंट पर लगाई गई हैं, जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, जो जोंज़ हैं, जो कन्ट्रोल हैं, उनको हटा लेना चाहिए। अभी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ रहा है। लेकिन वहां पर सरकार ने गल्ला पहुंचाने का प्रबन्ध किया और लोगों को गल्ला मिलता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी आदमी पिछले बरस वहां या कहीं और भूखों नहीं मरा। पिछले दो सालों में भूखों नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही क्रेडिट की, बड़े ही गर्व की बात है।

कृषि उत्पादन हमको बढ़ाना है तो हमें पानी की व्यवस्था करनी होगी। आज पानी की बहुत कमी है। खास तौर पर मैं अपनी कंस्टिटयूएंसी की बात आपको बतलाता हूं। बीस बरस पहले जितना पानी वहां मिलता था उतना ही पानी आज भी मिलता है। एक प्रतिशत भी पानी वहां ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। जमना की नहर आती है। ताजेवाला पर सारा पानी रोक लिया जाता है और एक चौथाई या पांचवां हिस्सा ही पानी वहां से आगे के लिए दिया जाता है। भाखड़ा डैम बन गया है तब भी हमारे वास्ते पानी रिलीज नहीं किया गया है। इसका नतीजा यह होता है कि नहरों में पानी नहीं आता है या बहुत कम आता है और उसकी बजह से काफी परेशानी होती है। कुछ लोगो ने ट्यूब वैल लगा लिये हैं जिससे लाभ हुआ है और पानी का इंतजाम उन्होंने किया है। लेकिन आम किसानों को पानी नहीं मिलता है। उनको बड़ी परेशानी होती है। पहली योजना से मैं इस बात की कोशिश करता आ रहा हूं कि आगरा के लिए पानी का इंतजाम किया जाए, वहां पर सिंचाई के लिए पानी दिया जाए हमेशा यही कहा जाता रहा है कि रामगंगा डैम बन रहा है और जब वह बन जाएगा तब आपको पानी मिल जाएगा तीनों योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। पता नहीं रामगंगा डैम कब बन कर तैयार होगा और कब पानी आगरा जिले को उससे मिल सकेगा। मैं समझता हूं कि पानी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है।

अब आपने पम्पिंग सैट्स पर ड्यूटी लगा दी है। यह बहुत ही अनुचित है। खेती सही अर्थों में अभी शुरू ही हुई है। जो कमी है उसको हमें पूरा करना है। ड्यूटी जो आपने बीस परसेंट लगा दी है उससे इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। यह बहुत खतरनाक चीज है। मैं चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय वित्त मन्त्री जी से इसके बारे में बात करें।

कृषि के साथ दूध का भी बहुत सम्बन्ध है। यह कहा जाता था कि भारतवर्ष में दूध की नदियां बहती हैं। मेरे ही जमाने में एक रुपये का बीस सेर दूध मिलता था। मैंने पिया है। लेकिन आज उसका भाव एक डेढ़ रुपया सेर है। हर आदमी को दूध मिलता था। लेकिन आज हालत यह है कि औरतों को, बच्चों को,

कमजोर आदमियों को, रोगियों तक को दूध मिलना मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी योजनाओं में जितना ध्यान व्यापार की ओर देते हैं उतना ही ध्यान पशु धन की ओर, दूध की पैदावार की ओर, पशुओं की नस्ल सुधारने की ओर, कैटल ब्रीडिंग की ओर भी दें। आज हम देखते हैं कि अमरीका, हालैंड न्यूजीलेंड वगैरह में दूध की नदियां बहती हैं। हिन्दुस्तान में जो नदियां दूध की बहती थीं वे आज अमरीका, हालेंड, न्यूजीलेंड वगैरह में बहती हैं। आज हिन्दुस्तान में दूध नाम को ही मिलता है। अमरीका में प्रति व्यक्ति दो पाउंड दूध का औसत बैठता है हमारे यहां एक दो आउंस ही शायद बह बैठता हो। हमारा देश शाकाहारी है। हमारे यहां लोग मांस नहीं खाते हैं, अण्डा नहीं खाते हैं। उनको अगर दूध घी भी न मिले इसका क्या परिणाम होगा, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं।

अमरीका में एक गाय अस्सी पाउंड दूध देती हैं जब कि हमारे यहां दो-चार या छः-आठ पाउण्ड से ज्यादा नहीं देती हैं। इतना ही हमारे यहां औसत बैठता है। मैं आप से आग्रह करूंगा कि इस चीज को आप वार बेसिस पर लें, वार वेरिस पर कैटिल ब्रीडिंग की ओर ध्यान दें।

मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है कि थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, इसकी कोशिश हो रही है। भारत की आबादी पचास करोड़ है और साढ़े पांच लाख यहां गांव हैं। यहां पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है। पशु धन की वृद्धि होनी चाहिए, उसकी नस्ल सुधारी जानी चाहिये। अच्छी गायें होनी चाहियें, अच्छी भैंसें होनी चाहियें। ऐसी होनी चाहियें जो कम से कम बीस पाउंड और चालीस पाउंड दूध दें ताकि हर एक को दूध मिल सके।

कृषि की उन्नति के लिए, पानी, खाद, बीज, पशु धन, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। पशु धन की ओर पूरा ध्यान दिया जाय ताकि अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें हों और ज्यादा दूध मिल सके। सांडों की नस्ल को भी सुधारा जाना चाहिये। महात्मा जी ने वर्धा में इसकी कोशिश की थी। जो गाय दो या चार पाउंड दूध देती थी वह आट दस पाउण्ड दूध देने लग गई थी। मैंने देखा है कि बंगलौर में कैटल ब्रीडिंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और उसकी तरक्की हो रही है। वहां पर नस्ल सुधार की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है पहले प्रथा यह हुआ करती थी कि हमारे यहां बुजुर्गों के नाम पर सांढ या बैल छोड़ दिये जाते थे और उनसे अच्छी नस्ल पैदा होती थी। ऐसा कोई प्रबन्ध होना चाहिए कि अच्छे सांढ, बेल, अच्छी गायें, अच्छी भैंसें हो सकें और इस ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांड्ज का समर्थन करता हूँ और आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री शारदानन्द (सीतापुर) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर विचार प्रकट करने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक विकराल समस्या बना हुआ है। आज खाद्य और कृषि पर कल से विवाद चल रहा है, मैं कल से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की तारीफ़ की कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। 17 मार्च को मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि दो वर्ष में हमारा देश आत्म-निर्भर हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उन का आधार क्या है ? कौन से उनके पास ऐसे आंकड़े हैं जिन के द्वारा उन्होंने इस प्रकार की घोषणा

[श्री शारदा नन्द]

की है। मैं चाहूँगा कि जब वह जवाब दें तो इस बात को अपने जवाब में बताएं।

आप जानते हैं इस देश के अस्सी प्रतिशत लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का मान-सम्मान विदेशों में कितना है ? आज हम भुक्खड़ के नाम से विदेशों में पुकारे जाते हैं। अपने देश में जहां पर 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं, हम खाने के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो पाये हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश ने स्वतन्त्रता पाई, उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं जिस का यह परिणाम है कि आज 20 साल के बाद भी हम आत्म-निर्भर नहीं हो पाए हैं। सब से बड़ा कारण उसका यह है कि जो सबसे पहली प्राथमिकता दी गई वह खेती को न दे कर उद्योगों को दी गई है। उद्योग हमारे देश के लोगों के जीवन-यापन के साधन हो सकते हैं पर जीवन देने के वह साधन नहीं हो सकते। जीवन तो खाद्य समस्या हल होने से ही मिलेगा। खाद्य समस्या के हल के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। सब से पहले पानी की आवश्यकता है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा और वह यह कि आज इस विभाग के साथ सिंचाई विभाग पर भी जोर देना चाहिए और सिंचाई विभाग तथा खाद्य विभाग के मन्त्री एक होने चाहिएं, यह मेरी मांग है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पानी की आवश्यकता है, उसके लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बना करके इस देश में उस कठिनाई को दूर करने का विचार किया गया जिस का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश की 80 प्रतिशत जमीन वर्षा पर निर्भर है। उसके लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज छोटी-छोटी योजनाओं के द्वारा, लघु योजनाओं के द्वारा इस कार्य को पूरा किया गया होता तो भली प्रकार से हमारे खेतों को पानी मिल पाता। आज देश में जगह जगह ट्यूबवेल बन रहे हैं। पिछले वर्षों में जब कि खाद्य की बहुत कमी थी, जगह-जगह सूखा पड़ रहा था, उस समय लोगों को प्रोत्साहित किया गया, किसानों से कहा गया कि खेत-खेत में कुएं खोदो, रहट लगाओ और छोटे-छोटे ट्यूबवेल जगह-जगह बनाओ। जब ट्यूबवेल बने उस समय किसानों ने सोचा कि हम को देश की आवश्यकता पूरी करनी है, इसलिए मेहनत के साथ अपने खेतों में उसने रहट लगाए, कुएं लगाए। उसके बाद हो क्या रहा है ? एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि दो साल में हम आत्म-निर्भर हो जाएंगे, दूसरी तरफ मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि वहां पर जो पानी की व्यवस्था की गई, सरकार के द्वारा जो ट्यूबवेल लगाये गये, उस में से 50 प्रतिशत ट्यूबवेल बन्द पड़े हुए हैं। जो कुएं खोदे गए थे उस में 80 प्रतिशत कुएं बेकार हो गए हैं। जो रहट लगाये गये थे वह 50 प्रतिशत रहट बेकार हो गए हैं। एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नयी नयी जगह पर ट्यूबवेल लगाते हैं और दूसरी तरफ पीछे क्या हो रहा है कि वह ट्यूबवेल बन्द होते जा रहे हैं, वह कुएं बन्द होते जा रहे हैं, वह रहट बन्द होते चले जा रहे हैं। यह तो आज पानी की समस्या की हालत है। दूसरी चीज जो ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में भी आपको गहराई से विचार करना है। आज जगह-जगह हो यह रहा है, मैंने घूम कर देखा है, एक गांव में एक ट्यूबवेल लगा और 50-60-80 फुट के स्ट्रेटा पर लगा दिया गया, उसकी बोरिंग कर दी गई, जाली डाल दी गई। उसके बाद दो-चार किसानों ने उसके पड़ोस में ट्यूबवेल लगाया और नतीजा यह हो रहा है कि वह ट्यूबवेल अब पानी नहीं दे रहा है। किसानों ने पांच-सात दस हजार रुपये लगाए और वह ट्यूबवेल आज पानी नहीं दे रहा है। किसान मारा-मारा फिर रहा है और उसके ऊपर से

उधर तहसील का चपरासी और अमीन डंडा लिए फिर रहा है कि जो तकावी तुम ने ली है वह वापस दो। वह कहां से दे ? तो इस पर भी आप को विचार करना होगा और साथ ही साथ किसानों को बताना होगा कि वह डीप बोरिंग कराएं। नहीं तो नतीजा यह होगा कि एक तरफ आप ट्यूबवेल बनाते चले जाएंगे, जब ट्यूबवेलों की संख्या और बढ़ेगी तो पानी उनको नहीं मिल पाएगा और होगा यह कि वह ट्यूबवेल बन्द हो जायगा।

पानी के बाद खेती के लिए खाद आवश्यक है। दूसरे नम्बर पर खाद आती है। आज उर्वरक का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है। ठीक है आप उर्वरक के लिए काश्तकार को प्रोत्साहित कर रहे हैं पर आज आप देखें, उर्वरक कितना महंगा पड़ रहा है। दूसरी बात—जब हमारे देश में प्रत्येक खेत के लिए पर्याप्त पानी नहीं है तो इस देश के लिए इस मिट्टी के लिए वह उर्वरक कहां तक उपयोगी होगा यह भी सोचने की बात है। आज भले ही उससे आप और फायदा उठा लें पर आगे चल कर के उस से फायदे के वजाय नुकसान होने वाला है क्योंकि यह उर्वरक या ऐसी चीजें जिन का उपयोग विदेशों हुआ वहां वह ठण्डे देश हैं, बहां के लिए वह चीजें ठीक हो सकती हैं। यहां पर भी अगर जाप उनको बढ़ावा देना चाहें तो साथ-साथ पानी और उर्वरक दोनों का तालमेल बैठाइए। आज हो वह रहा है कि उर्वरक के नाम से किसान यह उर्वरक तो खरीदता है लेकिन दूसरीं तरफ कम्पोस्ट खाद बनाने की जो कुछ समय पहले सरकार ने एक योजना बनाई थी जिस के अन्तर्गत ब्लाक का बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, ग्राम सेवक यह गांवों में जा जा कर गड्ढे खुदवाते थे, उन गड्ढों का क्या हुआ। जैसा मैंने बताया आज वह कुएं बन्द हो रहे हैं, वह ट्यूबवेल बन्द हो रहे हैं, वह रहट बन्द हो रहे हैं और उसी प्रकार से आज देहातों में वह गड्ढे बन्द हो रहे हैं। आज देहातों में यह गढे नहीं है वहां आज कम्पोस्ट कोई नहीं बनाता। तो आज आप उर्वरक जो बाहर से मंगा रहे हैं वह उर्वरक मंगाना बन्द कर दीजिये। जितनी उर्वरक हमारे देश में पैदा होती है उसकी खपत अपने देश में करिए और जो आप बाहर से मंगा रहे हैं, उस पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस पैसे को पानी मुहैया करने पर खर्च करें।

दूसरी चीज उर्वरक के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि आज उर्वरक वैसे ही काफी महंगा है। बड़े बड़े काश्तकारों को छोड़ कर आम काश्तकार जो छोटे काश्तकार हैं वह उसको खरीद नहीं पाते क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है। दूसरी चीज यह है कि आज हमारी सरकार ने और हमारे वित्त मंत्री ने दस प्रतिशत उस पर बढ़ौतरी की शंका पैदा कर दी है। इसके मानी यह हैं कि आपने किसान की जेब को झांकना शुरू कर दिया है। दूसरीं चीज बीज के विषय में मैं कहना चाहता हूं। आज बीज अगर हमारे देश में किसानों को अच्छा मिले, वैसे तो आप बीज कुछ तैयार कर रहे हैं और वह किसानों को मिल रहा है लेकिन उन आम किसानों तक वह बीज पहुंचाने का अभी कोई तरीका आपने नहीं निकाला है। वह जो बीज यूनिवर्सिटियों के द्वारा तैयार किया जाता है और कुछ आपने अपने और साधन जुटाए हैं जिनके द्वारा आप बीज का उत्पादन करके काश्तकारों को देते है।इस लिये आज मैं कहना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटी द्वारा तैयार किये गये बीज और आपके संस्थान द्वारा तैयार किये गये बीज में तालमेल बैठाना चाहिये। हो यह रहा है कि सरकार द्वारा पैदा किया गया "शरबती सुनहरा" बीज, जिसका दुनिया भर में नाम है और सरकार की तरफ से भी बड़ा प्रचार किया गया है—मैं पूछना चाहता हूं—क्या पंत नगर यूनीवर्सिटी इस शरबती सुनहरे को प्राथमिकता देती है ? आपको मालूम होगा—शायद वह

[श्री शारदानंद]

नहीं देती है। इस प्रकार का जो आपस में तालमेल नहीं है इस को दूर करना चाहिये, ऐसा न हो कि जो बीज पैदा करते हैं उन में टकराव हो जाय।

आज सरकार नैशनल सीड कारपोरेशन के जरिये से काश्तकारों को बीज देती है, लेकिन जिस समय बीज दिया जाता है, उसी समय एक फार्म पर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं। वह फार्म क्या है ? उस में लिखा होता है कि जितना भी बीज आप पैदा करेंगें, सरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर वह सारे का सारा बीज आपको वापस करना होगा। जब काश्तकार बीज तैयार करता है—मान लीजिये आपका केन्द्र किसी जिले में है और वहां से 100 मील या 200 मील दूर किसान उस बीज को डवेलप कर के पैदा करता है तो आपके कारपोरेशन की तरफ से यह कहा जाता है कि वह बीज आप हमारे केन्द्र पर पहुंचाइये, जहां से आप बीज ले गये हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिससे कि आप जहां पर वह बीज दें, वहीं पर उसको लौटा सके। ऐसी व्यवस्था आपको शीघ्र करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय मैं जिस प्रदेश से आता हूं—उस उत्तर प्रदेश का मुख्य धन्धा—चीनी का है और वहां पर लगभग 71 चीनी की मिलें हैं जो कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अभी शायद कल ही हमारे एक प्रश्न के उत्तर में खाद्य मत्री जी ने बतलाया था कि हमारा उत्पादन 30 लाख टन होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश ही आपको 24 लाख टन चीनी दे सकता है, अगर आप कुछ सही ढंग से काम करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि चीनी के मूल्य में और किसानो को मिलने वाले मूल्य मे तालमेल बैठाना होगा, इस समय इन के भावों में तालमेल नहीं है। जब स्वर्गीय रफी अहमद किदवाई के हाथ में यह डिपार्टमेन्ट था, उस समय उन्होंने कहा था कि जितने मन चीनी की कीमत होगी, उतने मन गन्ने की कीमत होगी—लेकिन यह तालमेल आज नहीं बैठ रहा है आज आपने किसानों को मिल-मालिकों की दया पर छोड़ रखा है और वे मिल-मलिक ऐसे हैं जो आपकी बात भी सुनना नही चाहते हैं। आप किसानों के लिये जो मूल्य तय करते हैं, वह उस वक्त करते हैं जब किसानों की पैदावार तैयार हो जाती है, आपको चाहिये कि आप इस मूल्य को पहले तय करें। उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है ? आप ने तय किया कि गन्ने की कीमत 10 रु० क्विंटल के हिसाब से दी जायेगी, लेकिन मिल मालिक सात, साढ़े सात, आठ रुपये दे रहे है, क्या आप उनसे पूछने की हिम्मत रखते हैं, क्या आप उन को सजा देगें जिन्होने आपके इस कथन की अवेहलना की है—शायद आप ऐसा नहीं कर सकेगें।

एक विशेष चीज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपकी किताब में खेतीहर मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिये कोई उल्लेख नहीं है। मैं आज इस सदन और आपकी मारफत खाद्य मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अब वह समय आ रहा है जब खेतीहर मजदूर, जिनके पास भूमि नहीं है, शान्त नहीं बैठेगा। क्या आप चाहते हैं कि उनका कारवां गावों से होकर प्रदेशों को रौंदता हुआ दिल्ली में आ कर खड़ा हो, तब ही आप उनकी बात सुनेंगे।

श्री जगजीवन राम : ऐसा भी करा दीजिये।

श्री शारदानन्द : हम नहीं करायेंगे तो दूसरे भाई कराने के लिये तुले हुए हैं। आप को चाहिये की उन खेतीहर मजदूरों की समस्याओं को हल करें, वरना शहरों की आबादी बढ़ती

जा रही है, गांव से मजदूर भाग कर शहरों की तरफ आ रहा है और आता जायगा ।

आपके सरकारी फार्मों में जो मजदूर काम करता है, उस को आप निकाई और दूसरे कामों की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आपका नियम ऐसा है कि उन को 6 महीने के बाद हटा दिया जाता है । मेरा निवेदन है कि आप अपने कानून में परिवर्तन कीजिये और इस समय को ज्यादा बढ़ाईये, कम से कम एक साल कीजिये ताकि उन ट्रेन्ड आदमियों को हटाया न जा सके ।

पौष्टिक आहार की हमारे देश में बहुत कमी है । देश की 50 करोड़ आबादी में से 32-33 करोड़ आदमी इस से वंचित रहता है । आपको एक साल से 6 साल तक का बच्चा अधिकांशत: बीमार मिलेगा, इस का कारण यही है कि पौष्टिक आहार की हमारे यहां कमी हो रही है । इस का कारण यह है कि हमारे देहातों में किसानों को पहले दूध, घी और मट्ठा मिलता था जो आज नहीं मिल रहा है । इस का सब से बड़ा कारण यह कि हम देश में गऊवध बन्द नही करते हैं ; आपको चाहिये की आप गऊवध तुरन्त बन्द करें । अगर नहीं बन्द करेंगे तो इस के लिये एक विशाल आन्दोलन होने वाला है, तब ही आप इसको मानेंगे ।

सारे देश में त्राहि त्राहि मची हुई है, एक क्रान्ति की लहर आई हुई है, ऐसे समय में आप किसानों की जेबों को टटोल कर, उस के ऊपर सम्पत्ति कर लगा कर या इस प्रकार का कोई कर लगा कर, खाद के दाम बढ़ा कर, देश की उन्नति कराना चाहते हैं और जैसा कि आपने कहा है कि हम 2 वर्षों के अन्दर आत्मनिर्भर हो जायेंगे, मैं समझता हूं कि यह मृग-मरीचिका के समान होगा ।

श्री भा० दा० देशमुख (औरंगाबाद) ; उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकाबड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे इस डिमांड पर बोलने का अवसर दिया । इस मंत्रालय की मांग को सपोर्ट करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं । हमारे स्वर्गीय नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब इस देश पर सकंट था—यह "नारा बुलन्किया था—"जय जवान"—जय किसान" मैं आज की सरकार से पूछना चाहता हूं, अभी दो साल नहीं हुए, क्या वह इस नारे को भूलने जा रहे हैं ? आज का बजट किसानों के लिये एक चुनोती है और मैं समझता हूं जो बजट हमारे सामने आया है, उसने किसानों के जज्बातों को, उन के रुझान को, उन के दिलो को एक ठेस पहुंचाई है । अगर यही बजट कायम रहा इस पर दोबारा गौर नहीं हुआ तो इस से देश के किसानों के अन्दर बड़ी हलचल पैदा हो जायेगी और मैं समझता हूं कि उस से होनेवाले परिणाम बहुत भयंकर होगें ।

हमारी सरकार की एग्रीकल्चर पालिसी के बारे में कुछ सन्दह दिखाई देता है, आज देश के अन्दर चीनी के बारे में यह कहा जाता है कि हम को गन्ने की पैदावार बढ़ानी है, लेकिन जैसे ही किसान अपनी पैदावार बढ़ाता है, हर साल हमारी नीति में ऐसी तबदीली आ जाती है कि उनको लाल झन्डी दिखलाई देने लगती है । मैं मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात को छोड़िये और किसानों को हरी झन्डी दिखलाइये ताकि वह अपने काम हैं सफल हो सके । आज देश के उन भागों में जहां गन्ने की अच्छी पैदावार हो सकती है, जहां पानी काफी तादाद में हैं, जहां गन्ने में शुगर-कन्टेन्ट 12 परसेन्ट से लेकर 13 परसेन्ट तक मौजूद है :

16.00 hrs.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

श्री मा. दा. देशमुख]

स्पेशलिस्ट्स की टीम्स वहां पर जाती हैं और वे वहां पर गन्ने के कारखानों के प्रपोजल्स को मान लेती है कि वे वहां पर बन सकते हैं, लेकिन दो सालों से उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है । महाराष्ट्र की सरकार ने यहां पर 15 प्रपोजल्स भेज रखे हैं लेकिन हर समय सरकार यही कहती है कि प्लानिंग कमीशन ने यह कहा और कैबिनेट के सामने यह प्रपोजल अभी विचारधीन है । मैं तो कहता हूं कि अगर यही हाल सरकार का रहा तो इस देश के अन्दर चीनी की पैदावार बढ़ने वाली नहीं है । आज कंज्यूमर्स को चार रुपए किलो चीनी खरीदनी पड़ती है । मैं समझता हूं दुनियां के किसी भी मुल्क में इतनी महंगी चीनी नहीं है इसलिए इस तरह से यह मामला हल होने वाला नहीं है । ...(व्यवधान) ... सरकार को चाहिए कि अपनी पालिसी को बदले । में नहीं समझता कि कोआपरेटिव सेक्टर में शुगर फैक्टरीज् लगाने में कौन सी रुकावट है । जब किसान अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेन्ट भी तैयार है तो फ़िरउसके रास्ते में कौन सी रुकावट है? आपसे किसी और किस्म की सहायता भी नहीं मांगी जाती है फिर भी आप लाइसेन्स नहीं देते हैं । आई०एफ०सी० के द्वारा आप जो कर्जा देते थे इसको आपने बन्द कर दिया है । जब किसान अपना सर्माया जमा कर रहा है, कोआप्रेटिव सेक्टर में इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर क्या वजह है कि सरकार को लाइसेन्स देने में हिचकिचाहट होती है? किसान को इस तरह से क्यों मायूस किया जा रहा है ? महाराष्ट्र के एम०पीज० ने और किसानों ने रिप्रेजेन्टेशन किया हुआ है —आप फारेन एक्सचेंज न दीजिए, आई०एफ० सी० का लोन मत दीजिये लेकिन आप लाइसेन्स तो दीजिए । स्टेट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है । वेहतरीन से वेहतरीन चीनी वहां पर पैदा की जा सकती है । बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है । जब तक आप नीति को अपनाये रहेंगे तब तह इस देश में चीनी की कठिनाई दूर होने वाली नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में किसी राज्य विशेष की बात नही करना चाहता, चाहे मद्रास हो या मैसूर ही, जहां पर भी कोआप्रेटिव सेक्टर में फैक्ट्रीज् बन सकती हैं, जहां पर किसान तैयार हो वहां पर सरकार को चाहिए कि उनके प्रपोजल का स्वागत करे और जल्द से जल्द वहां पर लाइसेन्स दे ।

दूसरे इस वजट में आपने वेल्थ टैक्स और डयूटी वढ़ाने की बात की है । अब इस देश का किसान कुछ साइंटिफिक ढंग अपनी खेती में अपनाने लगा था, वह कुछ थोड़ा जागा था और आगे कदम वढ़ा रहा था । लेकिन आप फर्टिलाइजर पर, एलेक्ट्रिक पम्प्स पर डयूटी लगा रहे हैं । मेरा निवेदन यह है कि अगर आपने इस टैक्स और डयूटी को रिवाइज़ नहीं किया तो आने वाले समय में एग्रीकल्चर को बहुत बहुत बड़ी ठेस पहुँचेगी और फिर हुकूमत को पछताना पड़ेगा कि हमने एक गलत कदम उठाया था जिसके कारण उत्पादन नहीं हो सका । यहां पर कहा जाता है कि किसान बड़े बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अगर आप दूसरे मुल्कों से मुकावला करें तो 500 की जगह पर यहां के किसान 5 परन्सेंट ही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं । अब धीरे धीरे यहां का किसान इस टेक्नीक को समझने लगा है । इंटेसिव कल्टीवेशन को अब यहां का किसान भी समझने लगा है । अब अगर आपने उन किसानों को इंकरेज नहीं किया तो वे मायूस हो जाएगे और आप जो कुछ भी करने के लिए सोच रहे है वह पूरा नहीं होगा ।

सरकार की एक कमजोरी और है । आप क्रेडिट फ़ैसिलिटीज् देते हैं, 50 करोड़ रुपया

सारे देश में जो आप बांटते हैं वह उसी प्रकार से बांटे जाते हैं जैसे कि खैरात में बताशे बांटे जाते हैं। किसान के हाथों तक पहुँचने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 9-10 परसेन्ट का इन्ट्रैस्ट देना पड़ता है। किसान को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूं हुकूमत की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का जायजा लिया गया है, इससे मालूम होता है कि हुकूमत ने भी इस बात को महसूस किया है। उन कठिनाइयों को अगर आपने दूर नही किया तो जो बढ़ावा आप किसानों को देना चाहते हैं, वह बढ़ावा उनको मिल नहीं पायेगा।

एक बात मुझे और कहनी है कि इस देश में एक कांस्टैंट एग्रेरियन पालिसी होनी चाहिए। इस मंत्रालय के अन्तर्गत जितना भी अधिक से अधिक खर्चा सरकार कर सकती है वह करना चाहिए। आप राष्ट्रीय आय में 50 प्रतिशत इनकम कृषि से लेते हैं और इसको देने वाले 80 फीसदी लोग देहातों में फैले हुए हैं। दुर्भाग्य से आज उन सब लोगों का कोई आर्गेनाइज्ड क्लास नहीं बन सका है। आज इस देश में किसानों को भी अपनी लावीज़ तैयार करने की जरूरत है जोकि हुकूमत के सामने डटी रहे और अपने मतालिबात को मनवाये; इसके अभाव में आज किसान पीसा जा रहा है। साहूकार और जमीदार के चुंगुल से अगर वह बचा भी तो कुछ ऐसी नीतियों की वजह से वह परेशान है और दुर्भाग्य से जैसी उसकी आवाज बुलन्द होनी चाहिए वह नहीं होती है। बाबूजी के दिल में किसानों और मजदूरों के प्रति जो दर्द है, उसमें मुझे कोई सन्देह नही है लेकिन मैं नहीं समझता कि क्या कठिनाई है जिसके कारण वे अपनी नीति को, अपनी पालिसी को बदल नहीं पाते हैं। एलेक्शन के समय में तो किसानों की जय के नारे लगाये जाते हैं, सारे दल उन किसानों का सहारा लेते हैं लेकिन जब जीत कर यहां एयरकंडीशंड बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें कुछ फर्क पड़ जाता है। उस ठंडे दिमाग को कुछ गर्म करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं बाबूजी मेरी इन भावनाओं से सहमत होंगे। उनके रास्ते में अगर कोई कठिनाइयां हैं तो हम भी बाबूजी के साथ हैं।

एक निवेदन मुझे यह करना है कि चीनी के सम्बन्ध में आपने जो कन्ट्रोल और डी-कन्ट्रोल की पालिसी अख्तियार की है—70 परसेंट कन्ट्रोल और 30 परसेंट डी-कन्ट्रोल—उसके अन्तर्गत देहातों में किसानों को बड़ी कठिनाइयां हैं। किसानों को कन्ट्रोल रेट पर चीनी नहीं मिलती है। यह बड़े खेद की बात है। जो किसान आपको सारी दुनियां की चीजें पैदा करके देता है, जिसके घर से ही चीनी पैदा होती है उसी किसान को कन्ट्रोल रेट पर चीनी नहीं मिलती है। वह चीनी ब्लैकमार्केट में चली जाती है। आपने चीनी के डिस्ट्रीब्यूशन की जो एजेन्सीज बना रखी हैं, उसके सम्बन्ध में इस समय बहस नहीं करना चाहता। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप चीनी के कलर में कोई चेंज कर दीजिए ताकि यह मालूम हो सके कि यह चीनी कन्ट्रोल की है और यह चीनी डी-कन्ट्रोल की है। आज शहरों के लोग कन्ट्रोल की चीनी खाते हैं लेकिन जो देहात के लोग हैं उनको चीनी नसीब ही नहीं होती। यह वास्तव में बड़े दुख की बात है।

अन्त में मुझे एक बात और कहनी है। आपने एग्रीकल्चरल एम्प्लीमेन्ट्स, स्पेयर पार्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्टस पर टैक्स बढ़ाया है इसके कारण जरई पैदाबार में कमी आयेगी। आज किसानों को आप रीजनेबिल प्राइस के नाम पर जो दे रहे हैं उसका अगर जायजा नहीं लेंगे और किसान को इसी तरह से दबाया गया तो किसान और मक्रूज हो चलेते जाएंगे। गांवों का जो नक्शा पहले था उसमें आज भी

[श्री भा० दा० देशमुख]

कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। आज भी 80 फीसदी किसानों के पास पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। वे किसान आज भी ज्यों के त्यों नजर आ रहे हैं। आप उनकी तरफ भी खास ध्यान दीजिए। उनकी जरूरत के जो भी सामान हों, लोहा, सीमेन्ट, स्पेयर पार्ट्स, इंजिन के लिए पेट्रोकेमिकल्स, उन सारी चीजों को कन्ट्रोल रेट पर उसके घर पहुंचाइये। इसके अलावा कास्ट आफ प्रोडक्शन वर्क आऊट करके सही दाम दीजिए। इस समय इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (वागपत): श्रीमान् पिछले दो वर्षों से हमारे देश में खाद्यान का उत्पादन बढ़ा है, यह सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है परन्तु मुझे साथ ही साथ यह भी कहना पड़ता है कि यह संतोष का बिषय नहीं है। सन 1968-69 में जैसा कि हम समझ रहे हैं कि रिकर्ड उत्पादन किया है लेकिन उसके बाद भी हमें बाहर से 56 लाख टन आनाज मंगाना पड़ा जिसकी कीमत हमको 361 करोड़ रुपए देनी पड़ी। इसी प्रकार से 200 करोड़ का उर्वरक हमको बाहर से मंगाना पड़ा। तो देश की यह स्थिति अच्छी नहीं है। परन्तु हमारे वैज्ञानिक जोकि प्रयोगशालाओं में मेहनत कर रहे हैं, अधिक उपज देने वाले बीज की नयी नयी किस्में तैयार कर रहे हैं। उसके लिये वे वास्तव में वधाई के पात्र हैं। और उन का परिश्रम प्रशंसनीय है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा किसान जिसे आमतौर से अशिक्षित समझा जाता है, लकीर का फकीर समझा जाता है वह किसान आज उत्सुक है विज्ञान की नई उपलब्धियों का स्वागत करने के लिये, इन नये बीजों को लेने के लिये। अगर आप उस को वीक भाव पर नहीं देते तो वह तिगुने, चौगुने दाम पर खरीद कर ले जाता है और बोता है। परन्तु उस की वास्तविक कठिनाई क्या है? वह यह है कि किसान के आस पास जो सरकार है, जिस को किसान सरकार समझता है, वह सरकार किसान को सहयोग नहीं देती, बल्कि उल्टे बाधायें पहुंचाती हैं। वह क्या? किसान के आस पास का महकमा माल महकमा है, नहर बिजली का महकमा है, थाना है, गन्ने का महकमा है। जितने भी यह सारे के सारे महकमें हैं उन सब का बुरा हाल है। हम कहते हैं कि देश में हरियाली क्रान्ति हो रही है, ग्रीन रिवोल्यूशन हो रहा है और वह अपनी हरी झंडी दिखा रहा है इस का स्वागत वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, हमारा मंत्रालय भी कर रहा है, इस हरी झंडी का स्वागत किसान भी कर रहे हैं, लेकिन मालूम पड़ता है कि इस हरी झंडी को अभी तक आप के जो सरकारी विभाग हैं, जिन से किसान का वास्ता पड़ता है, वह हरी झंडी को नहीं देख पा रहे हैं। और जब तक यह विभाग जिनका वर्णन मैंने ऊपर किया है हरी झंडी को नही देखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अगर वह अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो नतीजा यह हो सकता है कि जो लोग हरी झंडी को देखकर अपना दिमाग नहीं बदलेंगे तो इनका दिमाग लाल झंडी से बदलना पड़ेगा। अब एक ही बात, हरी झंडी से दिमाग बदल सकते हैं या लाल झंडी की प्रतीक्षा करनी है। तो मेरा निवेदन है कि जब ये सरकारी महकमे, जो किसान के साथ सहानुभूति नहीं करते, रिश्वत लेते हैं, जब तक यह सारी मशीनरी ठीक नहीं होती है तब तक आप आशा नहीं कर सकते हैं कि जो आप चाहते हैं उसके अनुकूल फल मिल सके।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गन्ने में दो बीमारियां लगी—एक बीमारी पायरीला कीड़ा और दूसरी रैड रौट। मैंने अपने मंत्रालय के मंत्री श्री शिन्दे साहब को लिखा, वैसे तो मैं

आशा करता था कि सरकार का कोई विभाग होना चाहिये जो यह देखे कि इतने लाख एकड़ में बीमारी फैल रही है और वह खुद रिपोर्ट करे, लेकिन जब मैंने शिन्दे साहब को लिखा तो उन्होंने उस पर तुरन्त ध्यान दिया और वैज्ञानिक भेजे। मैं भी गया। उन वैज्ञानिकों ने घूम फिर कर यह देखा इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, उसके पीछे क्या हुआ मुझे आज तक पता नहीं चला, और वह रिपोर्ट कहां गयी इसका कोई पता नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि सरकार की तरफ़ से कोई काम करने के लिये शुरूवात भी होती है तो वह इस कागजी घुड़ दौड़ में और ब्यूरोक्रेसी में फंस कर रह जाता है। पता तो यहां तक चला कि उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी थे उन्होंने केन्द्र के अधिकारियों को यह कहा कि यह क्षेत्र तो हमारा था, तुम वहां कैसे पहुंचे? तो राज्य और केन्द्र की खींचातानी में यह मामले अटके रह जाते हैं। इसलिए खाद्य मंत्रालय के मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि ऐसे मामलों में वह राज्य सरकारों की जिस तरह से भी हो सके उनको समझा बुझा कर उनका सहयोग लेकर किसानों की जो कठिनाइयां हैं उनको हल करने के लिये वह कोई न कोई क्रियात्मक रूप से ध्यान दें और हल निकालने के लिये उन की सहायता करें।

यह ठीक है कि पहले साल 10 लाख नाइट्रोजन का खर्च था और इस साल 14 लाख चाहिये। लेकिन किसान को खाद जो मिल रही है वह ब्लैक मार्केट में मिल रही है। मैंने मंत्रालय को पिछले वर्ष लिखा था कि मेरे कस्बे में 20, 30 दुकानी पर नमक मिली हुई खाद खुले रूप में बिक रही है जिससे खेती को बड़ा नुकसान होता है। मंत्री जी ने लिखा कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है। पता चला उत्तर प्रदेश सरकार के आफ़िसर हापुड़ आये और खबर वड़ौत तक हो गयी। परिणामस्वरूप रातों रात वह नमक मिली हुई खाद गायब हो गयी। जैसे दिल्ली में स्क्वैड आता है पटरियों पर बैठने वालों को पकड़ने के लिए और लोग उसको देखकर आगे-आगे भागते हैं और जब गाड़ी गुजर जाती है तो फिर लोग बैठ जाते हैं, बिल्कुल यही हाल हो रहा है। इसके लिए आप को कोई स्थायी मशीनरी लानी होगी। इससे बड़ा क्या अनर्थ हो सकता है कि उर्वरक खेत में जाय और उपज बढ़े वह न होकर नमक मिली हुई खाद जा रही हैं जिससे खेती बरबाद हो रही है। तो इस तरह से जो किसान के साथ व्यवहार होता है उसको रोकने के लिये मंत्री महोदय ध्यान दें और कोई स्थायी मशीनरी बनानी चाहिये जो किसानों की कठिनाइयों को अनुभव करके उन को दूर करने की कोशिश करे।

सिंचाई के बारे में सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 76 हजार निजी नलकूप बने और दो हजार सरकारी नलकूप बने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप जरा यह भी रिपोर्ट लिया करें जितने नलकूप हैं उनमें से चालू कितने हैं। मुझे अपनी नहर की कहानी बताने दीजिये। मेरे यहां पूर्वी यमुना नहर है। इस साल आठ आठ हफ़्ते से पहले नहर नहीं आयी, पानी किसान को मिलता नहीं है, इसी तरह से कुओं के लिए बिजली नहीं है तो किसान क्या पैदा करे? आप यहां बैठे बैठे हिसाब लगा देते हैं कि हमने इतने हाई ईल्डिंग बैरायटी के बीज भेज दिये हैं, और आठ, आठ हफ़्ते नहर नहीं चलती, बिजली कुओं को मिलती नहीं है तो किसान क्या करे। सिवाय अपने भाग्य को रोये और प्रबन्ध कर्ताओं को रोये।

इस देश के 82 फ़ीसदी आदमी गांवों में बसते हैं और यदि कारखानों का उत्पादन

[श्री रघुबीर सिंह शास्त्री]

निकालना है तो उसके लिए आप को इस देश के 82 फ़ीसदी आदमियों फी क्रय शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। और वह तभी बढ़ेगी जब किसान को उसकी चीज़ का उचित दाम मिलेगा। आप कहते हैं कि किसान ज्यादा पैदा करे, वह भी करता है और उस को देचने के लिए दूर-दूर तक मंडियों में ले जाता है लेकिन उसको अपने उत्पादन का नाम कम मिलता है जिससे उसके उत्साह को ठेस लगती है। उपज बढ़ाने का तभी लाभ है जब उस को अपनो उपज का उचित दाम मिले।

फारमर्स फोरम ने कृषि मूल्य आयोग का सुझाव भेजे, उन को मानना तो दूर, उस ने यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की कि आप जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उस रिपोर्ट में फारमर्स फोरम के सुझाव रख दीजिये। कृषि मूल्य आयोग के बारे में हम ने कहा कि किसान का विश्वास उस पर तब तक पैदा नहीं होगा जब तक कृषि मूल्य आयोग में किसानों के प्रतिनिधि नहीं बैठेंगे। आयोग के सदस्य कितने ही विद्वान क्यों न हों लेकिन वे किसान की समस्याओं को कहां तक समझते हैं जब तक ऐसे लोग उस आयोग में नहीं होंगे तब तक आप आशा नहीं कर सकते कि किसान के हृदय में कृषि मूल्य आयोग के बारे में विश्वास पैदा होगा कि वह उनकी समस्याओं का समझ कर मूल्य नियत करेगा।

हमारे यहां फरवरी में चुनाव होने के बाद कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस सरकार बनने का सबसे पहला उपहार यह मिला कि जो मिल मालिक साढ़े नौ रुपया गन्ने का दाम दे रहा था। जिस दिन यह एलान हुआ कि कांग्रेस सरकार बनेगी उसी दिन मिल मालिकों ने साढ़े सात रुपया दामकर दिया। हम समझते हैं कि अगर दूसरी सरकार बनती तो जिस दिन वह सुनते उसी दिन 2 रुपया भाव बढ़ा देते। लेकिनजिस दिन से कांग्रेस सरकार बनी दो रुपया भाव कम कर दिया। हमारे खाद्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, 9 दिसम्बर को उन्हों ने यहां कहा कि मैं चाहता हूं कि 10 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए। हम ने भी ढिंढोरा पीटा कि खाद्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया, चुनाव सभाओं में भी सब जगह कहा कि 10 रुपये से कम नहीं देने देंगे। लेकिन जैसे ही इलैक्शन खत्म हो गया खाद्य मंत्री की हमें चिट्ठी आ गई कि मेरा वह आश्वासन नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि हम मिलों को मरने नहीं देंगे। अच्छा है चलने दीजिए और किसानों को मिलों की मशीनों में दे दीजिए। जब तक आप का ऐसा नियत्रंण नहीं होगा किसान का भाव आप ठीक तय करें तब तक उस में उपज बढ़ाने की भावना पैदा नहीं हो सकती।

इस के अतिरिक्त मुझे कृषि शिक्षा के बारे में भी कहना है। जब वैज्ञानिक खोज बढ़ रही है, खेतों में विज्ञान पहुंच रहा है तो यह आवश्यक हो गया हैं कि देश में कृषि शिक्षा का सुधार होना चाहिए और वह वैज्ञानिक होना चाहिए। हमारे देश में 8 विश्वविद्यालय है कृषि के और 60 कृषि महाविद्यालय हैं जिन में से पांच हजार के करीब सालाना ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं। लेकिन इन पांच हजार को सिवाये इसके कि कहीं नौकरी पर लगा लें, बेचारे और कुछ नहीं कर सकते।अगर इन पांच हजार के ज्ञान के स्तर की आप बात करें तो वह इतना नीचा है, इतना गिरा हुआ है कि वह बेचारे कुछ जानते ही नहीं। आप समझते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हो कर आये हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता है। इस लिए मेरा कहना यह है और गत वर्ष भी मैंने कहा था कि आप को उन के स्तर को उठाना चाहिए। इसको करने का एक तरीका यही है कि आप के जितने कृषि शिक्षा के कालिज हैं उन के ऊपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सीधा नियन्त्रण होना

चाहिए। यह जो आपकी साइंटिफिक एग्रीकल्चुरल कौंसिल है, इस का पूर्ण नियन्त्रण रहना चाहिए। जब इस का नियन्त्रण सारे कृषि के कालिज और कृषि विश्वविद्यालयों के ऊपर होगा तब आप आशा कर सकते हैं कि उस में कुछ सुधार होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे।

अगली मूल बात यह है कि हम रोज जिक्र करते हैं कि देश में कृषि का उद्योग बना रहे हैं, देश में कृषि को व्यवसाय बना रहे हैं। अगर हमें कृषि उद्योग बनाना है कृषि व्यवसाय बनाना है, तो हम को यह इम्प्रेशन देना चाहिए कि हम वस्तुतः ऐसा करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जब एक फैक्टरी खोलने की बात होती है तो सर्वे होता है, सड़कें बनती हैं और सारी नागरिक सुविधाएं वहां पहुंचाई जाती हैं। कृषि उद्योग बनाना चाहते हैं तो गांव-गांव में सड़कें बनानी चाहिए, हर गांव में नागरिक सुविधाएं पहुंचाई जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों में यह इम्प्रेशन हो कि आप कृषि को उद्योग बना रहे हैं। जहां 82 प्रतिशत इस देश के आदमी गांवों में रहते हैं। उन के लिये ये आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई जायं। जो सुविधाएं आप नये उद्योग धन्धों में देते हैं वही कृषि के लिए भी करें तो सही माइनों में यह कहा जायगा कि आप कृषि उद्योग बना रहे हैं और उसका विकास करना चाहते हैं।

इसी तरह से अब मैं एक और विषय पर आना चाहता हू। मैं समझता हूं कि बहुत से मेम्बरों ने उसका जिक्र तक नही किया और वह यह है कि आप का मंत्रालय जो है वह सामुदाहिक विकास मंत्रालय भी है, पंचायत राज से भी आपका वासता है। यह मैं कहना चाहता हूं कि आप ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस देश में साढ़े पांच लाख गांव हैं, जिन में 2 लाख 14 हजार पंचायतें हैं। 98 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जोकि पंचायतों के अन्तर्गत हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वे गांव जाकर देखें, वे भी गांव के हैं, उनका भी अनुभव है और मेरा अपना अनुभव है, तो पायेंगे कि पंचायतों का सारा संगठन थोथा हैं और इतना बेकार है कि उन गांवों में दलबन्दी हो रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। कोई भी अच्छा काम पंचायतें नहीं करती हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। उदाहरण के लिए मेरा मेरठ जिला है और उस जिले की आबादी 27 लाख की है। उसके नजदीक ही मुजफ्फरपगर का जिला है। कई हजार पंचायतें वहां पर होंगी। ममूने के तौर पर सिर्फ एक बात से आप जांच लेंगे। शायद ही किसी पंचायत की कभी कोई नियमित बैठक होती हो। पंचायत का एक प्रधान है और जो जमीन गांव पचायत की होती है, तो एक एक प्रधान ने एक एक साल में लाखों रुपया जमीन बेच कर इकट्ठा कर लिया है और सारी गांव भी जमीन बेच दी है। इस लिए मेरा कहना है कि यदि गांव पंचायतों का ढर्रा इसी प्रकार चलता रहा, तो दल बंदी बढ़ती रहेगी, ईर्ष्या द्वेष बढ़ता रहेगा और भ्रटाचार बढ़ता रहेगा। इन कारणों से गांव पंचायतें बिल्कुल असफल हो रही हैं। वे असफल हो रही हैं लेकिन फिर भी चल रही हैं। इस लिए मेरा निवेदन है और वह यह है कि जितने भी विचारशील लोग हैं और जो पंचायतों की समस्याओं को समझते हैं, उन्हें बिठलाकर पंचायतों के चुनाव तथा वित्तीय व्यवस्था में सुधार के उपाय सोचें। और लो वहां पर गड़बड़ है उसको दूर करे, जिससे गांव पंचायतों में से यह अनैतिकता, यह भ्रष्टाचार और यह जो दलबन्दी है दूर हो। जिन्होंने गांव के जीवन को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है और विषाक्त कर दिया है, इनसे गांवों को छुटकारा मिल सके। या तो आप गांव पंचायतों में सुधार करें या इस प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

दें। मैं आप को धन्यवाद देता हूँ कि आप ने मुझे समय दिया।

MR. CHAIRMAN : Shri G. S. Mishra.

श्री अहमद आगा (वारामूला) : सभापति महोदय, यह इतिफाक है कि मुल्क ने जरई-तरक्की की है।

MR. CHAIRMAN : I am sorry ; I have called Shri G. S. Mishra.

श्री गा० शं० मिश्र (छिन्दबाड़ा) : सभापति महोदय, मैं कृषि मन्त्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ।

कई वर्षों पहले गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान को सच्चे रूप में यदि देखना हो तो यहां के 7 लाख गांवों में उसके दर्शन कीजिए। हम लोगों ने इन बीस वर्षों में देहातों को भुला दिया। पिछली जितनी भी योजनाएं बनी उन में कृषि की आवश्यकताओं की हमें जिस क़दर प्राथमिकता देनी चाहिए थी नहीं दी और उस का परिणाम यह है कि आज शहरों में जिस प्रकार से तरक्की हुई है, उनकी तुलना में देहातों में वह तरक्की नही हुई।

कृषि की मूल आवश्यकताएं सात होती हैं। पहली है कृषि की जुताई। इसके लिए आज हमारे देश में बैलों का ही साधन है। बैलों कीं जितनी कीमत बढ़ी हुई है, बैलों की खुराक की जितनी कीमत बढ़ी हुई है, उनके चारे, उनकी कार्यक्षमता, उनका कार्य काल और उन पर लगने वाले आदमियों का खर्चा, इन सब चीजों को हम जोड़ते हैं तब यह देखते हैं कि बैलों से खेती करना आज अलाभकारी हो गया है। ऐसी स्थिति में हम को ट्रैक्टर्स और उनसे चलने वाले यंत्रों की आवश्यकता हो गई है। लेकिन हम यह देखते हैं कि ट्रैक्टरों की कीमतें हिन्दुस्तान में और देशों की अपेक्षा दुगने से भी अधिक है। इसके बावजूद वे उपलब्ध नहीं होते हैं।

फिर दूसरी वस्तु जो हमको खेती के लिए अत्यावश्यक होती है वह है बीज। जहां तक बीज का सवाल है, इन चन्द वर्षों में हमारे नौजवान कृषि शास्त्र के वैज्ञानिकों ने जो प्रगति की है, उसके लिए वे और हमारे मन्त्रीगण धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन बीजों के द्वारा हमने एक चमत्कार कर दिखाया है, अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। मेरा यह सुझाव है कि हमारे जो वैज्ञानिक इन शोध कार्यों में लगे हुए है, उनको इसका कुछ पुरस्कार मिलना चाहिये, उनकी तंख्वाहें बढ़ाई जानी चाहिए, उनको भी इंसेंटिव देने चाहिएं।

तीसरी वस्तु जो हतारी खेती के लिए आवश्यक होती है वह हैं सिंचाई। जहां तक सिचांई का सवाल है, सिचांई की व्यवस्था प्रत्येक गांव को उपलब्ध करना इमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। सिचांई के बगैर खेती करना जुआ खेलने के बराबर है। यह गांधी ने अनेक वर्षों पहले कहा था। इस सीख को कितना हमने अपनाया, यह देखने की बात है। आजादी के पहले 56 करोड़ एकड़ में सिचाई होती थी। आजादी के उपरान्त 35 करोड़ एकड़ में और सिंचाई की है। इस 91 करोड़ एकड़ में 3/5 सिंचाई है जो तालाबों और कुओं से होती है। जिस समय हमारे देश में वर्षा नहीं होती है उस समय अधिकांश कुएं और तालाब, जोकि हमारी सिंचाई के साधन हैं, सूख जाते हैं। अत : आज भी खेती मूल रूप से किसानो के पसीने और भगवान के पानी की साझीदारी में चल रही है और हम जुए के समान अपनी खेती को पाते हैं। इसमें भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट में आबपाशी का औसत 7 और 8 प्रतिशत है। इससे बड़ा दुभार्गय हमारा क्या हो सकता है।

जहां तक बिजली का सवाल है, जहां कुएं हैं, वहां पर बिजली ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ज्यादा अच्छे तरीके से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं सिंचाई के लिए। देश में जितनी बिजली तैयार होती है, उसका 7 प्रतिशत ही कृषि को उपलब्ध है और 93 प्रतिशत शहरों आदि को। फिर उद्योगों की तुलना में सिंचाई के लिए मिलने वाली बिजली की प्रति यूनिट कीमत आठ गुना तक ली जाती है। लाखों किसान बिजली चाहते हैं सिंचाई की उपज बढ़ाने के लिए, लेकिन वंचित रहते हैं।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश जो रकवे में और खास कर काश्तकारी रकवे में यू० पी० के बाद दूसरे नम्बर पर आता है, वहां दो प्रतिशत देहातों का विद्युतीकरण हुआ है।

तीसरी चीज है उर्वरक। उर्वरक की यह हालत है कि जहां प्रति एकड़ 400 पौंड नाइट्रोजन हम को चाहिए, हम अपने सब साधनों से नाइट्रोजन का यदी उपयोग करें तो 17 पौंड से ज्यादा हम नहीं दे सकते। ऐसी हालत में हम उर्वरकों से भी बंचित हैं। इन बीस वर्षों की यह बड़ी दुखदपूर्ण कहानी है। चौथी चीज होती है फसल की रक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन, क्राप प्रोटेक्शन। कीटनाशकों की भी उर्वरकों जैसी हालत है। भविष्य में उनकी उपलब्धि भी एक गम्भीर समस्या बन कर हमारे सामने आयेगी।

इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कीमतें। हमेशा हमारे प्लांनिग कमीशन ने और कांग्रेस पार्टी ने मैनिफैस्टो में इलैक्शन के पहले यह कहा है कि किसानों को इंसेंटिव प्राइस दी जाय। आज कृषि मंत्रालय यह महसूस करता है कि हमारे पास किसानों की लागत का तखमीना करने के लिए कोई भी साधन नहीं हैं। मेरे ही एक प्रशन के उत्तर में इन्होंने इस तरह का जवाब दिया था और हमें यह कहते हैं कि जब हम कीमतें तय करते हैं, प्रोक्योरमेन्ट प्राइम तय करते हैं तब हम इन्सेन्टिव का ख्याल रखते हैं। यह कैसे हो जाता है। यह कैसा जाल है। यह हमारी समझ में नहीं आता। हम मान लेते हैं कि वह कुछ करते हैं। होता यह है कि जो कीमतें ये तय तय करते हैं, वे हमारी लागत पर निर्भर नहीं करती हैं। जो व्यापारी का माल होता है वह जितनी मर्तवा उसको लेता है, बेचता है, उतनी दफा उसको रोलिंग करता है और मुनाफा लेता है। खेती में जो फसल आने के समय ही एक या दो बार किसान अपनी फसल को बेचता है उस पर मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है तो उसे घाटे में अपनी मेहनत को बेचना पड़ता है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि किसान आज दरिद्र हो रहा है, कर्जदार होता चला जा रहा है।

मूल्य निर्धारण के लिए जो कमीशन आपने बनाया है उस केमीशन में उपभोक्ता मात्र है, जितने आफिसर्स हैं, वे भी उपभोक्ता हैं कोई भी प्रौड्यूसर नहीं है। वह जानते नहीं कि प्रोड्यूसर की क्या तकलीफें हैं, किस तरह से खेती के उत्पादन के लिए लागत लगती है, उसका किस तरह अन्दाजा लिया जाए। जब उपभोक्ता हमारी कीमतें तय करेंगे तो उसका उद्देश्य यह होता है कि कृषि के उत्पादन की खासकर खाद्यान्न की कीमतें न बढ़ने पायें। तो यह जब उद्देश्य है तो कम से कम हम आपसे यह उम्मीद करना चाहते हैं कि हमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको आप हमारे लिये उपलब्ध करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उपज प्रति एकड़ में पैदा कर सकें और इस तरह से हम अपने कृषि के उत्पादन में कास्ट प्राइस कम कर सकें। एक बात और भी देखिये कि कीमतें तय करने में किस प्रकार भेदभाव रखा जाता है। पिछले वर्ष हम लोगों ने कपास की कीमतें बढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न किया था। उसके परिणामस्वरूप बहुत थोड़ी कीमतें बढ़ाई गईं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले कितने वर्षों में कपास की कीमतें किस प्रकार बढ़ाई गई और पिछले वर्षो में किस प्रकार से कपड़े की कीमतें किस कद्र बढ़ीं। यदि ये आंकड़े मिल जायें तो उससे पता लग जायेगा कि हमारे साथ और इंडस्ट्रियल होल्डिंग के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है।

[श्री गा० शं० मिश्र]

सही मायनों में जब तक अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनें, ट्रैक्टर, खाद, सिंचाई बिजली आदि मुहैया नहीं किये जाते तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा और यह नहीं होगा कास्ट आफ़ प्रोडक्शन कम नहीं होगी और जब तक आपका कमीशन किसानों को मुनाफ़ा सही मायनों में देने के बजाय उपभोगता को सस्ती कीमत पर देने के लिए किसान के उत्पादन का मूल्य लागत से नीचे निर्धारित करेगा तब तक किसान को घाटा सहना पड़ेगा। आज भी वही हालत है जो स्वतंत्रता पूर्व थी। मैं फिर गांधी जी के शब्दो को दोहराता हूं :

But the town dwellers have believed that India is to be found in its towns and villages were created to minister their needs.

उन्होने आगे कहा :

I have found that the town dweller has generally exploited the villages. In fact he has lived on poor villager' subsistence.

श्रीमानु, दरअसल में हमारी हालत तो यह है कि कुएं से निकला पानी खेत नही पहुंच रहा—पानी ले जाने वाली नाली हीं पानी सोख जाती है। यहां जो चीज हुई यह शहरों में ही ले गये। देहाती कर्जदार ही बना रहा। इसके बाद भी आप देखिये कि भारतीय किसान निर्यात व्यापार में 54 प्रतिशत का और राष्ट्रीय आय में 51 प्रतिशत का भागीदार है। उसे आवश्यक साधन दीजिए। वह कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन उपभोक्ता को, व्हापारी को, उद्योग को निर्यात के लिए देगा। उसकी तरक्की ही देश की तरक्की है।

मैं चन्द बातें सहकारिता पर भी कहना आवश्यक समझता हूँ। महाराष्ट्र में किसान जो गन्ना पैदा करता है वह खुद कोआपरेटिव शुगर मिल्स चला रहा है और कुछ नई मिलें चलाना चाहता है। श्रीमान, ये महाराष्ट्र की शुगर मिलें श्री रफी अहमद किदवई साहब की याद ताजा करती है। जब उनके समय में शक्कर की तंगी आई थी, उस समय शुगर मिल्स का विस्तार किया गया। वे बड़ी आशा बांध कर इन मिलों का जिक्र करते थे। लेकिन आज नई कोआपरेटिव शुगर मिल्स के लिए आपके यहां से आज्ञा नहीं दी जा रही है। महराष्ट्र के मुख्य मन्त्रीश्री वसन्तराव जी नायक—जो मूलतः एक किसान हैं— इस कार्य के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन यहां किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। गन्ने की खेती में इस तरक्की को जिसे महाराष्ट्र के किसान ने कर के दिखा दिया, उसके बाद भी आज हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में गन्ने की प्रति एकड़ उपज संसार के सब से अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले हवाई द्वीप की अपेक्षा कम नहीं है। जहां तक शुगर कंटेन्ट का सवाल है वह संसार के रिकार्ड से अधिक आता है। महाराष्ट्र में प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन 40 से 50 टन होता है और शक्कर का उत्पादन 6 से 7 टन तक है जब कि देश के अन्य भागों में प्रति एकड़ शक्कर का उत्पादन 1.5 टन ही है। एक सीधी सी बात है कि शुगर की कमी है हमारी खुद की आवश्यकताओं के लिए और निर्यात के लिए। फिर भी हम नई शुगर मिलें जहां अधिक उत्पादन हो सकता है प्रति एकड़ के हिसाब से, वहां बनने नही दे रहे हैं। वह किसान खुद अपनी मेहनत से, अपने लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाना चाहता है जिस से और भी लाभ उठायेंगे, उस पर भी उसको देने के लिए यदि इतनी देर की जा रही है तो यह बड़े खेद की बात है। इसके ऊपर जब टैक्स लगाने की बात हो रही है तो हम नहीं समझ पाते कि क्या करें। सोचना चाहिए कि जो अग्रिकल्चरल इकानामी आज इस तरह से पिलड़ी हुई है, गिरी हुई है, उसको बढ़ाने के लिए इन्सेटिव दिया जाए या उस पर और करों का बोझ लाद कर उसे और बढ़ाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपने मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ और कृषि विभाग की इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

SHRI JYOTIRMOY BASU : (Diamond Harbour) Sir, this Government's this Food Minister's tall claim of self sufficiency in foodgrains by 1970 and also their claim of 'Green Revolution' has turned out to a be false and it is nothing but a 'Red Revolution.' That is what they have done. It is more or less a green revolution, but it is a green signal for perpetual shortage and starvation. There has been no growth on last year's production. It is based on their own Food Ministry's report. It is said in today's *Economic Times* that this year's food output will be no more than 94 million tonnes which is two million tonnes less than last year. It also says that the Ministry's admission that foodgrains production for 1968-69 would be around last year's level clearly means that its earlier estimate of 98 million tonnes was based on its unfounded optimism rather than on hard facts. So, you have been pulling fast on all of us.

Now about targets. They said that by the end of the Third Plan they would produce 100 million tons of food and three years have passed, but the fulfilment is still far below. The *per capita* availability in 1968 was about 456 gms. per day. That is exactly the same what it was in 1954, namely, 16.10 oz.

There are some minor achievements here and there. But agriculture in this country and food production in this country are stil very much subject to the vagaries of nature. They have not been able to change that position.

PL-480—I was going to say PL-420 -, in these fifteen years of time has brought foodstuff worth Rs. 2,122 crores and that almost amounts to, if I am not very much wrong, 420 per head...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : I hope his Government will not accept P-480.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I will tell you that. These 2,122 crores are being used extensively for infiltration of Americanism into this country.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : In his West Bengal Ministers are on strike. Being a Communist, how can you participate in today's discussion...

MR. CHAIRMAN : Order, order.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Mr. Chairman, if you advise him to listen to me patiently, I shall be very willing to meet his queries.

As I have said just now, these 2,122 crores have been planted into this country by blackmailing this county and several U.S. Missions have been forced into this country. Today this money is finding its way into every sphere of our life through foreign missionaries. Go to Delhi University and have a look at that bcook they have written on the American Politics in education in our countty. All this money is coming from PL. 480.

The crisis has deepened. During the Second Five Year Plan period, they imported food worth Rs. 544 crores and 81 lakhs. They improved on that because during the Third Five Year Plan period they imported food worth Rs. 853.22 crores. After that, in these last three years alone, they imported food worth Rs. 729 crores. So, Shri Jagjiwan Ram and his Government have made this country a perpetual begger and a laughing stock of the rest of the world. I have said very little about the entire problem. I have now to deal with my State.

I am talking about West Bengal and Assam. Why Assam ? West Bengal has been marked as a red zone and Assam as a yellow zone. So, the policy should be the same to both the States.

[Shri Jyotirmoy Basu]

The average annual compound rate of growth in percentage terms in all India for all foodgrains is 2.50 ; for Punjab 3.66 for West Bengal 1.14 and for Assam 76. It is a wonderful performance.

Now we come to the annual growth of yield rate per acre between 1952-53 and 1964-65. The figure for all India for all foodgrains is 1.51 ; for Gujarat, Shri Desai had been leading that State, 4.64. West Bengal 0·88 and Assam ·52 There is no politics in foodgrains. There is no improvement in production of cereal as well and they are not willing to draw up a national food budget because they will not be able to do much politics in foodgrains. The position has not improved. Thecereal production in some States is as follows :

West Bengal	1964-65	5853.8
,,	1967-68	5389.3
Kerala	1964-65	1132.6
,,	1967-68	1115.9

So you have done very little—nothing more than that. So, the net result, after taking the population growth into consideration, is that the foodgrains production has gone down in West Bengal. In 1964-65 62.60 lakhs metric tonnes of food-stuff was produced but in 1967-68, it came down to 58.59 lakhs metric tonnes. All-India production has gone up by 6%. In West Bengal, it has gone down.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Now you have got United Front Government in West Bengal.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I am talking of All-India production. So, Mr. Naidu you have to better your knowledge. The rice production in 1964-65 in West Bengal was 57 lakhs and 51 thousand metric tonnes but in 1967-68 it came down to 51 lakhs 98 thousand metric tonnes.

Now I shall come to Irrigation form food. Irrigation in West Bengal is on 26,000 acres of cultivable land. In reply to Q. No. 3367 Unstarred Question—it was stated that 4378 shallow tube-wells were sunk of which only 4054 were in working condition. But, as the Government says, only 3221 wells were in actual working condition white 423 wells were out of order.

As regards minor irrigation, there is no politics with West Bengal. The existing canals have been neglected and no de-silting has been done. Regarding the loans advanced by the Land Mortage Banks, Agricultural Re-Finance Corporation, the Central Cooperative Banks, Agricultural Agro-in dustries Corporation to various State between 1966—69 for minor irrigation amounted to Rs. 258-72 crores. Let us see how this amount had been distributed to various States. They are as follows:—

	(in crores of rupees)
Maharashtra	64.74
Gujarat	40.12
Assam	0.40
West Bengal.	Nil.

You do not want to do politics with Food. Not a single tube well irrigates our land in West Bengal. They do not want to do that. I have seen the Ministers many a time ; I have seen the Chairman of the Planning Commission. They do not want to do it because the people will have enough to eat. They will try to throw them out more vigorously.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : But many of the cooperatives are within the jurisdiction of the State Govenment.

SHRI JYOTIRMOY BASU : You say that when you reply. We had a lot of jute cultivation and we have been earning money by way of foreign exchange. But what have you done with regard to food ? You were morally obliged to compensate on that account. When Mr. Sen was dominating as the Congress Chieftain, they gave them 16,050 tonnes of foodgrains. Am I right to say this ? But, when the United Front Government came into power, it was reduced by 30%. The moment that *shikandi* Government in collabaration with the Congress came, Shri Prafulla Chandra Ghosh, that Quisling required more food and the Centre rushed

about the same figure as they gave in 1956. They do not any politics in food.

I will now come to sugar distribution. They are doing the same thing here also. They have reduced our quota. Though this is slightly outside the subject, there is a rumour about the purchase of de-controlled sugar. I want to know whether there is any truth in the claim by mill-owners that they purchased the de-controlled sugar. I would like the Minister to say yes or no to that.

I shall now come to another performance of this Department, *i.e.* deep sea fishing. The people in West Bengal consume mostly fish. What have they done about that? We have 85 kilometres of sea-front. I had a talk with the Director of the Norwegian Plot Protect which came to this country. He took me aside and told me : "I had an impression that we were going to your State. But, we had a telegram asking us not to proceed and we don't know why it was done." I would tell you what the Estimates Committee has said about the performance of Mr. Shinde's Department and what they have done in regard to West Bengal. I quote from Page 10 of the Fortieth Report of the Estimates Committee, 1967-68.

> "The Committee are unhappy to note the way in which the development of fisheries in the Bay of Bengal has been handled. It appears that initially no proper survey was made about the fishers in the Bay of Bengal and the deep sea fishing operations undertaken by the Government, etc. etc."

The Centre has been doing it very deliberately. If I say that they have been neglecting the problems of West Bengal deliberately with an object in mind, will it be wrong ?

I would like to mention here about the assistance from the World Bank in this regard. It is stated :

> "The latest position is that another World Bank mission is now going round Bombay and Madras."

Their Study Teams have reported on Mangalore, Tuticorin and Visakhapatnam. There is no mention of West Bengal at all. Though they were very anxious to help West Bengal, they were not permitted by the Central Government. In Assam the fish costs Rs. 12 to Rs. 18 per kg. How can an ordinary man get protein when it is so costly ? If there had been sufficient deep sea fishing in West Bengal, we would have supplied sufficient quantity of fish to Assam. But the Centre has killed the whole thing.

The Central Fisheries Corporation was set up in December, 1965.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member has to conclude now. Only if he can take some time from the time of unattached members, he can continue,

SHRI JYOTIRMOY BASU : It was stated that the Corporation would endeavour to achieve the break-even position gradually by increasing its turnover at the rate of 10,000 tonnes per annum. This is what a letter from Mr. Shinde's Department to the Fish Department of the Government of West Bengal says. The total daily requirement of fish in Calcutta has been estimated at 258 tonnes, but the effective demand is nearly satisfied if about 167 tonnes of fish arrive in the wholesale markets of Calcutta and Howrah daily. The Corporarion proposed to start with 10,000 tonnes of fish per annum which comes to 23-30 tonnes per day, *i.e.* about 16% of the effective demand. As against this, the Corporation has so far failed to bring not even 2 tons of fish per day. The Corporation could bring only 393 tons of fish during 1965—66.

MR. CHAIRMAN : Yus must conclude now.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Sir, I would like to inform you what the Profit and Loss Account of Shinde's baby show. Net loss in 1965-66 was Rs. 2,08,244 ; in 1966-67 it was Rs. 5,60,714. I feel that *Bharat Ratna* Award must be given to the Minister. In 1966-68 the net loss was Rs. 12,68.063. The total loss at the end of the year 1967-68 amounted to Rs. 20,37,022. They

[Shri Jyotinmoy Basu]

could have reduced the price of fish by reducing the overhead costs. But they had no such mind because the whole Government lives on bureaucrats and it dare not touch them. It sells fish at Rs. 6, Rs. 6.50 and Rs. 7 a kilo as the big traders, profiteers and hoarders do. There is no difference between the two.

Has this Ministry ever approached the Railway Ministry to arrange for refrigerator-vans to bring fish over to Calcutta from places where there is plenty of fish ? Let them please not play politics with fish at least. What they are doing is fishy.

Then I come to co-operatives. What was the growth of co-operatives in West Benagl, Assam and Orissa ? Since the Congress Government's traditional financiers closed their door to it, they fell back on co-operatives.....

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude now. I have given you much more time than the quota.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Do you understand the seriousness of the subject I am talking about ?

MR. CHAIRMAN : I am calling the next speaker now. Please co-operate with the Chair.

SHRI JYOTIRMOY BASU : In co-operatives they invested Rs. 18 lakhs. The profit was Rs. 3,000 in Howrah. The expenditure is Rs. 30,000.

And who is the Vice-Chairman of this organisation ? A sitting Congress MLA !

We have the disgraceful episode of the powerloom industry racket where Congressmen had been thieving in a flock in an organised manner. The Minister should read the report and tell the House what he proposes to do with regard to that.

MR. CHAIRMAN : Shri Aga.

SHRI JYOTIRMOY BASU : One more word.

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat.

16.58 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री अहमद आगा (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री ने दुरुस्त अगराज के लिये रुपये की मांग की हैं और दुरुस्त तरीके पर उसको खर्च भी करती है।

जरई तरक्की कोई जादू मंत्र से नहीं हो सकती। वह धीरे-धीरे होगी और हो रही है। हमने मुल्क में नहरों का जाल बिछाया, किसानों को ट्रैक्टर दिये। इसके कारण आज हमारा फूड प्रोडक्शन करीब 95 मिलियम टन हो चुका है। हमने वेहतर तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल किया, ज्यादा उपज बीज इस्तेकाल कर-बाये, और इन सब चीजों से लाभ उठाया। हमारा टार्गेट या कि 81 मिलियम एकड़ सैराव हो। उसमें से अव तक 35 मिलियन एकड़ सैराव हो चुका है और मजीद हो रहा है। हयने क्रिमकश अदबियात तकसीम किए ताकि फस्लों का बचाव हो। कांग्रेस सरकार ने हवाई स्प्रै इंट्रोड्यूस किया जो बहुत पापुलर हो गया है। 16.89 लाख एकड़ स्प्रे हो चुका है। अभी तक दो फस्लों के तहत 20 फी सदी आबपाश रकबे का आ चुक्रा है। इससे मालूम होगा कि तरक्की की तरफ हम कदम उठा रहे हैं और इस हद तक आगे जा चुके हैं। इसके लिये यह कहा जा सकता है कि हमारी उतनीं तरक्की तो नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये थी, लेकिन तरक्की की जानिब कदस उठाया गया है।

योजनाओं के इब्तदा में जहां हम हम 22,9 करोड़ रु० के जरई कर्जे देते थे, वहां अब 450

करोड़ रु० तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कोआपरेटिव बैंकों की डिपाजिट इंश्योरेंस स्कीम भी चालू की है ताकि लोगों को आसानी से कर्जा मिलता रहे। हमने ऐग्रीकल्चर क्रेडिट कारपोरेशन भी बनाया ताकि जो लोग कोआपरेटिव से रुपया हासिल न कर सकें वह वहां से हासिल कर लें।

इसी सरकार ने मछली पालन के सिलसिले में बहुत अच्छा काम किया है अच्ची खासी तरक्की इसमें हुई है। डेरीज़ और दूध की पैदावार के सिलसिले में भी अच्छा काम हुआ है। 840 प्लांटमुल्क में हैं जिनको यूनिसेफ से और न्यूजीलैंड से इकदाद मिली है। सायल कंजर्वेशन के सिलसिले में 35.6 लाख एकड़ हमने और महफूज़ कर ली है। लैंड सर्वे हमने 12.9 लाख का किया है। प्री इनवैसटमेंट सर्वे तकरीबन तमाम शुमाली हिन्दुस्तान में हमने कर लिया है।

17 hrs.

मैं देख रहा हूं कि इस सबके बावजूद जो छोटा किसान है वह कोई फ़ायदा नहीं उठा सका है। यह कहा जाता है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनिस सहीं है। उसके पास जायदाद नही है, ज़मींन का वह मालिक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या एतराज़ की बात है कि जो उसकी फ्यूचर पैदावार है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको कर्ज़ न दिया जाए? उससे बेहतर और क्या ज़मानत हो सकती है? मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर दुबारा गौर करेंगे और छोटे किसान भी कर्ज से फायदा उठा सकें, इसका इन्तजाम वह करेंगे।

मुझे मालूम है कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ हैं और अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ की वजह से वे ज़मीन काश्त नहीं कर पाते हैं। मिनिस्टर साहब अगर स्टेटिसटिक्स को देखें तो उनको मालूम हो जाएगा कि बहुत सी जो फैलोलैंड है, यह वह लैंड है जो कि इन लोगों की है और इसको वे इस वास्ते काश्त में नहीं ला पाते कि उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है।

हम समझते हैं कि है शमा फरोजां लेकिन
मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है।

एक तरफ तो ये लोग हैं कि जो कि ज़मीन से फायदा नहीं उठा पाते हैं, इनकी ज़मीन वेकार पड़ी हुई है और दूसरी तरफ विरला खेतीबाड़ी की तरफ आ रहे हैं, दूसरे बड़े-बड़े लोग भी खेती की तरफ आ रहे हैं। जो लोग समझते थे कि इंडस्ट्रीज़ में टैक्सेशन ज्यादा है, वे आज इस तरफ आ रहे हैं, वे आज ज़मीन खरीद रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लैंड सिफार्म्ज़ को आप लागू करें और एक रीलिंग मुकर्रर करें। उससे जो ज़मीन बचे उसको आप छोटे किसानों में तकसीम करें ताकि वे लोग अपनी होल्डिंग्ज़ को इकोनोमिक होल्डिंग बना सकें। यह बड़ी अजीब बात है कि छोटे किसानों की तरफ तवज्जह कम दी जा रही है।

मैं देखता हूं कि अकसर कश्मीर को आप भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं मुझे मालूम नहीं है। इरिगेशन एंड पावर के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया था कि काश्मीर को आप ने बिलकुल फरामोश कर दिया है। पिछले बीस साल में कोई भी मेजर या मीडियम प्रोजैक्ट आपने उसको नहीं दिया है। अब आपका खयाल है कि तवी रावी कम्प्लैक्स को आप पूरा करेंगे। उससे एक लाख बीस हज़ार एकड़ ज़मीन सराब होगी। इसी तरह से वहां एग्रिकलचरल क्रेडिट कारपोरेशन का फायदा नहीं हो रहा है। उसको वहां लागू नहीं किया गया है। सारे हिन्दुस्तान में रेग्युलेटिड मार्किट है

[श्री अहमद आगा]

लेकिन काश्मीर में रेग्युलेटिड मार्किट एक्ट नहीं है।

मछली पालन के सिलसिले में वहां कुछ नहीं हुआ है। वहां डेरी नहीं हैं। 84 आपके प्लांट हैं लेकिन काश्मीर को आप बिलकुल भूल गए हैं। सायल कंजर्वेशन के सिलसिले में कोई खास काम नहीं हुआ है। डेढ़ बरस से मैं मिन्नत करता आ रहा हूँ कि प्री-इनवैस्टमेंट सर्वे काश्मीर को शामिल किया जाए। मुझे मालूम है कि किश्तवार को आप इसमें शामिल कर रहे हैं। मुझे एक किसान की बात याद आ रही है। वह एक बार रास्ते चल रहा था। चलते-चलते वह थक गया। वह आराम करने लग गया। उसने खुदा से दूआ मांगी कि वह उसके लिए एक घोड़ी भेज दे। थोड़ी देर में एक पटवारी साहब अपनी घोड़ी पर सवार उधर से गुजरे। उसकी घोड़ी के पीछे-पीछे एक बछड़ा दौड़ा चल रहा था। उस पटवारी ने कहा कि तुम तो बड़े हट्टे कट्टे जवान हो। उसने जवाब दिया कि मैं मेहनत करता हूं, तुम्हारी तरह से बैठा नही रहता हूं। इस पर उस पटवारी ने कहा कि इस बछड़े को उठा लो। उस किसान ने कहा कि मांगी थी घोड़ी चढ़ने को और दी उठाने को। किश्तवार में इसका क्या फायदा। वहां वुड वेस्ट इंडस्ट्री नही हो सकती है। वहां बिजली नहीं है। प्री इनवैस्टमेंट सर्वे आप वैली में करवायें वहां पर बिजली भी है और वुड वेस्ट इंडस्ट्री हो सकती है। वहां लोग भी बेरोजगार हैं। बन्दर नचाने वाला अगर आ जाता है तो दस हजार लोगों की भीड़ वहां जमा हो जाती है। इसलिये कि उनको काम नहीं। तभी तो मुल्क का भला हो सकेगा। मैं कहूंगा कि किश्तवार में प्री इनवैस्टमेंट सर्वे की जरूरत नहीं है। आप वैली में करवायें। काश्मीर में एक जायनरी मिल है। 350 आदमी यहां काम करते हैं। जहां लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हों वहां 350 को काम मिले, इससे क्या हो सकता है। इस वास्ते आपको चाहिए कि आप काश्मीर में ऐसे काम करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

वहां पर एक वूलर झील है जो बहुत बड़ी झील है। वहां पर लोग मछली पकड़ते हैं। सुबह चार बजे सरदियों में वे मछलियां पकड़ने चले जाते हैं एक कुरता पहन कर। उस वक्त हवा नहीं चलती है। अगर हवा हो तो किश्ती डूब जाती है। उनके लिए आप एक दो मैकेनाइज्ड वोट्स का इन्तजाम करें।

गर्मियों में वे मछलियां पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि तब पानी की सतह ऊपर होती है और मछलियां बहुत नीचे चली जाती हैं। इस वास्ते वे सरदियों में ही पकड़ते हैं। इस तरह से मैं समझता हूं कि काश्मीर की तरफ कम तवज्जह दी जा रही है। मैं आशा करता हूं कि उसकी तरफ ज्यादा तवज्जह दी जाएगी।

एक शेर मैं तकरीर खत्म करता हूं

हर चारागाह को चारागिरी से गुरेज था,
वर्ना दुख थे बहुत, ला दवा न थे।

नुस्खा मौजूद है, सिर्फ दवाई देने की बात है।

[شری احمد آغا (بارامولا)]

ادھیکش مہودے۔ میں اس منسٹری کی مانگوں کا سمرتھن کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس منسٹری نے درست اغراض کے لئے روپے کی مانگ کی ہے اور درست طریقہ پر اس کو خرچ بھی کرتی ہے

زرعی ترقی کوئی جادو منتر سے نہیں ہو سکتی وہ دھیرے دھیرے ہوگی اور ہو رہی ہے۔ ہم نے ملک میں نہروں کا جال بچھا دیا۔ کسانوں کو ٹریکٹر دئے۔ اس کے کارن آج ہمارا فوڈ پروڈکشن قریب ۹۵ ملین ٹن ہو چکا ہے۔ ہم نے بہتر ٹیکنیکی طریقوں کا استعمال کیا۔ زیادہ اُپج بیج استعمال کروائے اور ان سب چیزوں سے لابھ اُٹھایا۔ ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ۸۱ ملین ایکڑ سیراب ہو۔ اس میں سے اب تک ۴۵ ملین ایکڑ سیراب ہو چکا ہے اور مزید ہو رہا ہے ہم نے کرم کش ادویات تقسیم کئے تاکہ فصلوں کا بچاؤ ہو کانگریس سرکار نے ہوائی اسپرے انٹروڈیوس کیا جو بہت پاپولر ہو گیا ہے۔ ۱۶۰۷۹ ایکڑ اسپرے ہو چکا ہے۔ ابھی تک دو فصلوں کے تحت ۲ فی صدی آبپاشی رقبے آ چکا ہے اس سے معلوم ہوگا کہ ترقی کی طرف ہم قدم اُٹھا رہے ہیں اور اس حد تک آگے جا چکے ہیں۔ اس کے لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری اتنی ترقی تو نہیں ہوئی ہے جتنی ترقی چاہئے تھی۔ لیکن ترقی کی جانب قدم اُٹھایا تو گیا ہے۔

یوجناؤں کے ابتدا میں جہاں ہم ۲۲۰۹ کروڑ روپے کے زرعی قرضے دیتے تھے وہاں اب ۲۵۰ کروڑ روپے تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کوآپریٹیو بینکوں کی ڈپوزٹ انشورینس اسکیم بھی چالو کی ہے۔ تاکہ لوگوں کو آسانی سے قرضہ ملتا رہے۔ ہم نے ایگریکلچر کریڈٹ کارپوریشن بھی بنایا تاکہ جو لوگ کوآپریٹیو سے روپیہ حاصل نہ کر سکیں وہ وہاں سے حاصل کریں۔

اس سرکار نے مچھلی پالن کے سلسلے میں بہت کام کیا ہے۔ اچھی خاصی ترقی اس میں ہوئی ہے۔ ڈیریز اور دودھ کی پیداوار کے سلسلے میں اچھا کام ہوا ہے۔ ۴۸ پلانٹ ملک میں ہیں جن کو یونیسیف سے اور نیوزی لینڈ سے امداد ملی ہے۔ سایل کنزرویشن کے سلسلے میں ۴۵۰۶ لاکھ ایکڑ ہم نے اور محفوظ کر لی ہے۔ لینڈ سروے ہم نے ۱۲۰۹ لاکھ کا کیا ہے۔

پری انویسٹمنٹ سروے تقریباً تمام شمالی ہندوستان میں ہم نے کر لیا ہے۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سب کے باوجود جو چھوٹا کسان ہے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی کریڈٹ ورتھی نیس نہیں ہے اس کے پاس جائیداد نہیں ہے۔ زمین کا وہ مالک نہیں ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا اعتراض کی بات ہے کہ جو اس کی فیوچر پیداوار ہے۔ اس کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اس کو قرض نہ دیا جائے۔ اس سے بہتر اور کیا ضمانت ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ منتری مہودے اس پر دوبارہ غور کریں گے تاکہ چھوٹے کسان بھی قرض فائدہ اُٹھا سکیں۔ اس کا انتظام وہ کریں گے۔

مجھے معلوم ہے کہ بہت سے کسان ایسے ہیں جن کے پاس ان اکونومک ہولڈنگز ہیں اور ان اکونومک ہولڈنگز کی وجہ سے وہ زمین کاشت

نہیں کر پاتے ہیں۔ منسٹر صاحب اگر اسٹیٹسٹکس اگر دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ بہت سی جو منسپل لینڈز ہیں تو بیکار پڑی ہوئی لینڈز ہیں۔ یہ وہ لینڈز ہیں جو کہ ان لوگوں کی ہیں اور اس کو وہ اس واسطے کاشت نہیں لا پاتے ہیں کہ اس سے کوئی لابھ نہیں ہو سکتا ہے

ہم سمجھتے تھے کہ ہے شمع فروزاں لیکن
موم کے جسم میں دھاگے کا جگر جلتا ہے

ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو کہ زمین سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ ان کی زمین بیکار پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف برلا کھیتی باڑی کی طرف آ رہے ہیں دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی کھیتی کی طرف آ رہے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ انڈسٹریز میں ٹیکسیشن زیادہ ہے وہ آج اس طرف آ رہے ہیں وہ آج زمین خرید رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لینڈ ریفارمز کو آپ لاگو کریں اور ایک سیلنگ آپ مقرر کریں۔ اس سے جو زمین بچے اس کو آپ چھوٹے کسانوں میں تقسیم کریں۔ تاکہ وہ لوگ اپنی ہولڈنگز کو ایکونومک ہولڈنگز بنا سکیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ چھوٹے کسانوں کی طرف توجہ کم دی جا رہی ہے۔

میں دیکھتا ہوں اکثر کشمیر کو آپ بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے اریگیشن اینڈ پاور کے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ کشمیر کو آپ نے بالکل فراموش کر دیا ہے۔ پچھلے ۲۰ سال میں کوئی بھی میجر یا میڈیم پراجیکٹ آپ نے اس کو نہیں دیا ہے۔ اب آپ کا خیال ہے کہ توی وادی کمپلیکس کو آپ پورا کریں گے اس سے ایک لاکھ بیس ہزار ایکڑ زمین سیراب ہوگی اس طرح وہاں ایگریکلچر کریڈٹ کارپوریشن کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو وہاں لاگو نہیں کیا گیا ہے۔ سارے ہندوستان میں ریگولیٹڈ مارکیٹس ہے۔ لیکن کشمیر میں ریگولیٹڈ مارکیٹ ایکٹ نہیں ہے۔

مچھلی پالن کے سلسلے میں وہاں کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہاں ڈیری نہیں ہے۔ ۴۸ آپ کے پلانٹ ہیں۔ لیکن کشمیر کو آپ بالکل بھول گئے ہیں۔ سائل کنزرویشن کے سلسلے میں کوئی خاص کام نہیں ہوا ہے۔ ڈیڑھ برس سے میں منت کرتا آ رہا ہوں کہ پری انوسٹمنٹ سروے میں کشمیر کو شامل کیا جاوے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کشتوار کو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں۔ مجھے کسان کی بات یاد آ رہی ہے۔ وہ ایک بار راستے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا۔ وہ آرام کرنے لگا۔ اس نے خدا سے دعا مانگی کہ وہ اس کے لئے ایک گھوڑی بھیج دے۔ تھوڑی دیر میں ایک پٹواری صاحب اپنی گھوڑی پر سوار ادھر سے گزرے ان کی گھوڑی کے پیچھے پیچھے ایک بچھڑا دوڑا چل رہا تھا۔ اس پٹواری نے کہا تم تو بڑے ہٹے کٹے جوان ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں محنت کرتا ہوں۔ تمہاری طرح سے بیٹھا نہیں رہتا ہوں اس پر اس پٹواری نے کہا کہ اس بچھڑے کو اٹھا لو اس کسان نے کہا کہ مانگی تھی گھوڑی چڑھنے کو اور دی اٹھانے کو۔ کشتوار میں اس کا کیا فائدہ۔ وہاں روڈ بیسڈ انڈسٹری نہیں ہو سکتی ہے۔ وہاں بجلی نہیں ہے۔ پری انوسٹمنٹ سروے آپ دہلی میں کرا لیجئے وہاں پر بجلی بھی ہے اور روڈ بیسڈ انڈسٹری ہو سکتی ہے۔ وہاں لوگ بھی بے روزگار ہیں بندر نچانے والا اگر آ جاتا ہے تو دس ہزار لوگوں کی بھیڑ وہاں جمع ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ ان کو کام نہیں تب ہی تو ملک کا بھلا ہو سکے گا۔ میں کہوں گا کہ کشتوار میں پری انوسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے

آپ دہلی میں کرائیے۔ کشمیر میں ایک جا یتری مل ہے۔ تین سو پچاس آدمی وہاں کام کرتے ہیں۔ جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیروزگار ہوں وہاں ۳۵۰ کو کام ملے اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ اس واسطے آپ کو چاہیے کہ آپ کشمیر میں ایسے کام کریں۔ تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے۔

وہاں پر ایک وولو جھیل ہے جو بہت بڑی جھیل ہے۔ وہاں پر لوگ مچھلی پکڑتے ہیں صبح چار بجے سردیوں میں مچھلیاں پکڑنے چلے جاتے ہیں۔ ایک کرتا پہن کر۔ اس وقت ہوا نہیں چلتی ہے اگر ہوا ہو تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ان کے لئے آپ ایک دو میکنائزڈ بوٹس کا انتظام کریں۔ گرمیوں میں وہ مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ کیونکہ تب پانی کی سطح اونچی ہوتی ہے اور مچھلیاں بہت نیچے چلی جاتی ہیں اس واسطے وہ سردیوں میں ہی پکڑتے ہیں اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی طرف کم توجہ دی جا رہی ہے۔ میں آشا کرتا ہوں اس طرف زیادہ توجہ دی جائے گی۔

ایک شعر سے میں تقریر ختم کرتا ہوں

ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا
ورنہ دکھ ہمیں جو تھے بہت لا دوا نہ تھے

نسخہ موجود ہے صرف دوائی دینے کی بات ہے]

श्री गुणानन्द ठाकुर (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन से जोर शोर से खाद्य समस्या पर बहस चल रही है। मैंने सुना है। मुझे ताज्जुब हुआ कि अधिकांश वक्ताओं ने जो बुनियादी सवाल हैं उनको नहीं उठाया। केवल खाद, फर्टिलाइजर बीज, पानी इत्यादि की बात ही की है। हिन्दुस्तान गावों में बसता है। यहां साढ़े पांच लाख गांव हैं। देश की 85 परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों के मामले में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे उस वक्त तक जब तक कि खेती में जो ज़मीन है उस में हम मूल सुधार नहीं लायेंगे। जब तक ज़मीन का बटवारा नहीं होगा, ज़मीन में सुधार नहीं होगा, ज़मीन जो उसको जोतता है उसको नही मिलेगी तब तक वही पुरानी शराब नई बोतलों में भरने वाली बात होगी। उसी कहानी को दोहराया जाएगा। इस देश में पन्द्रह प्रतिशत से अधिक लोगों के पास ज़मीन नहीं है और अगर है भी तो बहुत कम है, एक दो एकड़ जमीन है।

हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पास बसने के लिए घर तक नहीं है, घर बनाने तक के लिए उनके पास ज़मीन नहीं है। ऐसी अवस्था में कैसे पैदावार बढ़ सकती हैं। कैसे मुल्क की उन्नति होगी, कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा। बड़े बड़े पूंजी पति आज गांव की ओर जा रहे हैं, खेती की ओर जा रहे हैं और काले पैसे को सफेद पैसे में परिणत कर रहे हैं। उनकी मांगें बढ रही हैं। उनको ट्रैक्टर चाहियें, अच्छा फर्टिलाइज़र चाहिये। देश का उत्पादन बढ़े इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आप देखें कि स्वतंत्र भारत के नागरिकों को आपने भिखमंगा बना दिया है। यह कांग्रेस राज की सफलता हैं। बीस वर्ष हमें आजादी मिले हो गए हैं और बीस वर्ष के आजाद भारत के नागरिक भिखमंगे कहलाते हैं, इससे बढ़कर और बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है।

मैं समझता हूं कि जब तक जो कानून है उस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, छोटे छोटे किसानों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, गावों तक विकास की योजनायें नहीं जाएगी तब तक देश की खाद्य समस्या यों ही पड़ी रह जाएगी। कहा जाता है कि देश की पैदावार

[श्री गुणानंद ठाकुर]

बढ़ी है । मैं मानता हूं बढ़ी है। लेकिन जब मानसून अच्छा होता है तो पैदावार बढ़ जाती है और जब मानसून खराब होता है तो पैदावार घट जाती है । कृषि और सिंचाई का इस देश में अन्योन्यात्रय सम्बन्ध हैं । कृषि एक विभाग है और सिंचाई दूसरा विभाग है । हमारे देश का आज पहला काम यह था कि हम एक साल तक शहरों में जहां अराम के लिए बिजली दी जाती है, उसको रोक कर खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए गावों में किसान को बिजली देते । दूसरी बात यह है कि आज छोटी छोटी योजनाएं यों ही पड़ी हुई हैं । मैंने कई बार खाद्य मन्त्री लिखा, राज्य के मन्त्रियों को लिखा कि एक छोटी सी योजना को चालू कर दें, सरहास जिला में खरदहा नदी एक है उसकी योजना पूरी कर दें तो लाखों मन अनाज की पैदावार बढ़ सकती है । लेकिन कृषि विभाग एक उपहास का विषय बन कर रह गया है । इस ओर उस ने कोई ध्यान नहीं दिया । देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए आज इस बात की जरूरत है कि लैंड टु दि टिलर, इस नारे को कार्यान्वित किया जाना चाहिए । जोतने वालों को जमीन मिलनी चाहिए । तब जाकर एक बुनियादी परिवर्तन होगा कृषि में एक क्रान्ति होगी और तब देश की कृषि ससस्या सुलझेगी और पैदावार भी बढ़गी ।

आज आप देखिए, किसानों की क्या हालत है ? जो खेती करने वाले किसान हैं, वह सबसे अधिक तबाह है; परेशान हैं। गावों में जो बड़े बड़े जमींदार हैं और मनीलेंडर्स हैं उन लोगों का कर्ज किसानों पर चढ़ा रहता है। जो सरकारी एजेंसीज हैं कर्जा देने की उन के जरीए किसानों को लोन नहीं मिल पाता और इतनी परेशानी होती है, मैं एक साधारण किसान का लडका हूं,मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि किस तरह से सौ पचास रुपये के लिए किसानों को आधे से से अधिक रुपया दफ्तरों में दे देना पड़ता है और फिर वह खाली हाथ लौट कर आते हैं । अगर खेती के संबन्ध में इस तरह सरकार का दृष्टिकोण रहा तो आप सोच सकते हें कि कैसे देश आगे बड़ सकता है। मैं सबसे पिछड़े स्टेट बिहा का रहने बाला हूं बिहार में सैंकड़ें में 95 लोग खेती पर जीबिका चलाते हैं खास करके नार्थ बिहार में। लेकिन आज साधन के अभाव में किसानों की बड़ी ही दयनीय स्थिती हो रही है । आप को आश्चर्य होगा कि जूट की बोवाई का समय हैं लेकिन अभी तक इनका जूट का बीज नहीं पहुँचा है । किसान हाहाकार मचा रहा है । मैं आज के अखबार की खबर बताऊं कि किस तरह वहां हाहाकार मचा हुआ है और बीज अभी तक बहां नहीं पहुंचा है । लास्ट ईयर जूट का उत्पादन हमारे यहां सब से कम हुआ इसलिए कि जूट का वाजिब दाम किसानों को नहीं मिलता क्योंकि सरकार की नीति हमेशा ऐसी रही है मैं शास्त्री जी कीं बात सुन रहा था, जब चुनाव का मौका आता है तो यह बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करते हैं, किसानों को बड़े बड़े आश्वासन देते हैं । लेकिन जब चुनाब समाप्त हो जाते हैं तो फिर दृष्टिकोण बदल जाता है, किसानों के बिपरीत काम किए जाते हैं जिसके चलते जूट और गन्ने को लेकर किसान आज प्रेशान हैं और तबाह ही रहा है । कौआपरेटिव की भी आज वही हालत है । कोआपरेटिव के जरिए जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है । इसलिए आज जरूरत है इस बात की कि सरकार कृषि समस्या कों प्राथमिकता दे । इस पर सरकार को अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए । सबसे पहला काम यह किया जाना चाहिए, देश की पेदावार तब बढ़ेगी जब सरकार भूमि सेना का संगठन करे । आज क्या है ? गांवों में हजारों हजार एकड़ जमीन पड़ी रहती है, बेकार रहती है, नौजवानों में कोई इंसेटिव

नहीं है; आज बेकारी की जो समस्या बढ़ी हुई है, अगर सरकार भूमि सेना तैयार करे तो बेकारी की समस्या भी हफ हो सकती है और पैदावार भी बढ़ सकती है जिसके लिये सुब्रमण्यम कमेटी ने अभी मंजूर किया है, हालांकि हम तो शुरू से चिल्ला रहे हैं कि अगर सरकार भूमि सेना खड़ी करके गांव के लोगों में यह भावना पैदा करे तो मैं समझता हूं आज जो बेकार नौजवान तोड़-फोड़ में लग जाते हैं, उनको संगठित करके प्रवाहित किया जाये तो देश का भविष्य बन सकता है और भूमि सेना के जरिए उत्पादन भी बहुत अधिक बढ़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या आज जो देश के सामने है, खास कर के मेरे जैसे नौजवान को तो भरोसा नहीं हो रहा है कि इस प्रजातांत्रिक तरीके से कोई सुधार हो सकता है ? किसी चोर के खिलाफ कोई अभियोग लगाया जाये तों क्या उसकी जांच हो सकती है, उसको सजा मिल सकती है ? मुझे तो लगता था कि यह लोक सभा देश की सबसे बड़ी सभा है और इसमें अगर किसी सवाल को उठाया जायेगा तो उसका एक अलग महत्व होगा लेकिन आश्चर्य है कि यहां पर भी किसी समस्या को उठाने के बावजूद भी वही नतीजा होता है जो होना चाहिए। खैर, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी परम्परा है कि लोक सभा की मर्यादा को भी खत्म करे और राज्य सभा की मर्यादा को भी। लेकिन मेरे जैसे नौजवान को, इनकी तो निन्दा करने की आदत है। पर एक सवाल हमने उठाया था और कई बार उठाया भारत सेवक समाज का। मैं आपसे बताऊं, भारत सेवक समाज के नाम पर एक बड़ी जमात खड़ी की गई। श्री गुलजारीलाल नन्दा उसके अध्यक्ष बने। बड़े-बड़े साधु महात्माओं को इट्ठा किया गया, जन सहयोग का नया नारा बना। प्लानिंग कमीशन में उस समय कांग्रेस वालों का बड़ा तांता लगा था, पोप पाल से भी पैसा आया था, जन सहयोग के नाम पर काम चलने लगा और आपको जानकर आश्चर्य होगा—एक तो बिहार की सरकार कैसी बनी है में उस सम्बन्ध में क्या कहूं ? एक प्रिविलेज मोशन आया था जो वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री हरिहर सिंह, उनके खिलाफ कि दो हजार रुपया लेकर उन्होंने दल बदला था, खैर उनकी बात को छोड़िए लेकिन ऐसे-ऐसे लोगों की उसमें साजिस रही है, श्री विनोदानन्द झा जिस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो पत्र लिखा था उनके पत्र से पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं और भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री तेज-नारायण झा जो संविद सरकार के राज्य मंत्री थे, उन्होंने एक विवरण रखा था, किस तरह से भारत सेवक समाज में लोगों ने गोल माल किया, यह मैं पढ़ देना चाहता हूं। यह मैं बिहार की चर्चा खास तौर से कहना चाहता हूं क्योंकि सारे देश की चर्चा करूं तो उतना समय नहीं है। मैं थोड़ा सा अंश पढ़कर सुनना चाहता हूं। मैंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ कर पहले सुनाई थी।

> "सरकारी धन के बे-रोकटोक खुल्म-खुल्ला ऐसे दुरुपयोग से सरकार की काफी बदनामी होने लगी। बाध्य होकर नदी घाटी योजना विभाग ने मार्च 1962 में ऐसा निर्णय लिया कि इकाई नायकों को काम नहीं दिया जायगा। उनके बदले भारत सेवक समाज के स्थानीय ज्ञाता को ही काम सौंपा जाय और वे जिससे काम कराना चाहें करावें। नये बोतल में पुराना शराब। इस नई प्रणाली का फल भी वही हुआ था। जो इकाई नायकों के केस में हुआ था। इस मद में भारत सेवक

[श्रीगुणानन्द ठाकुर]

समाज के स्थानीय नेताओं के पास 7,04,052.48 रुपये बाकी हैं और उन से भी कुछ वसूल नहीं हो पाया है।

भारत सेवक समाज के स्थानीय नेताओं ने एक ओर मजेदार मसाला निकाला था। यह इकाई नायकों को प्रतियेक विपत्र का 90 प्रतिशत ही देते थे और 10 प्रतिशत सामुहिक विकास कार्य एवं संगठनात्मक खर्च के नाम पर हड़प लेते थे। सामुदायिक कार्य के नाम पर दस लाख से ऊपर रुपये जमा हुए और इतना ही रुपया संगठनात्मक कार्य के लिए भी भारत सेवक समाज के नेताओं ने निकाल लिया।"

SHRI JAGJIWAN RAM : Sir, the hon. Member is raising something about the Bharat Sewak Samaj. As the House is aware, so far as the money given as grant or the loan to the Bharat Sewak Samaj from the Central Government or by any Ministry is concerned, the entire matter has been referred to a Commission. What he is reading is something about what happened in the Bihar Legislature. If money has been given by the Bihar Government to Bharat Sewak Samaj the Parliament is not competent to discuss it but the Bihar legislature is competent.

MR. SPEAKER : He is only proving that Bharat Sewak Samaj mishandled the funds.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : वह किस नस्ल का है भारत सेवक समाज, यह बता रहे हैं।

श्री जगजीवन राम : वह तो सब तरह की नस्ल को आप पहचानते हैं।

लेकिन यह बात हम कह रहे थे कि यहां भारत सेवक समाज की बात चल रही है तो उसको कमीशन में दे दिया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहां पर क्या हुआ, इनका व्यक्तिगत किसी से द्वेष है तो हर जगह...

श्री गुणानन्द ठाकुर : व्यक्तिगत द्वेष नहीं है।

श्री जगजीवन राम : वह आगे आ रहा है। व्यक्तिगत ही आने को है।

श्री गुणानन्द ठाकुर : नहीं, यह बिल्कुल ग़लत बात आप कह रहे हैं।...(व्यवधान)...

SHRI JAGJIWAN RAM : I would request you, Sir, to see that if any allegation is made here against any body who is not present here to protect himself that should not be permitted.

श्री गुणानन्द ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, चूंकि जगजीवन बाबू कहते हैं कि यह राज्य का मामला है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जांच कमीशन बैठा था उस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन था और बिहार का बजट केन्द्र से पास हुआ था इसी लोक सभा से इस लिए उस समय का रेफ्रेंस आना चाहिए था। मैं थोड़ा सा पढ़ कर समाप्त करता हूं :

'सामुदायिक उन्नति के कार्य के विषय में यह कहा गया कि योजना आयोग से और रुपये प्राप्त करने हैं और यह कह कर श्री ललित नारायण मिश्र ने 2,10,30,00 और अहटन चौधरी ने 6,33,068.00 रु. निकाल लिए। ऐसा कहा जाता है कि इतने ही रुपये योजना आयोग से भी मैचिन्ग ग्रांट

लिए गए किन्तु अध्यक्ष महोदय, वे रुपये क्या हुए इसका कहीं भी कुछ हिसाब नहीं है। जब ये प्रश्न उठाए गए कि भारत सेवक समाज महालेखा-पाल, बिहार से इन रुपयों का आडिट करावे तो श्री ललित नारायन मिश्र ने इसका घोर विरोध किया। इस सम्बन्ध में मैं तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विनोदानन्द झा और स्वामी हरिनारायणानन्द एवं श्री ललित नारायण मिश्र के बीच हुए पत्र-व्यवहार की ओर संकेत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से गड़बड़ मची हुई है, घुटाला चलता है। बाबू जगजीवन राम जी के बारे में मेरे मन में व्यक्तिगत रूप से बड़ा विश्वास था, बाबू जी इस मामले में बड़े निष्ठावान व्यक्ति हैं, लेकिन जब से चीनी के मामले में इन्हों ने 60 : 40 किया हम को बड़ा तज्जुब हुआ। एक गरीब हरि नेता, डा. अम्बेडकर का शिष्य होते हुए, मिल मालिकों के चक्कर पड़ गया .

SHRI JAGJIWAN RAM : Sir, I take serious objection to these remarks. I would not like to be called by the name Harijanneta. I stand here on my own merit.

श्री गुणानन्द ठाकुर : वह राष्ट्रीय नेता हैं...

SHRI JAGJIWAN RAM : I take serious objection to this.

श्री गुणानन्द ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं उनको राष्ट्रीय नेता कहता हूं, लेकिन जब से उन्हों ने चीनी में 60 : 40 चलाया है, देश को बड़ा धक्का लगा है। चार रुपये किलो चीनी जब चाहिए, तुरन्त मिल जायगी, लेकिन डेढ़ रुपया किलो वाली चीनी नहीं मिलती। आप सप्लाई इंस्पेक्टर या बी०डी०ओ० के यहां दरख्वास्त देते देते मर जाइए, चीनी नहीं मिलेगी। इस से देश के लोगों में मेरे जैसे नौजवानों की संख्या बढ़ी है।

अध्यक्ष महोदय, देश की खाद्य समस्या केवल यहां पर बहस करने से हल नहीं होगी। यदि यह सरकार चाहती है, बाबू जगजीवन राम चाहते हैं— वह देश के गरीबों के नुमाइंदे हैं—कि देश की खाद्य समस्या हल हो तो देश के कृषि कानूनों में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए। देश के किसानों को ऋण से मुक्त करना चाहिए। आजादी के बाद से लेकर आज तक, 1858 से उठवाइए और 1947 तक देखिए—किसानों की दशा क्या है, आज किसान कर्ज में कितना फसा हुआ है ? मैं प्रार्थना करता हूं कि किसानों को कर्ज से मुक्त कीजिए। एग्रीकल्चर कमीशन बैठा कर किसानों की समस्याओं को सुलझाइए। देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए खाद्य का स्टेट ट्रेडिन्ग होना चाहिए। बिहार में जब संविद की सरकार थी, जब बाबू कपिल देव सिंह वहां के खाद्य मंत्री थे, जब वहां से खाद्य की मांग होती थी तो हमें कहा जाता जा कि हम ने पांच लाख टन भेजा है, लेकिन पौने दो लाख टन ही पहुंचता था, क्योंकि पी. एल. 480 के माध्यम से पोलिटक्स चलती थी, गैर कांग्रेसी सरकारों को कुचलने की साजिश चलती थी। 20 वर्षों की आजादी के बाद भी आज देश भिकमगा है। उस को आत्म निर्भर बनाने से लिए, उस को भिकमंगा होने से बचाने के लिए, जरूरी है कि आज गांव गांव में भूमि-सेना खड़ी की जाय। बटाईदारी कानून जो बिहार में पास कर के लाईब्रेरी में रखा हुआ है, उसको धरती पर लाया जाय, मैदान में लाया जाय, किसानों को काफी कृषि ऋण दिया जाय, उनको पैदावार बढ़ाने

[श्री गुमानंद ठाकुर]

के लिए इन्सैन्टिव मिले और भूमिहीनों में जमीन का बटवारा हो, तब ही इस देश की खाद्य समस्या सुलझ सकती है। नहीं तो बजट इसी तरह से आयेगा, पास होगा, पी. एल 480 जिंदाबाद करते रहेंगे और उस हथियार को गैर-कांग्रेसी सरकारों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जायगा, देश के भिकमंगापन को दूर करने की चिंता इन को नहीं रहेगी।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chitoor) : Mr Speaker, Sir, I congratulate the Agriculture Ministry, especially Shri Jagjivan Ram and his assistants, Shri Annasahib Shinde and Shri Gurupadaswamy, for the green revolution they have brought in the country. Though food production is in creasing every year, the growth of population is at a much faster rate. Even though the target of production this year is 85.6 million tonnes, we had to import 5.8 million tonnes of foodgrains from foreign countries. This shows that we are still lagging behind in the matter of food production.

17.25 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the chair*]

If really wanted to increase food production, we would have to take some serious steps, give some incentive to farmers and provide some irrigation facilities etc ; otherwise, we would not be competing with the increase in population in the country and we would be importing foodgrains year after year. To avoid this the Government must come forward with some concrete proposals.

In foreign countries they will fix the prices of foodgrains a year before so that the farmer can think which crop to produce which crop to produce which will benefit him and the plan accordingly and produce foodgrains. I our country, even after the foodgrains have come into the market we are not able to fix prices. So far the Goverment has fixed prices for rice and wheat only ; they have not fixed prices for any other commodity. The farmer is kept in the dark if they had fixed the prices, the farmer would have boldly come forward, invested more money and produced more foodgrains. But here the Government has not come forward.

Instead of giving reasonable prices, now the Government is wanting to reduce prices. They were giving some good price all these years. We have produced wheat in large quantities in our country but now the agricultural prices fixation committee--you call it an advisory committee—has recommended to the Government the reduction of price of wheat. This shows that there are no agriculturists or people who know about agriculture in the price fixation committee. If really they are interested in producing more foodgrains in our country, they should wait till 1971 or 1972, till we have achieved self-sufficiency.

If they reduce the prices, what will happen ? Next year the farmers will take to some commercial crop and will not grow wheat and wheat production will be effected.

The argument that they have put forward is a silly argument. They say that the cost of imported wheat is less and so they want to bring down wheat prices to the level of the cost of imported wheat. If they want to fix price according to the cost of imported foodgrains, are they going to give the same price for rise as thay are giving for imported rice? I will ask the Minister whether they are going to do that. Is the Government prepared to do that ? I do not think they will do that. Wherever it is convenient to them they talk about this and wherever it is not convenient to them they do not come forward to do that. This is double standard and this is not good. We cannot have double standards with the farmers. Year after year the farmers in our country are requesting the Government to fix some support price or minimum price for all the foodgrains and oilseeds produced in our country. Except for wheat and rice they have not fixed support prices. I will tell you what is happening in the case of groundnut. Every year when thd farmer gets the produce, prices go down and after the merchant purchases the groundnut prices go up ; the merchant is benefited but not the agriculturist. If they can fix some support price or minimum price for groundnuts, they need not import oil or oilseeds from foreign countries, like soya bean or sunflower oil from Russia or America.

On the one hand we want to be self-sufficient in foodgrains and, on the other hand, we are improrting oilseeds or oil from other country. This is not good in the interest of our country. If you want to be self-sufficient in oil or in oilseeds, we must produce more and if you want to produce more oilseeds in our country, the Government must come forward to fix the support price or the minimum price for the oilseeds.

I have to say one thing regarding sugarcane. I cannot understand why the Government are not following one policy. They have fixed the minimum of about 100 per tonne. This is not the way to fix the price. In Maharashtra, they get about 13 to 14 per cent recovery ; in Andhra Pradesh, in some areas, we get 11 to 11 5 per cent and, in some other p.aces, we get 8 to 9 per cent recovery. If the sucose content is less, the price has to come down. If the sucrose content is more they must be given more price for the sugarcane. The Government must come forward, at least in the coming year, to fix the price according to the sucrose content. The minimum cane price should Rs. 125 per tonne and the price must go up according to the sucrose content. The Government must come forward do this. Some people who are members of cooperative suggar factories are given sugarcane to factories to manufacture sugar and, in some places, where they are not meubers they are manufacturing jagger. Last year, the price was Rs. 160 per quintal. This year, the price has gone down to Rs. 60 or Rs. 65 per quintal. There is so much of difference. The price has gone dawn. I do not know why the Government is not thinking of poor agriculturists. They are not able to help them. They are not even thinking of this. The Government have never thought of this to give help to the farmer in any way, to give jaggery for the manufacture of sugar. They can divert jaggery for the manufacture of sugar. At least, they could have done that by giving some incentive to the factories that the excise duty will be reduced if they manufacture sugar from jaggery. They can reduce the excise duty and encourage the sugar factories. If they do that, the price of jaggery will go up.

Then, year, after year the farmers in our country are requesting the Government to introduce crop insurance.

MR. DEPUTY SPEAKER : The hon. Member may try to conclude now.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I have taken just 5 minutes or so.

MR. DEPUTY SPEAKER : I have to accommodate as many Members as possible I know you are a very vocal Member. I will give you a couple of minutes. There are many others also who want to speak.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I am an agriculturist. I have not spoken so far on any demand.

MR. DEPUTY SPEAKER : I know you are quite vocal. I will give you a few minutes.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Regarding crop insurance and cattle insurance, the farmers are requesting the Government to introduce crop insurance and cattle insurance. But they have not even replied to our demands, to our speeches, that we make. They do not even think of them. They are not coming forward to do anything. Now. Mr. Morarji Desai is coming forward to nationalise general insurance, fire insurance and other insurance, which is already doing well. Why can't the Government come forward to do cattle insurance and crop insurance ? Let Mr. Morarji Desai come forward with a bold step and say, "I am introducing crop insurance and cattle insurance in the country. I am doing it this year. "Let them do it if they are sincere about it. Why snould they go and take over general insurance which is already doing well ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : He is singing a different song along altogether. General insurance must be nationalised.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : That must come second. This must come first. That is my argument.

Regarding agricultural agricultural tax, I am not able to understand their policy.

Our national incom is about Rs. 30,000 crores, out of which about Rs. 14,000 crores

[Shri Chengalrayar Naidu]

are from agriculture and the balance of about Rs. 16,000 crores are from the other sectors, from trade, bussinessmen, factory people and industrialists. Out of the total population of our country, about 80 per cent are agriculturists or agricultural labourers who live in villages and their income is only Rs. 14,000 crores. The balance of 20 per cent of the population live in towns and thier income is about Rs. 16,000 crores. Is it fair to tax 80 per cent of the people who are getting only Rs. 14,000 crores or will it be fair to tax 20 per cent of the population which get Rs. 16,00 crores ? I cannot understand the Government's policy. I can say that the Finance Ministry has become out-dated ; they are not fit to live in this world ; they should have been in the world about 20 or 30 years ago. Both the Finance Minister and the Finance Ministry have become out-dated. They are there only for the rich people and not for the poor people. In order to give tax-holiday to the extent of Rs. 100 crores to the industrialists, in order to give benefit to 20 per cent of the people, he wants to tax 80 per cent of the people and has, therefore, introduced this wealth tax on agriculturists. Is it fair ? Mr. Morarji Desai has said that he will rope in the big business people who are having lands. This is not correct. We know how wealth tax is collected. The big business people have purchased lands in the name of their industries. The Income-tax Department collects wealth tax on the share capital of the factory. If the share capital is Rs. 10 lakhs, they collect wealth tax only on those Rs. 10 lakhs. The industry may be having property worth Rs. 1 or 2 crores, but that will not be taxed according to the present calculations. If they are doing this, how can they rope in rich agriculturists ? I cannot understand this. I only plead that the poor people of this country should be properly attended to. The 80 per cent of the people who live in rural areas without any amenities should be properly attended to and should be encouraged. In the interest of self-production, they must not be touched. The other 20 per cent of the people who are living with all amenities, with all help from the Finance Ministry, and who are enjoying everything, must be taxed. The tax holiday of Rs. 100 crores should not be given to the industrialists. Government must collect those Rs. 100 crores from them and these Rs. 40 or 45 crores must be left off.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Since the hon. Member has raised a very pertinent point that the Finance Minister is unsuitable to remain in Government, what is your reaction to that ?

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I said 'outdated' ; I said about outdated policies.

श्री मीठा लाल मीना (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि स्वतन्त्रता के 20, 22 साल के बाद भी हमारी सरकार प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़ और सूखे की स्थिति के ऊपर अभी तक किसी भी तरह अपना अधिकार नहीं पा सकी है। इस समय अगर देश को अपनी खाद्य समस्या सुलझानी है तो उसके लिए जैसा कि कुछ मेरे साथियों ने कहा था, किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाए। जब तक आप किसानों के ऊपर ध्यान नहीं देगें तब तक खाद्य समस्या हल नहीं होगी।

किसानों के लिए तीन चीजों की मुख्यतया जरूरत होती है। वे हैं खाद, पानी और अच्छे बीज। सरकार अच्छे बीज देती है लेकिन वे समय से नहीं देती। ऊपर से तो अच्छे बीज चले जाते हैं लेकिन किसानों तक पहुंचते-पहुंचते समय निकल जाता है। पानी के बारे में सरकार आज छोटी सिंचाई योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि वह छोटी सिंचाई योजनाओं पर भी ध्यान दे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा कुए तथा तालाब आदि खोदने में सहायता दे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान के उत्तरी भाग में अकाल का वीभत्स दृश्य हो रहा है। उसके अलावा जिला सवाई माधोपुर क जयपुर का इलाका भी अकाल से पीड़ित है। वहां के किसान अपने खेतों में नलकूप आदि खुदवाना चाहते है और उन

नलकूपों को खुदवाने के लिए सारे का सारा खर्च वह किसान देने के लिए तैयार है। केवल सरकार वहां पर रिंग मशीन भेज दे। उससे पहले सरकार वहां सफल परीक्षण कर दे तो सारे के सारे किसान नलकूपों के खोदने के खर्च को वर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। मैं खुद तैयार हूं अपने खेत में नलकूप खुदवाने के लिए। पर मैं चाहूंगा कि सरकार पहले सफल परीक्षण तो कर ले। उसे खुद विश्वास नहीं है कि सरकार का परीक्षण वहां सफल हो जाएगा। कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से भी सवाई माधोपुर जिले की नादौली तहसील में वहां रिंग मशीन भी गई। डेढ़-दो साल वहां पड़ी रही और कर्मचारियों का भत्ता बना और फिर बिना काम किये वापस आ गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर इस तरह की रिंग मशीन भेजी जाये। वहां किसान पैसे वाले भी हैं, वे नलकूप खुदवा लेंगे।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाईमाधोपुर में सिंचाई अफ़सरों ने भ्रष्ट तरीके से पानी नहीं दिया जिससे लाखों मन धान का नुकसान हुआ। हमने केन्द्रीय मिनिस्टरों को भी लिखा और उनसे निवेदन किया पर उन आफ़िसरों के खिलाफ़ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं निश्चित रूप से मजबूती के साथ उनके खिलाफ़ आज भी कहना चाहता हूं कि अगर वे दोषी नहीं है तो मैं दण्ड भोगने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसे अफसरों के द्वारा पानी न देने की बात की जांच करनी होगी। अगर ऐसे अफ़सरों के खिलाफ़ कार्यवाही नही की जाती तो यह अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों को सही और सस्ती खाद नहीं मिलती। खाद के लिए कुछ आदमियों को लाइसेंस दिये गये है और लोग उन्हीं पर निर्भर करते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दें तो किसान कहीं से भी खाद ले सकते है। किसान के लिए गोवर की खाद, जिसे देसी खाद कहते है, देने के लिए भी सरकार को कायवाही करनी चाहिए। गांवों में लकड़ी का कोई इंतजाम नहीं। लोग जितना भी गौबर गाय बैलों से मिलता है वह जलाने के काम में लेते है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह किसानों को सस्ती लकड़ी जगंलों आदि से लाकर दें जिससे कि किसान लोग गौबर को न जलायें। इन रासायनिक उर्वरकों के लगातार प्रयोग से खेतों की उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है। किसान को अगर एक साल भी रासायनिक खाद खेत में डालने के लिए न मिले तो उस खेत में कुछ नहीं पैदा होगा। इस तरह से वह खेती नहीं कर सकता। अतः मैरा निवेदन है कि खाद वगैरह सस्ती और सही टाइम पर वहां पहुँचाई जाये। इसके अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर दिया जाना चाहिए। बड़े किसानों को ऋण, जमीन, ट्रैक्टर आदि के लिए देते है लेकिन छोटे किसानों को भी ऋण देना चाहिए। किसानों के लिए यह जो लगान होता है यह बिलकुल माफ़ होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने पहले यह कहा था कि लगान माफ़ कर रहे हैं, लेकिन हुआ यह कि एक साल बाद ही उस लगान को दुगना कर दिया और सौ रुपये पर 100 रुपए सरचार्ज बढ़ा दिया गया; जितनी भी खेती है, जो औद्योगिक पैदावार है, उन सब पर राजस्थान में टैक्स लगता। इधर खाद पर और मोटर पंपों आदि पर टैक्स लगा दिया है। इससे किसान हतोत्साहित हो गये हैं और समझने लगे हैं कि सरकार हमारे उपर हावी होना चाहती है। यह जरूर हैं कि किसानों ने उन्नति की है और खेती की काफ़ी उन्नति हुई है। लेकिन सरकार को चाहिए कि किसानों को प्रोत्साहित करें न कि उनको हतोत्साहित करें। मेरा निवेदन है कि वह लगान को समाप्त करें।

[श्री मीठालाल मीना]

आपके पास फूड कारपोरेशन विभाग है, या फूड करप्शन विभाग है। इसको आपको बिलकुल समाप्त कर देना चाहिए। खाद्य निगम ने राजस्थान में जो भ्रष्ट तरीके अपनाये, उसके कई कैसेज आपके पास आये है। इनकी जांच कराइये। अफ़सरों और कर्मचारियों ने मिल-मिलाकर लाखों रुपए खाये हैं। भरतपुर व बांदीकुई के मामले में उन के विरुद्ध जांच भी हो रही है। पर ज्यादा से ज्यादा उनकी पदवृद्धि ही होगी, इसके अलावा उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं होगी।

राजस्थान विधानसभा में खाद्य मंत्री ने कहा कि एक सरकारी अन्न भंडार के स्टोर-कीपर से जब अन्न कम होने के बारे में सवाल किया गया तो उस कर्मचारी ने जवाब दिया कि गेहूं कबूतर खा गये हैं। खाद्य निगम के एक अन्न भंडार से 1000 क्विंटल से भी अधिक गेहूं और 75 क्विंटल मिलो कम पाया गया है। इस का मतलब यह हुआ कि कबूतर 1075 बोरी अनाज खा गए। इस पर आप विश्वास कर लेते हैं। मैं आप को बतलाऊं कि गत साल की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है। खाद्य निगम के अध्यक्ष श्री एन पी सेन के अनुसार 1966-67 में मुनाफ़े का 20 प्रतिशन कर्मचारियों को बोनस दिया गया है तथा बाक़ी बचे हुए मुनाफे का भी एक बड़ा भाग कर्मचारियों पर ही खर्च किया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक तरफ़ तो यह खाद्य निगम अंधाधुंध मुनाफा कमाता है फिर भी आख़िर में जवाब मिलता है कि नफ़ा नुकसान क्या रहा ? नफ़ा, नुकसान सब बराबर रहा बल्कि यह कहिये कि नुकसान ही रहा। मेरा निवेदन है कि जहां आप खाद्य निगम में हो रहे भ्रष्टाचार और गड़बड़ी आदि को दूर करें वहां साथ हो साथ आप व्यापारियों पर भी विश्वास करें और उनका भी सहयोग लेने का प्रयत्न करें। सारे के सारे व्यापारी बेईमान हैं ऐसा मान कर आप न चलें। हो सकता है कि कुछ व्यापारी बेईमानी करते हों और मैं कहूंगा कि आप ऐसे बेईमान व्यापारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कीजिए लेकिन एकदम से सारे व्यापारी वर्ग को देईमान मानकर प्रोसीड मत करिए। अगर सरकार व्यापारियों को विश्वास में लेगी और उनसे सहयोग करेगी तो व्यानारियों से भी आपको पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। जैसा मैंने कहा एक. आध व्यापारी जो बेईमानी करे उसे आप दंड दीजिए लेकिन सारे ही व्यापारियों को बेईमान मत समझिए वरना इसका व्यापारियों पर अवांछनीय असर पड़ता है और उनका इस तरह का विभाग बन जाता है कि वह सरकार के साथ सहयोग नहीं करते हैं। आज हालत यह है कि इन इन्स-पेक्टरों और अफसरों के कारण व्यापारी इतने परेशान हो रहे हैं। खाद्य निगम में जिस तरह से व्यापक रूप में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे देखते हुए इस खाद्य निगम को बिलकुल समाप्त कर देना चाहिए।

क्षेत्रीय प्रतिबंध जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक जनता को पूरे तरीके से सस्ते खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे। मन्त्री महोदय द्वारा जो क्षेत्रीय प्रतिवन्ध समाप्त नहीं किये जा रहे हैं वह बड़े अफसरों की स्वार्थपूर्ण साजिश है। वैसे मुझे मालूम है कि स्वयं मंत्री महोदय का जहां तक ताल्लुक है मंत्री महोदय चाहते हैं कि खाद्य क्षेत्र समाप्त हो जांय लेकिन उनके नीचे के सरकारी अफसरान स्वार्थवश वैसा नहीं होने देना चाहते और इसलिए उसके खिलाफ राय देते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उनकी इस राय को न मानें और यह सारे क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटा दें। इससे सरकार को जहां कोई नुकसान नहीं है वहां किसानों को भी लाभ है क्योंकि उन्हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिलेगी और साथ ही उपभोक्ताओं को भी सस्ता गल्ला उपलब्ध हो सकेगा।

राजस्थान की चावल मिलों के बारे में मुझे कहना है कि वहां पर गये साल धान की फसल कम होंने के कारण चावल मिलें बन्द हो रही हैं। धानी न मिलने के कारण मिलें बन्द हैं और हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्रय विक्रय सहकारी संघ जयपुर 6 राइस मिलें नई लगा रहा है। जिसका कोई औचित्य नहीं है। जब-जब राइस मिलमालिकों ने कहा कि आप इस तरीके से यह मिलें क्यों लगा रहे हैं जब कि पहले ही मिलें नहीं चल रही हैं तो उन्होंने कहा कि हमको सेंटर ने पैसा दिया है हमारे पास पैसा पड़ा है; मिल चलें या न चलें हम को तो लगाना ही है। अब यह क्रय विक्रय सहकारी संघ वही है जोकि राजस्थान में गुड़ कांड के लिए जिम्मेदार था। वह राइस मिल वाले कहते हैं कि आप हमारी ही मिलों को बजाय नई लगाने के ले लीजिए। हमारी बन्द रहती हैं उन्हें ले लिया जाय लेकिन सरकार इसके लिए तयार नहीं है।

इसके अलावा राजस्थान में यह चकबन्दी की समस्या है। चकबन्दी सन 1962 में हुई थी। हमारे किसी कानून की खामी रहने के कारण उसको स्थापित कर दिया गया। सन 52 से लेकर सन 69 तक अर्थात इन सात सालों से किसान बर्बाद हो रहे हैं और करोड़ों रुपया उनका मुकदमेबाजी में खर्च हो रहा है। कोई प्राविधान नहीं निकल पाया है जिसके कारण हजारों किसान बर्बाद हो गये।

राजस्थान में पहाड़ों के पास हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है और जिसको कि फौरैस्टर्स कहते हैं वह उनके कब्जे में पड़ी हुई है। वह सारी की सारी जमीन कृषियोग्य है। उसको जल्दी से गवर्नमेंट लेकर किसानों को दे दे तो उस पर बड़ी अच्छी खेती हो सकती है।

इसके अलावा राजस्थान नहर के निर्माण के काम को भी जल्द से पूर्ण कराया जाय। उसमें केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दिये हुए धन का दो तिहाई भाग कर्मचारियों के यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते आदि पर ही खर्च हो जाता है और वह रचनात्मक कार्यो में नहीं लग पाता है। जरूरत इस बात की है कि वह ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक कार्यों में लगे।

मैं बस एक, दो बात और कह कर समाप्त कर दूंगा।

आज जितने भी कृषि कालेज देश में खुलते हैं वह शहरों में ही खुलते हैं। मैं चाहता हूं कृषि कालेज गांव में खुलें ताकि उन किसानों के लड़के, गाँव के निवासियों के लड़के उन में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पा सकें, जो गरीबी के कारण अपने लड़कों को शहरों में नहीं पढ़ा सकते। उनके मार्ग में और भी बहुत सी बाधायें आती हैं। इस लिए ज्यादा ज्यादा कालेज गांवों में खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए।

यू. पी. सरकार ने खंडसारी और चीनी पर से जो सारे प्रतिबन्ध हटा लिये हैं यह बड़ी अच्छी बात है। इस सरकार को भी इसी ढंग नीति अपनानी चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER : I wili requested Hon. Members to be very brief. I would like to accommodate few more. That will be possible only if you confine to 10 minutes or even less.

श्री बाल गोविन्द वर्मा खेरी: उपाध्यक्ष महोदय, इस में कोई दो राय नही हैं और करीब करीब सभी सदस्यों ने कहा है कि भारतवर्ष की उन्नति देहातों की उन्नति पर निर्भर कमती है। भारतवर्ष की अधिकतर आबादी खेती करती है और यदि उनके ऊपर विशेष ब्यान न दिया गया तो देश का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर शहरों की तरक्की को देख कर हम भौंचक्का हो जायं और

[श्री बालगोविन्द वर्मा]

देहातों की अवहेलना करें तो इस से काम चलने वाला नहीं है।

गांवों के जीवन में हमेशा एक साईकिल चला करती है। इस तरह से पांच सालों में एक साल अच्छा होता है, उस के बाद दो साल मध्यम होते हैं :

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, इतना धाराप्रवाह भाषण हो रहा है और सदन में गणपूर्ति नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है···अब कोरम हो गया है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि किसानों के जीवन एक साईकिल चलती है पांच साल की उस में एक साल अच्छा होता हैं, अगले दो साल मध्यम होते हैं और उस के बाद के दो साल खराब होते हैं।

19.53 hrs.

[श्री गाडिलिंगन गौड़ पीठासीन हुए]

इस तरह से किसानों की हालत एक साल सम्भलती है तो अगले दो तीन सालों में वह खराब हो जाती है। परिणाम यह हो रहा है कि उसकी स्थिति बजाय बनने के बिगड़ती जा रही है। हां केवल 1968 का एक साल ऐसा हुआ है जो वाकई बहुत अच्छा हुआ है, जिससे किसानों की हालत कुछ सम्भली है। लेकिन एक साल में किसानों की हालत अच्छी हो जाने से अगर आप यह अन्दाजा लगायें कि किसान बहुत अच्छे हो गये हैं इस काबिल हो गये हैं कि टैक्स दे सकते हैं, तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। यह तो उगते हुए पौधे की भांती पैरों तले मसल देना होगा। इस तपह से हम जो काना करते हैं कि देश में आत्मनिर्भरता आ जाय, वह चीज नहीं हो पायेगी।

फर्टिलाईजर पर टैक्स लगाना बहुत बड़ा अनर्थ है और इस तरह से देश का निर्माण नहीं हो सकता है। बहुत से माननीय सदस्य इस पर काफी कह चुके हैं, इस लिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जहां तक एग्रीकल्चर वैल्ड टैक्स की बात है. जो किसान बहुत दिनों से अपनी खेती करते चले आ रहे हैं उन यह टैक्स लगाना गलत होगा। जो लोग अपने काले धन को सफेद धन बनाना चाहते हैं, उन पर आप जिस प्रकार से चाहें टैक्स लगायें. उस में मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

जहां तक खेती का प्रश्न है, मंहगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिस की वजह से अभी तक जो खेती बैलों और दूसरे जानवरों की मदद से हुंआ करती थी अब उस तरह से करना मुश्किल हो गया है। आज बैलों की एक जोड़ी 2,000 या 2,500 रु० से कम में नहीं आती है, जिन से खेती की जा सके इस लिये अगर हम आज ऐसा सोचें कि खेती बैलों के जरिये ही होती रहेगी, तो यह असम्भव बात है क्योंकि आज स्थिति यह है कि अगर देवी प्रकोप के कारण एक जानवर खत्म हो जाता है तो किसान की कमर टूट जाती है।

आप जानवरों के दम पर खेती करें और उसके बारे में सोचें तो यह गलत कल्पना होगी। किसान ने वैज्ञानिक ढंग से करना शुरू कर दिया है। बस सोचने लग गया है कि उसी पर चल कर देश में आत्मनिर्भरता आ सकती है। वह सोचने लग गया हैं कि

इसके लिये उस को ट्रैक्टर चाहिए । अगर सस्ते दामों पर ट्रैक्टर उस को दिलाने की आप व्यवस्था कर दें तो यह खेती के लिये बहुत अच्छा होगा । जब तक ऐसा नहीं होगा तब यक देश की हालत सुधरने वाली नहीं है ।

हमारे यहां एक अजीब तमाशा है । न मालूम कितने प्रकार के ट्रैक्टर देश में मंगाये गए हैं । चूंकि अनेक प्रकार के ट्रैक्टर हैं इस वास्ते उनके स्पेअर पार्टस मिलना बड़ा मुश्किल हैं । गवर्नमेंट को चाहिये कि एक या दो टाईप्स के ट्रैक्टरों को यहां पर वह प्रोत्साहित करे ताकि आसानी से उन के स्पेअर पार्टस मिल सकें ।

किसानों ने काफी उन्नति करने की कोशिश की है जैसे खास तौर पर मेरा जिला है, लखीमपुर खीरी और पास में पीली भीत है, जहां पर लोगों ने महसूस कर लिया है कि खेती की हमें उन्नति करनी है ताकि देश की हालत ठीक हो । वहां लोगों ने ट्रैक्टर काफी मात्रा में ले लिये हैं । लेकिन उन के स्पेअर पार्टस न मिलने की वजह से उन के ट्रैक्टर बेकार पड़े हुए हैं । पंद्रह, बीस, पच्चीस और चालीस हजार रुपया उन्होंने ट्रैक्टर खरीदने में लगाया है । इतना रुपया लगाने के बावजूद भी अगर उनके ट्रैक्टर इसे तरह से बेकार पड़े रहें तो इस चीज को देख कर दुःख मालूम होता है अगर आप चाहते हैं कि अन्न के मामले में आत्म निर्भर बने तो ऐसे स्थानों पर जहां पर काफी मात्रा में ट्रैक्टर काम में आ रहे हैं, आप को वर्कशाप स्थापित करनी चाहियें और सस्ती कीमत पर उन की रिपेअर का इंतजाम करना चाहिये ।

आप बाहर ट्रैक्टर मंगा रहे हैं, रशियन ट्रैक्टर मंगा रहे हैं, चैकोस्लोवाकियन ट्रैक्टर मंगा रहे हैं । उत्तर प्रदेश में एक एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की स्थापना पांच छः लाख रुपया लगा कर की गई है । मैं समझता हूं कि यह सारा रुपया वेस्ट किया गया है । इस वास्ते में यह कहता हूं कि दस हजार ट्रैक्टर असैम्बल करने की क्षमता है । लेकिन वहां पर इसके आधे ट्रेक्टर्स असैम्बल करने को दिये जाते है और बाकी आधे के लिये हरयाणा के अन्दर एक वर्कशाप खोली गई है और वहां पर जा कर असैम्बल किया जाता है । हरियाणा में आप दूसरी मेक के ट्रैक्टर असैम्बल कर सकते है । ऐसा न कर के उत्तर प्रदेश से लेकर वहां उनको ले जाना, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय है । सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिये । जब इतना पैसा और लेबर वहां लगी हुई है तो उसको यह सारा काम न दे कर दूसरों में बांटना, उसको स्टार्व करना है यह कहां की बुद्धिमत्ता है ।

रशियन ट्रैक्टर जो आ रहे हैं, असैम्बल हो कर ही आ रहे हैं । इनको जहां भेजना हो वहां पोर्ट से सीधा भेजा जा सकता है । हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको सारे देश में वितरण किया जा रहा है । बजाय इसके कि बम्बई से इनको जहां भेजना हो डायरेक्ट भेज दिया जाय ताकि कम कास्ट लगे, खर्चा कम लगे, इनको पहले तंजाब भेजा जाता है और पंजाब से फिर सारे देश में इधर उधर भेजा जाता है । यह कौनसी अक्लमंदी की बात है, यह मैं आप से जानना चाहता हूं । इस पर भी आप को विचार करना चाहिये ।

काश्तकारों की आर मदद करें न कि उन हिम्मत आप तोड़ें । हमको चाहिये कि उनको ईलैक्ट्रिसिटी दें, पावर दें इन पर सबसिडी दें, फर्टिलाइजर उसको सस्ते दामों पर दें, बीज सस्ते दामों पर दें और रहरी पानी सस्ते दामों पर दें । लेकिन ऐसा न कर के

[श्री बाल गोविन्द वर्मा]

हम देख रहे हैं कि हर चीज के दाम बढ़ाये जा रहे हैं। पम्पिंग सैट्स पर आप ड्यूटी लगा रहे हैं। उनको बिजली मिल नहीं रही है। इस ओर आप का ध्यान जाना चाहिए। वास्तव में आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो कृषि मंत्रालय के पास ही इरिगेशन और पावर मिनिस्ट्री भी होनी चाहिये। पावर और इरिगेशन को इससे अलग रख कर हम वह सफलता प्राप्त नहीं कप सकते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं। इरिगेशन और पावर अगर एक ही मंत्री के पास हों और उसके पास जिस के पास एग्रिकल्चर है तो वह फौरन इन के बारे में निर्णय ले सकता है। उसके बजाय अब होता यह है कि दूसरे मिनिस्टर के पास जाना होता है जोकि इंडिपेंडेंट है और वह इन कामों की जो विशेषता है उसको समझ नहीं पाता है और इसका नतीज यह होता है कि उतना काम नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इस ओर भी आप का ध्यान जाना चाहिए।

सराजवादी समाज की रचना की बहुत चर्चा होतीं है। गरीबी को दूर करके हम सब को बराबर लाना चाहते हैं। लेकिन गरीबी जो है वह बढ़ती ही जा रही है। में यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया है। लेकिन जैसे उनकी हालत सुधरती है वैसे मंहगाई भी बढ़ती जाती है और इस कारण से जो उनकी उन्नति हुई है वह मंहगाई के कारण खत्म हो गई है। तो ऐसी हालत में अगर हम किसान को इंसेन्टिव और रेमुनरेटिव प्राइस नही देते तो हमारे देश का कल्याण नहीं होगा। यह कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। पहले जापान में और अमरीका में भी यही काम किया गया है जब वहां पर खाद्य समस्या की परेशानी थी और हमारे यहां भी उसी से कल्याण होगा। बाहर से हम हमेंशा अनाज मंगाते रहें और उस से देश को खिलाते रहें उस से देश का कल्याण नहीं होने वाला है।

18 Hrs.

इस बारे में हमें आज जरूरत इस बात की है कि हम देखें कि हमारे यहां कृषि विकास और कल्टीवेशन कितना बढ़ रहा है और मैं गवर्नमेंट से रिकमेंड करूंगा कि जिस प्रकार हर एक चीज के लिए कमीशन आप नियुक्त करते हैं, इसके लिए भी एक नया कमीशन नियुक्त करना चाहिए जो काश्तकारों की हालत को असेस करे और देखें कि उनकी काश्त पर कितना खर्चा बैठता है, उसको निकाल कर कितना उनको मार्जन बचता है : तभी जाकर कोई एक सही निश्चय पर आ सकते हैं।

इसके बाद में एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां गन्ने की समस्या बहुत तगड़ी है। गन्ने के दाम उचित नहीं मिलते हैं। सरकार के हिसाब से तो दाम ज्यादा दिला रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि काश्तकार का खर्चा इतना बढ़ गया है कि उसका खर्चा निकलना मुश्किल हो रहा है और फिर यही नहीं है कि इनके कहने से जितना दाम यह कहें उतना दाम वह दे दें। यह 40 और 60 का जो बंटवारा हुआ है अब उचित नहीं है। इसलिए इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा क्योंकि काश्तकार की हालत अच्छी नहीं है। हमारे यहां पिछली बार गन्ने का दाम अच्छे मिले। तो लोगों ने काफी गन्ना बोया। लेकिन इस साल आज अप्रैल का महीना चल रहा है और मेरे क्षेत्र का केवल 35 प्रतिशत गन्ना अभी सप्लाई हुआ है। हम कहते थे कि 2 करोड़ 30 लाख मन गन्ना है, मिल वाले कहते थे कि नहीं 1 करोड़ 60 लाख मन गन्ना है और अब जा कर गन्ना इधर उधर भेज रहे हैं जबकि बहुत पहले ही

इसे डाइवर्ट करना चाहिए था। मैं नहीं समझता हूं कि जून जुलाई से पहले वह गन्ना हमारा खत्म होगा।

एक बात और कह कर मैं बैठ जाऊंगा। कोआपरेटिव के ऊपर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। बावजूद इसके कि कोआपरेटिव से जनता का कल्याण हो सकता है लेकिन उस पर से विश्वास जनता का दिन ब दिन कम होता जा रहा है और लोगों को यह विश्वास होने लग गया है कि सरकार ने कोआपेरेटिव इसलिए चलाया है कि उनके भाई भतीजे और दोस्त उससे फायदा उठाएं और उसके बाद चले जांय और यह लोग उस बात को पुष्ट कर देते हैं। किस प्रकार से काम हो रहा है उसकी एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। न्यू देलही कोआपरेटिव बैंक यहां पर दिल्ली में है। उसके अन्दर लोगों ने करीब 3 लाख का गोलमाल किया है। मैंने कई दफा सरकार और कृषि मन्त्रालय से, सहकारिता मंत्रालय से यह रिक्वेस्ट की, बाबू जगजीवनराम जी से कहा कि आप कम से कम इसकी आडिट तो करवा दीजिए। बाबूजी ने पहले तो कह दिया कि ट्रांसफर्ड सबजेक्ट है, मैं क्या कर सकता हूं। इसके बाद मैंने फिर कहा कि यह यूनियन टैरीटरी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको देखिए और कम से कम आडिट तो करवा दीजिए फिर चाहे जो कुछ करिए, लेकिन अभी तक आडिट नहीं हुआ है।

एक मिदट और चाहूंगा केवल एक मिनट···

MR. CHAIRMAN : The hon. Member must sit down. Nothing will go on record now. Mr. Krishna.

SHRI S. M. KRISHNA (Madhya) : Mr. Chairman, there has been, as usual, a mad rush to congratulate the Minister on the green revolution that he has unleashed. Sir, I am afraid that the tall talk of a green revolution in this country is based on an unsound premise. I would also submit that the assertions are a little premature. In the back-drop of the tax proposals that have been placed before the House by the Finance Minister of the country, it boils down to the point that a development-oriented agricultural policy is yet to be evolved in this country. So long as the country is not self-sufficient in food, it does not behove of this honourable House and any Member of this House to congratulate the Minister. I, for one, refuse to congratulate the Minister so long as he presides over a Ministry which looks at foreign countries to satisfy our hunger.

In the short time at my disposal, I would like to concentration on only the Commissioning of new sugar factories in the country and the policy Government are evolving thereto. In 1968-69, about 1·03 lakh tonnes additional capacity was to be installed, which would make for a total of 36 lakh tonne capacity. Once before, the Food Minister made a policy statement to the effect that hereafter applications for starting factories in the various States would be given preference if they came from the co-operative sector. I hope—and it is a fond hepe—that the Government of India continue to stick to the same policy, which under the given circumstances is a sound policy. I would not like the farmers to be put at the mercy of the middlemen and the mill magnates.

When a policy was evolved, it was in keeping with the Industrial Policy Resolution that this House adopted. What was that policy? That policy was first, to check monopolistic trends in our body-economic, and second, to discourage the concentration of economic power in a few hands.

Today, what is happening? I am appalled at the state of affairs. I will just quote one example with which I am directly connected. I reliably understand that the Government of Mysore have in the last few days made a series of recommendations to Central Government pleading that fresh licences to start sugar factories be granted to private entrepreneurs. This, in my humble opinion, is a retrograde step in conflict with the

(Shri S.M. Krishna)

Industrial Policy Resolution adopted by this House and also the policy statement made by the hon. Minister of Food and Agriculture.

There is one particular case in my own constituency of Mandya. We had made an application to start yet another Sugar factory in the co-operative sector. Now I learn on authority that there has been a conspiracy between a set of industrialists who have migrated from Madras, particularly from Coimbatore, who own personal allegiance to a former Food Minister of this country. They have so manoeuvred with the Government of Mysore that this particular co-operative society which had made the application for the issue of a licence to start a sugar. factory has withdrawn its application, and now they have made an application that they may be given the licence to start the sugar factory in the private sector. I submit this does not fit in well with what we have been looking for.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : So far we have not got that information.

I do not know wherefrom he has got that Information.

SHRI S. M. KRISHNA : I got this from the chief promoter of this co-operative society who had made the original application for the grant of a licence to start the sugar factory in the co-operative sector, in which I happen to be one of the promoters. In my absence, they have passed a resolution to the effect that they are not going to press their applications because they have not been able to find the needed resources to put up the factory and the Central Government have not given them any facilities to raise the resources.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : That is a different question. The co-operative society can raise its own resources. I am asking wherefrom he got the information that this co-operative society has yielded place to a private person, as I have no information about it.

MR. CHAIRMAN : If the hon. Member has any information he may pass it on to the hon. Minister.

SHRI S. M. KRISHNA : I am passing on this information and I shall be the happiest if my information is wrong ; I should like to err on this point. I have got very authentic information that the Government of Mysore have recommended that a private party be given a licence to start a sugar factory in Mandya district. I submit that this is contrary to the pronouncements of the Food Minister on earlier occasions. At this rate I am afraid there may not be many co-operative institutions coming forward to set up sugar factories. Basically the co-operative sector institutions would look upon the Central Government for financial arrangements and if the Central Government let them down they would not be able to go into the market to find the necessary resources to set up a sugar factory. They would certainly need Rs. 2-3 crores. This is the only point I wanted to make and I am sure the hon. Ministers who are present here would give this subject the urgent attention it deserves.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH (Parbhani) : The hon. Member who spoke just before me is more likely to be correct because our experience of licensing of sugar factories and the very administration of sugar control and decontrol and sugar policy shows that those policies are guided more by money bags and "sugar-coated" civil servants than others ; they are amendable to moneyed persons rather than to the poor cultivators who sell their ornaments and other means of livelihood in order to raise the capital to form a co-operative sugar factory. Whenever there is a co-operative sugar factory with a request for licence, the constitunalists among our civil servants say : we connot make any distinction between a co-operative and a private individual as under our Constitution all are equal before law and we have to administer law equally. A few miles from the place where a co-operative factory is to be located if a private individual wants to put up a factory and comes with a request, the civil servant immediately say : there is already a licence issued in the same area ; a second licence cannot be issued, I think the Minister of

State for Agriculture who is a pragmatic politician and of agricultural stock has been unable win single handed the war with army of civil servants who claim to be votaries of constitutional law. They forget that under article 14 even our courts uphold that among equals the law shall be equal and equally administered. So, there is no absolute equality, that is, equality in absolute terms, in any part of the world. The Ministry should be hold enough to say that all sugar factories should raise their own capital and organise themselves into co-operative factories for processing sugar so that the cultivators may benefit. They cannot expect the poor and small holders or force them to come to New Delhi on their knees and pray for a scrap of paper called the industrial licence. They yield to monopolies and moneyed persons who often find it easy to walk away with a licence. Our senior Minister of Food and Agriculture is a well-known champion of the down-trodden people and whenever we have any progressive ideas and policies at least in Maharashtra, Gujarat and other southern States we find there is identity of views between him and the progressive politicians of that area. But whenever we, the cultivators, organised ourselves and requested for a licence, he is not able to help us. Is it not a strange irony of fate or fact that in a country where we are toying with the ideas of control and decontrol because of scarcity and the consumers are forced to buy sugar at Rs. 4 a kilo when we could have given them better sugar at less than Rs. 2 a kilo and where mere paper licensing or even installed capacity does not yield results, our civil servants go on with indefinite calculations of targets which are never reached? For the fourth plan which was supposed to have expired by now, they fixed a target of 4½ million tonnes of sugar. Still, they have kept the same target of 4½ million tonnes for the real fourth plan which has actually started just now. With an installed capacity of 3½ million tonnes, it is corner sense that the target should be upgraded and there should be liberal licensing of sugar factories.

I earnestly plead with the Minister of State and the senior Minister to pick up courage on behalf of the poor cultivators, poor farmers and poor landlords of those areas where they have specialised in cultivation of sugarcane with more sugar content, with the best sugar content, if I may say so in all humility, compared to anywhere in the world. If they care for national interest and consumers' interest, if they are for particular areas being developed where particular crops can be best grown, let them come forward come forward and say that anywhere in India, those cultivators who want to have a co-operative sugar factory will not be made to lose their self-confidence and self-respect for a scrap of paper called industrial licence. Let they say boldly that that they will be liberal, that they will not deny a scrap of paper called licence to those who are raising their own money and who do not come to New Delhi begging for money. I am told that sugar plant manufacturing capacity in this country is hardly utilised to the tune of 20 per cent and 80 per cent of it is idle. I am also told that only 25 per cent of the sugar manufacturing capacity is being utilised now. What is the idea in having a target of 4½ million or 3½ million tonnes and starting a couple of factories here and there in such a situations?

Sir, in parliamentary parlance, I am supposed to declare my personal interest before advancing any proposal. I happen to be one of the promoters of co-operative sugar factory in my area. It is my personal interest and it is also the interest of my constituents whose interest I am supposed to voice here. We have applied for a licence for a sugar factory exactly at the time of the commencement of the State of Moharashtra, in 1956. We have waited for 12 years. Our minister comes from the land of Janak and Janaki and we have undergone *Vanvas* for more than 12 years. Let us hope the Minister would be in a position to assure the poor cultivators of the backward area of Marathwada that they would not be made to wait too long—they have already waited long—for an industrial licence.

श्री शिंकरे (पंजिम) : सभापति महोदय, मैं गोआ से आत हूं। गोआ के बारे में हमारे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो कहा है वह आपको शायद मालूम ही होगा। उन्होंने कहा है कि गोआ भारत का एक सुन्दर टुकड़ा है। इनके पिता स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि गोआ के लोग अजीब हैं।

[श्री शिंकरे]

चूंकि हम गोआ के लोग संघ प्रदेश के देने का राज्य मिलने के बाद भी महाराष्ट्र में विलोनीकरण चाहते थे, और अभी भी चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को देखने के बाद आप भी शायद कहेंगे कि गोआ के लोग अजीब हैं, लेकिन बात यह है कि गोआ के लोग अजीब तो नहीं हैं हम लोग भावना प्रधान हैं लेकिन भावना विवश नहीं होते हैं। अलबत्ता गोआ के लोग प्रैक्टिकल हैं। गोआ के लोग साहित्य और कला के प्रेमी हैं लेकिन वह व्यवहार-दक्ष भी होते हैं। वह राष्ट्रीय भी होते हैं। जब सलाहकार समिति में पांचवें इस्पात के कारखाने की चर्चा चली तब सालेम, नैवेली और हौस्पट के बारे में बहुत से लोग क्लेम करते थे कि वह इस्पात का कारखाना बहां दे दें! मिनिस्टर महोदय ने मुझ से पूछा कि क्या आप गोआ के क्लेम के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं? मैंने कहा कि इस पर राष्ट्र कल्याण की दृष्टि से विचार किया जाय। गोआ की खनिज सम्पदा को राष्ट्र के कल्याण के लिए रखा जाय। फौरन एक्सचेन्ज के लिए जो गोआ की खनिज सम्पदायें हैं उनका उपयोग किया जाय।

आप जानते हैं कि गोआ में कम से कम 125 इंच वर्षा होती है और जब इतनी वर्षा वहां होती है तो शायद आपको मालूम होगा कि वहां की कृषि बहुत समृद्ध होगी और कृषि उद्योग जो वहां का है वह बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं यहां हमेशा कहता हूं कि गोंआ के लिए ज्यादा उद्योग धन्धे दिए जायं जिससे एग्रो-इण्डस्ट्रीज़ वहां पर स्थापित हों। गोआ के लोगों ने एक शुगर कारखाने की मांग की है और मैं आज उसकी यहां पर पुनः मांग दुहराना चाहता हूं। शायद इस पर हमारे मंत्री जी यह कहना चाहें कि वहां आवश्यक उतना गन्ना पैदा नहीं होता है। मैं कहूंगा कि पोर्चगीज ज़माने में जबकि वहां कस्टम का मामला था तब भी गोआ में एक चीनी का कारखाना था वह चल नहीं सका था क्योंकि ड्यूटी पे करके वहां की चीनी यहां भारत में आ नहीं सकती थी और आने के बाद यहां के शुगर कारखानों से कम्पीटीशन नहीं कर सकती थी। लेकिन इससे यह सिद्ध हो जाता है कि गोआ में गन्ने का काफी अधिक व अच्छा उत्पादन होता है और उनके लिए शुगर के कारखाने की आवश्यकता है। लेकिन हम तो देखते हैं कि गोआ जैसे प्रदेश के लिए जो हमेशा मांग करता है कि हमें एग्रो इण्डस्ट्रीज़ दे दो, जब वहां के लोग शुगर के कारखाने की मांग करते हैं तो उनके लिए लाइसेन्स नहीं मिलता है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि शुगर के कारखाने के बारे में गोआ की जो मांग है वह सुनी जाय।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि जब शुगर कारखाने की बात आती है तो हमारी सरकार केवल शुगर के ही प्रश्न को अपने ध्यान में रखती है लेकिन मेरे ख़याल में केवल शुगर का ही मामला ध्यान में नहीं है क्योंकि क्यूबा, जावा या फिलिपाइन्स में शुगर को बाई प्रोडक्ट माना जाता है। मोलेसैस का प्रयोग डिस्टिलरीज आदि में होता है जोकि शुगर का बाई प्रोडक्ट है। इसी तरह से बगासैज जैसा रा मैटीरियल न्यूजप्रिंट के लिए होता है। हमारा दृष्टिकोण यही होता है कि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हम ज्यादा कीमत देते हैं, ज्यादा उन्हें महत्व देते हैं। और जो प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कम देते हैं। मेरा कहना है कि गोआ से जो शुगर कारखाने की माँग आती है और अलग-अलग प्रदेशों से जो शुगर कारखाने की मांग आती है वह मानी जाय। न केवल चीनी की दृष्टि से लेकिन

अल्कोहल, न्यूज़प्रिंट, शराब, वगैरह का भी उत्पादन करने की दृष्टि से।

गोआ भारतीय संघ में एक ऐसा राज्य है जिस के कि बारे में कहा जाता है कि वह एक सुन्दर और अजीब प्रदेश है लेकिन भारतीय संघराज्य में ऐसा एक प्रदेश है कि जो सचमुच सुन्दर है, व वहां के लोग भी अजीब हैं। वह अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह क्योंकि वहां पर हमने एक ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटी देखी है, वह कार निकोबार में है। जब मैं वहां गया तो मैंने उस कोआपरेटिव सोसाइट को देखा जिसका कि क़ारोबार एक दम अजीब है। वहां की नारियल और सुपारी का क्रय-विक्रय उस कोआपरेटिव सोसाइटी के मार्फत होता है। वहां पर सुपारी की प्राइस साढ़े 3 रुपये किलो होती है। वह कोआपरेटिव सोसाइटी सुपारी को साढ़े 3 रुपये किलो के भाव से खरीद करती है और वह कलकत्ते के बाज़ार में 11 रुपये किलो के हिसाब से बेंचती है। अगर वहां का मामला इस तरह से चलता रहता है और कोआपरेटिव सोसायटी इस तरह से चलती रहती हैं तो कैसे देश की प्रोग्रेस हो सकती है?

मैं जानता हूं कि इस प्रदेश में किस तरह से कोपरेटिव सोसायटी चलती है। वहां पर जो कोआपरेटिव सोसायटी है उस की वजह से जो क्रय विक्रय होता है आर्केनट का उस का खरीदने वाला एक मोनोपोलिस्ट है। उस का नाम है आकूजी जाघवती। वह उस को खरीदता है साढ़े 3 रु० किलोग्राम के हिसाब से और बेजता है 11 रु० किलोग्राम के हिसाब से कलकत्ते के बाजार में। इस तरह से अगर आप चाहें कि आक्रेनट का प्रोडक्शन बढ़ जाये तो वह कैसे हो सकता है। मैं चाहता हूं कि वहां जो कोआपरेटिव चलती है उस के बारे में एन्क्वायरी हो और उस के बाद कोई डिसीज़न लिया जाय जिस में किस इस तरह की कोआपरेटिव देश में न चले।

श्री मुद्रिका सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, यह सर्वमान्य है कि भारतबर्ष का मेरुदण्ड खेती है और ज्यों-ज्यों खेती में विकास होगा, उतनी ही देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस को केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सभीक्षा ने भी अपनी प्रस्तावना में स्वीकार किया है। लेकिन हमें दुःख है कि एक तरफ कृषि मंत्रालय हरी क्रान्ति करने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है. उस के वैज्ञानिक भी इस में लगे हुए है और बहुत दूर तक हरी क्रान्ति हो भी पाई है, लेकिन दूसरी ओर जब हम यह देखते हैं कि इस हरी क्रान्ति को सफल बनाने के लिए किसानों को जो ज्याद से ज्यादा प्रेरणा मिलनी चाहिये, उस के लिये जो बजट बनाया गया है उस में बहुत बड़ा कर का बोझ फर्टिलाइजर पर, पम्प पर, डीज़ल आयल पर, लगा कर किसानों की प्रेरणा को ससाप्त करने की कोशिश की जा रही है।

ऐसी बात नहीं है कि हरी क्रान्ति जो थोड़ी बहुत हुई है उस से सारे देश के किसानों की हालत सुधर गई है, मैं मानता हूं कि मुट्ठी भर प्रगतिशील किसानों को, खासकर जो बीज पैदा करते हैं, कुछ आर्थिक लाभ जरूर हुआ है, लेकिन सारे किसान समाज को इस तथा-कथित हरी क्रान्ति से कोई बहुत लाभ हो गया है—इतना लाभ कि उन पर कर का बोझ लादने की जरूरत हो—यह बिल्कुल गलत धारणा है, निराधार बात है। ऐसी बात भी नहीं है कि खेती पहले से ही काफी कर का बोझ वहन नहीं कर रही है। उन्हें मालगुजारी देनी पड़ती है। उन्नत बीज जो आज पैदा किया जा रहा है, वह 4-5 रु० किलोग्राम लेते हैं। रसायनिक खाद के लिये जब अमरीका में एक किलोग्राम के लिये 1·5 किलो पैडी देना पड़ता है या जापान में एक किलोग्राम खाद के लिये 1·2 किलोग्राम पैडी देना पड़ता है, तब इस देश में एक किलोग्राम खाद लिये साढ़े 5

किलो चावल हमें खर्च करना पड़ता है।

इसी तरह बिजली को आप देखिये इंडस्ट्रियलिस्ट्स से प्रति यूनिट 3-4 पैसे लिये जाते हैं तो हम किसानों से 16-18 और कहीं-कहीं 20 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है। बिहार में सर्विसिंग चार्जेज 3 रु० फुट है। इस के अलावा वेटरमेंट लेवी है, सिंचाई का रेट है, एलेक्ट्रिसिटी है। इस के अलावा इनडाइरेक्ट टैक्सेज हैं जैसे सेल्स टैक्स है दूसरे टैक्सेज हैं, इन का बोझ भी किसान पर पड़ रहा है।

सब मिलाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां तीन चार सौ रुपयः प्रति एकड़ खर्चा पड़ता था वहां क्रांति के बाद डेढ़ हजार और दो हजार प्रति एकड़ किसान को खर्च करना पड़ रहा है। मालूम नही अर्थ विभाग में कैसे कैसे आला दिमाग के लोग हैं कि उनको मालूम हो रहा है कि किसान के घर में सोना बरस रहा है और उस पर कर लगाये जाने चाहिएं। पम्प्स पर ड्यूटी बीस परसेंट लगा दी गई है। रासायनिक खाद पर दस परसेंट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। दुनिया में इतना दाम किसी किसान को खाद के लिए नहीं देना पड़ता है जितना हमारे यहां देना पड़ता है। आप मिलान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमरीका का गेहूं सस्ता पड़ता है। वहां पर एक किलो खाद देने के लिए यूरिया या नाइट्रोजनस, सिर्फ 1·5 किलो गल्ला, जाहे चावल हो या गेहूं हो, खर्च करना पड़ता है। जबकि हमारे यहां साढ़ पांच किलो पड़ता है। जब यह इतना पहले से ही कीमती है तो फिर और बोझ उस पर लाद दिया जाय यह कहां का न्याय है। समयाभाव के कारण मैं और अधिक इस बारे में नहीं कहना चाहता हूं और कुछ दूसरी जरूरी बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

देश के कई भागों में एग्रिकलचरल यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन दुख की बात है कि बिहार में कोई एग्रिकलचरल यूनिवर्सिटी नहीं है। लुधियाना में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है. उड़ीसा में हैः हर प्रान्त में है लेकिन बिहार में एक भी नहीं है। बरसों से मैं इसकी मांग करता आ रहा हूं। डा० राजेन्द्र प्रसाद इस देश के सर्व प्रथम राष्ट्रपति थे लेकिन उनके नाम पर कोई भी चीज वहां नहीं है। वह भी एक किसान थे। उनके नाम पर वहां एक एग्रिकलचरल यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है लेकिन नहीं बनाई जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि इस ओर सरकार ध्यान देंगी।

क्रापइंश्योरेंस आज तक नहीं हो पाई है; आप जानते हैं कि हमारे देश की खेती गैम्बल इन रेन है। मोटर को इनश्योरेंस आप करते हैं, मोटर बाइक की करते हैं, मकान और दुकान की करते हैं, लेकिन जो पैदा करता है उसकी खेती की इनश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, कैटल जिनकी सहायता से खेती की जाती है, उनकी इनश्योरेंश की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए जब कहा जाता है तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंघती हैं। टैक्स लगाने के लिए ये बड़े उतावले रहते हैं। उसके लिए आप किसी प्रकार की कोई सरटेंटी की व्यवस्था तो करें, कहीं तो ऐसी व्यवस्था करें कि किसान निश्चिन्त होकर बैठ सके। उसकी क्राप की आप इनश्योरेंश करें, उसके कैटल को आप इनश्योरेंश करें, उसको आप इंसेटिव दें ताकि वह अधिक पैदा कर सके। तभी तो हरी क्रांति सफल हो सकती है।

करोड़ों रुपया विदेशों से पाउडर्ड मिल्क मँगाने में खर्च किया जाता है। निरंतर इसकी कोशिश की जाती है कि विदेशों से हमें दूध पाउडर मिले। क्यों नहीं जो देश का पशु धन है, जो कैटल हैं, उनको उन्नत करने की

कोशिश की जाती। वैज्ञानिकों की मदद से सुन्दर चरागाहें बनाई जा सकती हैं यदि हम कोशिश करें तो हम अधिक दूध प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। हमारा देश तो मवेशियों का देश है गौओं का देश रहा है, गो प्रधान देश रहा है फिर भी हम पाउडर मिल्क मंगाने पर फौरन एक्सचेंज खर्च करें और ऐसा करने के लिए फौरन एक्सचेंज निकालने का सवाल उठे, यह हमारे देश के लिए शर्म की बात है। आपको चाहिए कि आप अपने देश के पशु धन को विकसित करें ताकि करोड़ों रुपया जो फारेन एक्सचेंज का हमको दूध पाउडर मंगाने पर खर्च करना पड़ता है वह बच सके।

आप देखें कि हरी क्रान्ति के लिए जितने एग्रीकलचरल इनपुटस की आवश्यकता है उन सबके दाम बहुत ज्यादा हैं और उनमें से बहुत सी चीजें तो यहां उपलब्ध भी नहीं हैं। आप जानते ही हैं कि रासायनिक खाद हमारे देश में एक चौथाई पैदा होती है और 75 परसेंट हमको विदेशों से लानी पड़ती है। हम खाद तक के लिए फैक्ट्री रहीं बना सके हैं। समारा देश कृषि प्रधान देश है इस वास्ते कृषि से एलाइड जितनी इंडस्ट्रीज है उनको हमको प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर हमें पहले जोर देना चाहिए था। हमें चाहिए था कि ट्रैक्टर फार्मेशन करके हमें फौरन एक्सचेंज क्रियेट करते, उससे हम फौरन एक्सचेंज कमाते पर हमने दूसरी तरह की बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को डिवोलेप किया। बुनियादी गलती हम करते आ रहे हैं।

आज ट्रैक्टर्स की मांग है, छोटे ट्रैक्टरर्स की। रशियन ट्रैक्टर यहां बजार में है लेकिन उस के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आप लगाएंगे, उसके लिए छूट देंगे, प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, लेकिन क्या हरी क्रान्ति का स्वप्न देखने वाले इस विभाग को इतनी मोटी बात नहीं मालूम कि हम यहां स्माल ट्रैक्टर्स, छोटे ट्रैक्टर्स के कारखाने खोलें और बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर्स बनाएं। हमें पम्प की कमी है, एलेक्ट्रिक गुडस की कमी है। हम डीप बोरिंग कर के जो को ट्यूबवेल्स बना रहे हैं उस के लिए हमारे पास पम्प नहीं है। 20 फुट नीचे से पानी निकालने के लिए हमारे पस पम्प नहीं। जहां 20 फुट से नीचे गए विदेशों की ओर टकटकी लगाये बैठे हैं। हर ईश्यू में फारेन एक्चेंज का सवाल आता है। जिन इंडस्ट्रीज को डैवलप करना चाहिए जिससे सही माने में हरी क्रान्ति हो, उधर न जाने क्यों ध्यान नहीं जाता। ध्यान भी जाय तो फाइनेंस मिस्टिर का ब्रेक लगेगा। उन के सोचने के अपने कुछ ढंग हैं। मैं उन ढंगों पर अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं मानता हूं कि यह जो कृषि के मन्त्री हैं जगजीवन बाबू या इन के सहयोगी यह बड़े दाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, इन के वैज्ञानिक इस धन्यवाद के पात्र हैं, कि आज बड़े पैसाने पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर के इस देश में कृषि के अन्दर वे क्रान्ति लाना चाहते हैं। लेकिन वही हाल है, वन स्टेप फारवर्ड, टू स्टेप बैकवर्ड। एक ओर सब्सिडी देकर लोगों को रासायनिक खाद इस्तमोल करनेके लिए प्रोत्साहित किए, सब्सिडी देकर ट्यूबवैल के लिये प्रोत्साहित किए और दूसरी ओर ठीक अकाल के बाद, बहुत बढ़े सुखाड़ के बाद बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स लगा रहे हैं फर्टिलाइजर पर ओर पम्पिग सेट्स पर—एकदम आगे चले,दो कदम पीछे खिचे—इसी में यह देश चौपट हुआ है। इसी में यह खेती चौपट हुई है। मैं समझता हूं कृषि मंत्रालय को इस बात के लिए अंगद की तरह पैर रोपना चाहिए कि कोई भी काम अगर सैक्रेटरिएट में बैठे हुए नासमझों की राय से अर्थ मंत्री अपने बजट में कृषि पर कर जोड़ भी दें तो कृषि

[श्री मुद्रिका सिंह]

मंत्रालय को अंगद की तरह पैर रोप कर कहना चाहिए कि इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रान्ति की जरूरत है और हरी क्रान्ति के रास्ते में जो भी रोड़ा अटकाएगा हम उसको बर्दाश्त नही करेंगे। देश को सेल्फ-सपोर्टिंग बनाना है, तो किसानों को ज्यादा पैदा करने के लिये प्रेरणा देना होगा।

SHRI JYOTIRMOY BASU: Everybody is demanding removal of the Finance Minister. I hope, it is going on record.

MR. CHAIRMAN: Everything is recorded.

SHRI Y.A. PRASAD (Machilipatnam): The importance of agriculture to the Indian economy has been amply demonstrated in the past four years. The Annual Report of the Ministry of Food and Agriculture for 1968-69 makes an encouraging reading. The various measures taken to raise agricultural production are described in detail. They engender confidence in the future of this country. They show that a new dynamism is emerging in Indian agriculture and that appropriate steps are being taken to sustain, streng then and spread it all over the country.

I wish to make a few specific suggestions for speeding up agricultural progress. The first is that more attention must be given to such cash crops as cotton, jute, oilseeds and sugarcane. India's population is already estimated to have reached 529 million and it is rising at an annual rate of 13 million net. This vast and expending population has to be clothed and fed. Again, as production of foodgrains increases and farmers' incomes rise, the demand for clothing and other consumer goods as well as fats and sugar will increase. To meet this growth in demand, their production will have to be stepped up. This will be possible only if we grow more of cash crops also. Today there is too much dependence on other countries for the supply of cotton, jute and fats. This must and can be minimised to a great extent by stepping up the production of these crops in the country. Every effort must be made to see that the green revolution spreads to cash crops also.

The storage. movement and marketing of crops are lso equally important and expansion of these facilities must keep pace with the increase in agricultural production. The efforts of the public sector to build godowns and warehouses are commendable, but this sector alone cannot perform the entire task. It is better to encourage the private sector also to construct storage facilities, and sufficient institutional credit must be extended for the construction of silos in rural areas. If adequate and modern storage accommodation is established it will be possible for commercial banks to extend more credit to agriculture. It will also be possible to provide general insurance cover to stocks of agricultural commodities, implements and inputs. There seems to be little realisation of the value and importance of extending general insurance facilities to rural areas.

Another facility which agriculture needs is crop and cattle insurance. It is quite a few years now since the Congress Party pledged itself to provide crop insurance to our farmers. But previous little has been done to redeem that pledge. I would like to suggest here that the Life Insurance Corporation and the Oriental Insurance Company, both being Government institutions, can very well take up the responsibility of crop insurance and give the general insurance to the private sector. Otherwise, in our country, when we need more competition, it is better that the Government start a new venture, that is, to go into crop insurance with their two organisations.

It is gratifying to find that the scheduled commercial banks are making earnest attempts to provide finance for agriculture in a manner that will lead to more production. It was only recently they were fold to take up this function in a big way. Besides, they have not had the experience of, nor the organisation for, farm financing in any worth-while measure. Having regard to these limitations, it is a matter for appreciation that both collectively and individually the commercial banks have started playing a significant role in financing agricultural development. The target of Rs. 40 crores of agricultural finance fixed by the National Credit Council has been hit.

The commercial banks certainly be able to do more for agiculture, if storage, insu-

rance, roads, transport and communication facilities in rural areas are provided and expanded in adequate measure. In any case, without these facilities Indian agriculture cannot be modernised.

The proposed wealth tax on agricultural property, even with the qualification made by the Deputy Prime Minister, namely, that it will not apply to traditional agriculturists, is not a well-thought-out measure. Its enforcement will involve serious administrative problem and provide a fresh source of corruption.

I wonder whether this tax is worth all that trouble. It will, I am afraid, impede industrialisation of rural areas, for the agriculturists who invest a part of their savings in local industries will come within the mischief of wealth tax. Today, there are several agriculturists who are in a position to establish small industries in rural areas by going in partnership with engineering graduates many of whom are unemployed now. The proposed wealth tax will deter them from doing so and compel them to remain only as agriculturists. Why should they be penalised thus for being industrious and enterprising? If the object of wealth tax on agriculture is to prevent tax evasion by those who are having large non-agricultural incomes, must genuine agriculturists who wish to diversify the employment of their savings by going in for industrial investments be subjected to an annual penal tax? To do so would be a most retrograde step. The Finance Minister has promised to exclude genuine agriculturists from this new tax. I hope the definition of 'genuine agriculturists' will be such as to include all those who are primarily agriculturists but have non-agricultural incomes in the form of dividends and interest flowing from their investments in other spheres.

The Government should also create confidence among the farmers that it is taking active steps to step up the supply of fertilisers and other inputs. Mere verbal assurances will not do. There must be convincing evidence of energetic steps for creating the necessary capacity in the country. Viewed thus, the delay in sanctioning the new fertiliser projects such as the one worked out in great detail by the Tatas undermines the confidence of the people. It is to be hoped that the Government will be quick in making up its mind on such projects.

श्री यमुना साद मंडल (समस्तीपुर) सभापति जी, वास्तव में यह बड़े गौरव की बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने विश्व में हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस सम्बन्ध में वास्तव में हमें उन वैज्ञानिकों को दाद देनी है जिन्होंने विश्व के सामने एक नया रिकार्ड रखा है और यह दिखलाया है कि मिरैकिल सीड्स क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी इनका प्रयोग केवल 30 प्रतिशत जमीन पर भी नहीं हो रहा है, 70 प्रतिशत जमीन पर अभी इसका प्रयोग एक दम नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि इस प्रयोग को उस जमीन पर, उन गरीब किसानों तक भी पहुंचाया जाये, ऐसी व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

एक नयी चीज जो भारतीय कृषि के इतिहास में अभी मिली है वह है न्यूक्लिर रिसर्च लेबोरेटरी। इसमें लिखा है :

It is the first research project of importance in our country which involves close collaboration between four major research institutions—the Bhabha Atomic Research Centre, the Indian Veterinary Research Institute, the National Dairy Research Institute and the Indian Agricultural Research Institute.

आई०ए०आर०आई० और आई०सी०ए० आर०, इन संस्थाओं ने हमारे देश में क्रांति लाने में बहुत काफी मदद की है लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है मैन, यानी किसान वह किसान जो काफी सम्पन्न है। काफी सम्पन्न किसान ही इससे फायदा उठा सकते हैं। ये जो आपके दोनों बड़े मन्दिर हैं, जहां पर लोग कृषि के उत्थान को देखने के लिए जाते हैं, कृषि की नवीनतम चीजों को देखने के लिए जाते हैं, उनका एक जाल हमारे देश भर में बिछाया जाना चाहिए। बिहार

[श्री यमुना प्रसाद मण्डल]

के पूसा क्षेत्र से ही उठाकर इसको यहां पर लाया गया है। मेरा निवेदन है कि पूसा, बिहार में एक सर्वांगीण अनुसंधानशाला खोली जाना चाहिए। इसको खोलने की सारी परिस्थितियां वहां पर मौजूद होते हैं। बिहार सरकार वहां पर एक छोटा सा शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रही है। इसलिये मेरा कहना है कि वहां पर इसकी बड़ी जरूरत है। अभी कुछ महीने पीछे बाबू जगजीवन राम जी वहां (ढोली) गए थे, वहां पर ढ़ोली और पूसा में 1200 एकड़ से अधिक उर्वर भूमि जो बिहार सरकार की है, वह उपलब्ध है। मकान वगैरह भी वहां पर अच्छी हालत में मौजूद हैं। सब-स्टेशन के लिए सारी आवश्यकतायें वहां पर मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो जसा मुद्रिक बाबू ने कहा, वहां पर पूसा और ढ़ोयी के बीच में प्र० राजेन्द्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भी साधन मौगूद है। जितने भी क्राइटेरिया हैं वे सारे वहां पर मौजूद हैं। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि राजेन्द्र बाबू के नाम पर वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिर्वसिटी से बिहार की गरीबी को दूर करने का बहुत कुछ उपाय किया जा सकता है। कृषि विज्ञानिकों के प्रति आज सरा देश आभारी है। लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि गरीब लोगों तक भी आप ऊन चीजों को पहुंचायें। इसके लिए लैंड रिफार्म्स की बड़ी आवश्यकता है। अगर भूमि के सुधार नहीं किये जायेंगे, बटाईदारी इसी तरह से जारी रही तो फिर उन्नति नहीं नहीं हो पायेगी। मैंने 1968-69 की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, भूमि सुधार के बारे में उसमें लिखा है कि इसकी अत्यन्त आवश्यक्ता है।

और इस में शीघ्रता की जायगी। अगर 'बाबू जी' के नेतृत्व में छोटे-छोटे लोगों को, पट्टेदारों को, बटाईदारों को, हक नहीं मिला तो यह संघर्ष क्या रूप लेगा भगवान जाने। इसलिये में कहना चाहता हूं कि बहुत बुरा दिन आ सकता है अगर यह प्रौब्लम हल नहीं होगी।

मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां कोसी बहती है और गंगा का क्षेत्र है। गंगा और कोसी के क्षेत्रों में पशुओं का विकास हो सकता है। आई०ए०डी०पी० के साथ-साथ आप ने आई०सी०डी० इन्टेन्सिव कैटिल डैवलपमेंट—शुरू किया है। वहाँ क्रीमरी भी बरौनी में खोली गयी। लेकिन वह कागज़ पर है। उत्तरी बिहार के दरभंगा जिले में, जहां आधे करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, एक डेरी खोली गयी मधेपुर नाम के स्थान पर। लेकिन पांच, सात साल से उस में जंग लग रहा है चूंकि समय समाप्त हो गया इसलिये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री विश्वनाथ पाण्डे (सलेमपुर) : श्रीमान् यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश और सदन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी क्या आत्म निर्भर हो सकता है? मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर यह देश बाबू जगजीवन राम जी के नेतृत्यव में खाद्यान्न में आत्म निर्भर नही हो सका तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि जितने मंत्री पहले हुए उन्होंने कोशिश की कि आत्म निर्भरता हो। उन्होंने कहा कि गमले में अनाज पैदा करो, मुर्गी पालों, सूअर पालो, मांस खाओ, फल खाओ, सबज़ी खाओ। सब कुछ कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस का कारण यह है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि के उत्थान के लिये जिन चार चीजों की जरूरत होती है—सिंचाई, जुताई, बीज और पानी—इन का जब तक समुचित प्रबन्ध नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

देश में कृषि 32 करोड़ एकड़ भूमि में होती

है। जन संख्या बढ़ रही है। एक आदमी के ऊपर एक एकड़ से कम ज़मीन पड़ती है। और सिंचाई के साधन भी 20, 25 फ़ीसदी तक ही दे पाये हैं। जब तक सिंचाई पूरी नहीं देंगे तब तक खेती में आत्म निर्भर नहीं हो सकते। सब काम छोड़ कर खेती के ऊपर ध्यान देना चाहिये। पानी के साधन दें, फ़र्टिलाइज़र किसानों को दें, ऊत्तम बीज दें और किसानों को प्रोत्साहित करें तथा आवश्यक सामान दें जिस से वह आगे बढ़ें।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि ऊत्तर प्रदेश विशाल प्रदेश है। जन संख्या में प्रथम है और क्षेत्रफल में चौथा नम्बर है। लेकिन सिंचाई और खेती के साधनों में सब से पिछड़ा हुआ है। अभी भी लाखों आदमी हैं जो भूजा सतुआ, रक्ष, आम की गुठली, महुआ, और कटहल की गुठली पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पूर्वान्चल के चार जिले हैं जिन में बलिया, देवरिया, जौनपुर और आज़मगढ़ में काफी आबादी है। पटेल आयोग ने सिफारिश की कि सिंचाई के सम्बन्ध में, कृषि के उत्थान के लिये यह काम किया जाय। प्रान्तीय सरकार के मान का नहीं है कि उस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करे। इसलिये मैं चाहूंगा कि केन्दीय सरकार उस की मदद करे। पटेल आयोग ने जो सिपारिशें की उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल में कृषिउत्पादन के लिये उन को सरकार लागू करे।

यह बड़े अफ़सोस की बात है कि बलिया जिले में विल्थरा रोड के पुरब तरफ़ और सिकदन्रपूर के पश्चिम तरफ़ 20 वर्ष के बाद भी एक सरकारी ट्यूब वैल नहीं लगा है। और बलिया तथा देवरिया जिले या तो बाढ़ से या अनावृष्टि से पीड़ित रहते हैं। इसलिये जरूरी हैं कि सूखे से बचने के लिये पानी का इंतजाम किया जाय। कूए पम्पिंग सैट और ट्यूब बैल दिये जायें और बाढ़ नियंत्रण के लिये काम किया जाय जिससे देवरिया और बलिया जिले बच सकें।

यह आवश्यक हैं कि पूर्वान्चल में बलिया जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय हो और देवरिया में पशू चिकित्सा से संबंधित एक विश्वविद्यालय खोला जाय जिससे वहां के लड़के पशू सम्बन्धी औषधियों को सीखे।

इस समय उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर जो भयंकर सूखे से पिड़ित हैं और वहा पर पानी तक नहीं हैं, भोजन नहीं हैं, यहां तक कि पशूओं के चारे का अभाव हैं। प्रान्तीय सरकार कुछ नहीं कर सकती हैं, केन्द्र समुचित नहायता प्रदान करें;

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिनके दूवारा उन्नति हो सकती हैं। एक तो खाद्यान का जोन सिस्टम हैं यह समाप्त कर दिया जाय। खाद्य निगम व्यापार की स्थापना की जाय। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादन की योजना बनायी जाय और उस पर युद्ध स्तर पर कार्य आरम्भ करें। एक समय निश्चित किया जाय जिस के बाद बाहर से अन्न नहीं मंगायेगें। प्रत्येक खेत को पानी दिया जाय प्रत्येक घर को बिजली दें, मुनाफ़ाखोरी को रोकें, संचयजोरी को रोकें, अलाभकर जोतों का लगान माफ़ करें, करोड़ों खेतीहर मजदूरों की रक्षा की जाय किटाणु नाशक औषधियों का प्रयोग करें। फसलों का बीमा करें, पशुओं का बीमा करें, पशुओं की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करें, पशुओं को बढ़ावें और गोवध को बंद करें। गोबर की खाद का उपयोग किया जाय और

[श्री यमुना प्रसाद मण्डल]

उस की भी समुचित व्यवस्था करें।

[श्री यमुना प्रसाद मण्डल]

गन्ने की कीमत के बारे में केवल एक शब्द कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। गन्ने की कीमत जगजीवन बाबू ने 2 रुपये 75 पैसे प्रति मन रक्खी है जबकि आज सूखी लकड़ी 8 रुपये मन बिक रही है। जब किसान गन्ने का उत्पादन बड़ी मेहनत से और खून पसीना एक करके करता है। जाड़े में और बरसात में वह कठिन श्रम करके गन्ने की खेती करता है। उत्तरप्रदेश और बिहार में बहुत से किसानों का काफी रुपया मिल मालिकों के यहां जो बकाया पड़ा हुआ है उसे यह दिला दें।

SHRI BHAJIBHAI PARMAR (Dohad HAD) : I rise to support the Demads for Grants of the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation.

I would first like to draw the attention of the Minister to the estimates of the production of foodgrains during 1966-67, 1667-68 and 1968-69 in the State of Gujarat which are 21 9, 32·8 and 19·0 lakh tones respectively. Looking to the production of foodgrains in the State of Gujarat and estimating the requirement of foodgrains on the basis of 16 oz. of cereals and 3 oz. of pulses for human consumption for the adult population (88 per cent) of the State and 10 per cent of the normal production for requirement of seeds and wastage. the estimate is 46.2 lakh tonnes, comprising 39.2 lakh tonnes of cereals (36.6 lakh tonnes for consumption plus 2.6 lakh tonnes for seeds) and 7 lakh tonnes of pulses (6.8 lakh tonnes for consumption plus 0.2 lakh tonnes for seeds). Thus the total deficit of the State of Gujarat will be to the extent of 27.2 lakh tonnes of foodgrains.

The allotment made by the Government of India during the year 1967-68 (Nov. to Oct.) and 1968-69 (Nov. to Dec.) and supplies made against it are 5.02, 993 tonnes and 63,400 tonnes and 4,08,539 tonnes and 57,458 tonnes respectively. Thus the supplies made available to the State are much less than what the State normally used to import. These reduced supplies place the State in the very precarious position more so, when due to scarcity conditions in two-thirds of the villages of the State, the demand for cheap grains has much increased. During the current year, there have been some arrivals of khariff coarse grains from other States, but the price levels were much above those of those of milo supplied by the Centre to the States. I therefore request the hon. Minister to enhance the allotment to the State and to make larger supplies to cheap coarse grains to meet the demand from scarcity and backward adivasi areas. I further request and suggest the allotment of at least 50,000 tonnes of milo against the demand of 1·5 lakh tonnes of foodgrains every month as due to scarity conditions in two-thirds of the villages of the State, the demand for cheap grains has much increased.

If the extence of zonal restrictions is to be justifid, the Government of India should make available to the State sufficient quantity for distribution at the same rate as is available to other States like Punjab, Haryana and Delhi which are mixed-cereal consuming areas. In order to enables the State of Gujarat to a slightly liberal quantum of rice to the consumers, at least 20,000 tonnes of rice per month should be allotted to the State.

Now I want to say a few words about daily farming societies for the uplift of the rural people and for providing for a subsidiary means of livelihood particularly for the backward class people. Cows of good breed should be supplied to Adivasi and Harijan agriculturists at half the cost through societies. In order to improve the breed of cows, artificial insemination centres should be opened in at least taluka centres and good types of breed bulls should be supplied to every village panchayat where there are large numbers of cows.

The co-operative credit societies in the villages should be supplied with tractors

which they can cive on hire to agriculturists. Every such society should also be supplied with mobile oil, engine pumping sets in order to give facilities to small farmers having wells for drawing out water from them, as they cannot afford to purchase such sets of pumps for irrigating their land.

The youth of the economically backward communities shonld be given free training in the operation of tractors. More agriculture-bias schools and demonstration centres should be opened in each taluka, looking to the needs of the agriculturists who should be trained in the use of improved seeds, chemical fertilisers and protection of crops by use of insecticides.

19 hrs.

It is noticed that people experience difficulties in the treatment of their cattle in rural areas. Veterinary centres for treating cattle are to be opened after taking into account the number of cattle as people lose their precious cows and buffaloes and bullocks at the time of epidemic diseases for want of proper medicines. Lastly, I suggest that every panchayat should be supplied with first aid medicines for treating the cattle.

The landless persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be granted land so that they can stand on their own legs. It is noticed that the Harijans are sometimes afraid to take lands for agricultural purposes in rural areas due to the high handedness of caste Hindus. The gram sevaks and sevikas who are working in rural areas must take deep interest in their uplift and try to create such atmosphere so that people of different sects can meet and get together for solution of their day to day problems.

Before concluding I should like to offer my best wishes to Babu Jagjivan Ram and his three colleagues for success in their efforts to solve the food problem of the country.

19.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 11, 1969/Chaitra 21, 1891 (Saka)